राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 254

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 20 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

विराट बोले, तीन साल तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलूंगा

>> 14

अयोध्या में तीन साल में बनेगा भव्य राम मंदिर

पहली बैठक ▸ विहिप के मॉडल पर ट्रस्ट की मुहर, अगले माह तय होगा शिलान्यास का मुहूर्त

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में तीन सदस्यों का भी हुआ चयन

- ट्रस्ट के अध्यक्ष बने मणिरामदास जी की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास
- विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय महासचिव, गोविंद देव गिरि कोषाध्यक्ष
- पीएम के करीबी नृपेंद्र मिश्र भवन निर्माण समिति के चेयरमैन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अगले तीन सालों में अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के मॉडल पर ही बनेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में बुधवार को यह निर्णय लिया गया, जिसके बाद मंदिर के मॉडल को लेकर संशय अब खत्म हो गया है। इस मॉडल को राममंदिर आंदोलन की अगुआ विहिप ने करीब 30 साल पहले तैयार कराया था। बैठक में मंदिर के स्वरूप को लेकर फैसला किए जाने के साथ ही 15 सदस्यीय ट्रस्ट के शेष तीन सदस्यों का चयन किया गया और सभी सदस्यों में दायित्वों का बंटवारा भी किया गया। महंत नृत्य गोपाल दास को सदस्य चुनने के साथ ही उन्हें ट्रस्ट के अध्यक्ष-प्रबंधक का दायित्व भी सौंपा गया है।

विहिप के उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और उनके प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई अहम कमेटी भवन निर्माण समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मिश्र उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी हैं।

ढाई घंटे तक चली बैठक : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट की पहली बैठक दिल्ली में ग्रेटर कैलाश स्थित ट्रस्ट के कार्यालय में हुई, जो रामजन्मभूमि मामले की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन का आवास भी है। यह बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई जो तकरीबन ढाई घंटे तक चली।

अयोध्या में खुलेगा ट्रस्ट का बैंक खाता पेज>>6

ट्रस्ट के सदस्य

- वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरन
- महंत नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष
- वासुदेवानंद सरस्वती
- युगपुरुष परमानंद
- विश्व प्रसन्नतीर्थ
- गोविंद देव गिरि, कोषाध्यक्ष
- महंत धीरेंद्र दास
- विमलेंदु मोहन प्रताप मिश्रा, अयोध्या के शाही परिवार के सदस्य
- डॉ. अनिल मिश्र, होम्योपैथिक डॉक्टर
- चंपत राय, महासचिव
- कामेश्वर चौपाल
- ज्ञानेश कुमार, अतिरिक्त सचिव, केंद्रीय गृह विभाग
- अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, उप्र सरकार
- अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी, अयोध्या

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास (दाएं से तीसरे) की अध्यक्षता में बुधवार को ग्रेटर कैलास स्थित कार्यालय में पहली बैठक हुई। प्रेट्र

"राम मंदिर का निर्माण विहिप द्वारा तैयार कराए गए मंदिर के मॉडल के अनुरूप होगा। हालांकि, उसे भव्य बनाने के उद्देश्य से आकार को विस्तार दिया जा सकता है।

–महंत नृत्य गोपालदास, अध्यक्ष, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट

अयोध्या में इस साल अप्रैल में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। अगले तीन सालों में मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।

–गोविंद देव गिरि, कोषाध्यक्ष, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट"

महंत नृत्य गोपालदास : 1963 में बने थे छावनी के महंत

1937 में मथुरा में पैदा हुए महंत नृत्य गोपालदास किशोरावस्था में ही रामनगरी पहुंचे और मणिरामदास जी की छावनी में धूनी रमाई। 1963 में गुरु राममनोहरदास के साकेतवास के बाद उन्हें पीठ का महंत बनाया गया। महंती संभालने के साथ उनकी प्राथमिकताओं में छावनी की बेहतरी के साथ रामजन्मभूमि की मुक्ति का अभियान भी शामिल हुआ। 1984 में जब विहिप ने रामजन्मभूमि के लिए आंदोलन छेड़ा, तो नृत्य गोपालदास उस आंदोलन के अहम किरदार बनकर सामने आए। वर्तमान में वह रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं।

चंपत राय : आंदोलन के जिम्मेदार और संवेदनशील प्रतिनिधि

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के उपाध्यक्ष चंपत राय की गणना अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन के जिम्मेदार और संवेदनशील प्रतिनिधि के रूप में होती है। चंपत राय का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना कस्बे में हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की कार्यपद्धति ने उन्हें आकर्षित किया। वह 1995 में विहिप से जुड़े। राममंदिर के लिए पत्थर तराशी के काम के साथ अदालत में राममंदिर मामले की पैरवी की जिम्मेदारी निभाई।

सरोकार

चीन भेजा जाएगा पंचकूला की महिलाओं का बनाया मास्क

पंचकूला : ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हरियाणा के पंचकूला जिले के गांव बक्शीवाला के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 10 लाख मास्क तैयार कर रही हैं, जिन्हें कोरोना वायरस से लड़ रहे पड़ोसी देश चीन को पहुंचाया जाना है। (पेज-10)

जागरण विशेष

बोल बम के जयकारों से गूंज रही सतपुड़ा की वादी

होशंगाबाद : पचमढ़ी की वादियां इन दिनों बोल बम के जयकारों से गूंज रही हैं। त्रिशूल लिए हजारों श्रद्धालुओं में चौरागढ़ पहाड़ी स्थित शिव मंदिर में पहुंचने की धुन है। मन्नत पूरी होने पर भगवान को दो क्विंटल तक के त्रिशूल अर्पित किए जाते हैं। (पेज-10)

विश्वास.News

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अगवानी के लिए नहीं तोड़े गए ठेले ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 5

शाहीन बाग में पहले दिन अधूरी रही वार्ता, आज फिर पहुंचेंगे मध्यस्थ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन के जाने बाद पहुंचे तीसरे वार्ताकार वजाहत हबीबुल्लाह
- रामचंद्रन ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, जो दुनिया में मिसाल बनेगा

सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बात की। प्रेट्र

दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) विरोधी धरने के कारण बंद रास्ते को खुलवाने के लिए बुधवार को दो वार्ताकार प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन वार्ताकारों में से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े व साधना रामचंद्रन ने मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों के सामने बात न करने की बात कही।

बाद में वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों से बात की। इस दौरान लोगों ने उनसे तीसरे वार्ताकार वजाहत हबीबुल्लाह के साथ न आने को लेकर सवाल पूछे। हालांकि दोनों वार्ताकारों के धरनास्थल से निकलने के कुछ देर बाद ही वजाहत हबीबुल्लाह धरनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। संजय हेगड़े ने मीडिया को बताया कि प्रदर्शनकारियों से अच्छी बात हुई है। गुरुवार को दोबारा बात की जाएगी। साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि मामले में एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा, जो दुनिया में मिसाल बनेगा। हबीबुल्लाह ने प्रदर्शनकारियों से कहा, मैं आपका हमदर्द होने के नाते आपको बात करने के लिए राजी करने के लिए आया हूं। आप पहले से ही बातचीत के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरी जरूरत नहीं है। आप अपनी बात वार्ताकारों से कहें। वह अपनी बात आपसे कहेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे।

67 दिनों से चल रहा प्रदर्शन पेज>>7

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई स्वैच्छिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जरूरी पहल

- कर्जदार किसानों के लिए बीमा लेने की बाध्यता का प्रावधान खत्म
- राज्यों को बीमा कंपनियों से करना होगा कम से कम तीन साल का अनुबंध
- हर सीजन से पहले ही राज्यों को जमा करा देना होगा अपना हिस्सा

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद (बाएं से) कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। प्रेट्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियों को दूर कर उसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस दिशा में सबसे अहम कदम इस योजना को पूरी तरह स्वैच्छिक बनाना है। अब ऋणी किसानों पर फसल बीमा लेने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि योजना की तीन साल की अवधि में सामने आई खामियों को सरकार ने दूर किया है।

किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में तीन साल पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुल खेती की 30 फीसद भूमि पर लागू हो चुकी है। तोमर ने बताया कि योजना में अब तक 13 हजार करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में आए हैं, जबकि मुआवजे के रूप में किसानों को अब तक 60 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बीते तीन वर्षों के दौरान किसानों, सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों से मिले फीडबैक के आधार पर इसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

योजना में किए गए संशोधन से अब यह बीमा योजना पूरी तरह स्वैच्छिक हो गई है। पहले ऋणी किसानों का बीमा अनिवार्य रूप से हो जाता था, जो अब बाध्यकारी नहीं होगा। तोमर ने बताया कि बीमा लेने वाले कुल किसानों में ऋणी किसानों की संख्या 58 फीसद है, जबकि गैर ऋणी किसानों की संख्या 42 फीसद रही है। एक अन्य संशोधन के तहत छोटे व बड़े सभी राज्यों के लिए बीमा कंपनियों के साथ करार करने की अवधि कम से कम तीन साल होगी।

नुकसान के आकलन के लिए क्रॉप कटिंग के बजाय स्मार्ट तकनीक पर जोर पेज>>3

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

संजय कोठारी होंगे सीवीसी बिमल जुल्का बने सीआइसी

नई दिल्ली : राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) होंगे। पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) चुना गया है।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 6

त्राल में भीषण मुठभेड़, तीन कुख्यात आतंकी ढेर

श्रीनगर : सुरक्षाबलों ने बुधवार तड़के दक्षिण कश्मीर के त्राल में हिजबुल के जिला कमांडर और अंसार-गजवात-उल-हिंद के दो अन्य आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मृतकों के पास से हथियार और गोलाबारूद भी बरामद हुआ है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

कारोबारियों को राहत, कोरोना प्राकृतिक आपदा घोषित

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखने का एलान किया। इसके तहत कोरोना की वजह से माल की सप्लाई प्रभावित होने पर कांट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी या उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय ▸ पृष्ठ 13

ब्रिटेन ने किया नई वीजा प्रणाली का एलान

लंदन : ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने बुधवार को नई अंक आधारित वीजा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत सहित विभिन्न देशों के प्रतिभाशाली और सर्वश्रेष्ठ कामगारों को आकर्षित करने के साथ ही सस्ते व कम कुशल श्रमिकों की संख्या में कटौती करना है। नई वीजा प्रणाली एक जनवरी, 2021 से लागू होगी।

पीएनबी घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पूर्व एमडी की संपत्ति जब्ती का आदेश

नई दिल्ली, आइएएनएस : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ उषा अनंत सुब्रमणियन की संपत्तियों को जब्त करने का नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) का आदेश पलट दिया है। एनक्लैट ने नीरव मोदी द्वारा किए गए घोटाले में उषा को एहतियाती कदम नहीं उठाने का जिम्मेदार मानते हुए उनकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं सीएस वैद्यनाथन व मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में उषा का पक्ष रखते हुए कहा, कथित तौर पर घोटाला करने वाली कंपनी से संबंध नहीं रखने वाले व्यक्ति की संपत्ति जब्ती गलत है। कंपनी कानून-2013 में कोर्ट या ट्रिब्यूनल को ऐसे व्यक्ति की संपत्तियां जब्त करने का अधिकार देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। उनकी मुवक्किल को खाते से सिर्फ एक लाख रुपये महीना निकालने की अनुमति है। वह अपनी ही कमाई का इस्तेमाल करने में अक्षम हैं।

जस्टिस आरएफ नरीमन, एस. रवींद्र भट्ट और वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने दलील को सही मानते हुए एनक्लैट के जुलाई, 2019 के फैसले को पलट दिया। एनक्लैट से पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने भी जनवरी, 2019 में उषा की संपत्ति जब्ती का आदेश सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के आदेश को भी रद कर दिया। हालांकि स्पष्ट किया कि इस आदेश से घोटाले की जांच पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल सीबीआइ और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआइओ) इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी मुख्य आरोपित हैं।

हुनर हाट में मोदी ने लिया लिट्टी-चोखे का स्वाद

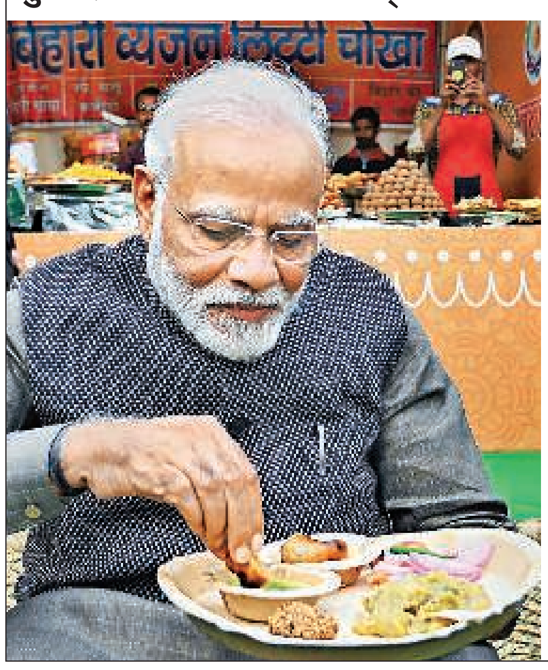

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अचानक राजपथ के लॉन (इंडिया गेट पर) में आयोजित हुनर हाट में पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। वहां उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी-चोखा खाया और कुल्हड़ में चाय पी। उन्होंने इसका भुगतान भी स्वयं किया। 'कौशल को काम' थीम पर आधारित इस हाट को 13 से 23 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। (खबर पेज-3 पर) प्रेट्र

व्यापक एफटीए की तैयारी में भारत और अमेरिका

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के दौरान आगे बढ़ेगी बातचीत
- दोनों देशों के बड़े आर्थिक हितों को ध्यान में रख कर तय होंगी शर्तें

भारत की तीन प्रमुख मांगें

- जीएसपी के तहत मिलने वाली रियायत बहाल की जाए
- भारतीय कृषि व तकनीकी उत्पादों का ज्यादा आयात करे अमेरिका
- भारतीय पेशवरों व कामगारों के लिए अड़चन का रवैया दूर हो

अमेरिका की तीन प्रमुख मांगें

- उसके कृषि व एल्कोहल उत्पादों पर शुल्क घटाई जाए
- ऑटो कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे और खोले जाएं
- ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नियमों को उदार बनाया जाए

इस बात पर असमंजस खत्म हो गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान अगले हफ्ते भारत-अमेरिका के बीच कोई कारोबारी समझौता होगा या नहीं। अब साफ है कि यात्रा के दौरान कोई कारोबारी समझौता नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे वजह यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर बातचीत हो रही है। अगले हफ्ते सप्ताह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच हैदराबाद हाउस में होने वाली आधिकारिक बातचीत में यह बहुत ही अहम मुद्दा रहेगा। दोनो देशों के प्रतिनिधियों के बीच इस बारे में पिछले कई महीनों से बात हो रही है। वैसे, एफटीए वार्ता पर समझौता इस वर्ष अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद नई सरकार के कार्यकाल में ही संभव दिख रहा है।

भारत यात्रा की तैयारियों में जुटे ट्रंप ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनो देशों में फिलहाल कोई कारोबारी समझौता नहीं होने जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि, 'दोनों देश व्यापक एफटीए पर बात कर रहे हैं जिसमें सभी पक्षों के हितों की समान तौर पर रक्षा हो सके। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) रॉबर्ट लाइटहाइजर के बीच कई दौर की बातचीत हुई है।

दोनो पक्षों के बीच यह सहमति है कि छोटे-मोटे ट्रेड समझौते की जगह बड़े समझौते को तरजीह दी जानी चाहिए। इतना तय है कि जो भी होगा वह एकतरफा नहीं होगा। मसलन, अगर अमेरिकी कंपनियों को भारत में पांच अरब डॉलर का बाजार मिलेगा तो अमेरिकी बाजार में भी भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा ही माहौल होना चाहिए। समझौते में दोनो देशों के लंबी अवधि के हितों का ख्याल रखा जाएगा।'

यह पहला मौका है जब दोनो देशों के बीच व्यापक मुक्त व्यापार समझौते को लेकर गंभीरता से बात हो रही है। अभी तक एक-दूसरे को प्रमुख वरीयता वाले कारोबारी राष्ट्र यानी एमएफएन का दर्जा देने पर बात हो रही थी। यह भी बताते चलें कि मोदी सरकार एफटीए को लेकर फूंक-फूंककर कदम उठा रही है।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारी दबाव के बावजूद अमेरिका आसियान देशों और चीन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के साथ होने वाले व्यापार समझौते रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) से अलग हुआ है। उसने अपने सबसे बड़े आर्थिक साझेदार यूरोपीय संघ के दबाव के बावजूद उसके साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू नहीं की है। ऐसे में अमेरिका और भारत के साथ होने वाले एफटीए की अहमियत बढ़ जाती है।

लंबी छलांग

अप्रैल से भारत सबसे स्वच्छ पेट्रो-ईंधन के इस्तेमाल वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण व तकनीकी सुधार की ओर बड़ा कदम, पहली अप्रैल से लागू हो रहा बीएस-6 मानक, सल्फर की मात्रा पांच गुना कम होगी

दुनिया के सबसे स्वच्छ पेट्रोल-डीजल के उपयोग को भारत तैयार

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने दुनिया के सबसे स्वच्छ पेट्रोल-डीजल के उपयोग की पूरी तैयारी कर ली है। आगामी अप्रैल से देश में स्टेज-छह (बीएस-6) मानकों वाला पेट्रोल-डीजल व्यापक तौर पर बिकना शुरू हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी सुधार के क्षेत्र में यह लंबी छलांग है। इसके बाद भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो इस दर्जे का स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएस-6 कार्बन स्तर वाला मानक यूरोपीय देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले यूरो-6 श्रेणी का है।

तकनीकी क्षेत्र में इसे बड़ा सुधार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीएस-4 से सीधा बीएस-6 मानकों का रुख किया गया है। बीएस-6 पेट्रोल-डीजल में सल्फर का हिस्सा पहले से पांच गुना कम होगा। अर्थात बीएस-4 के तहत जो वाहन प्रति किलोग्राम पर 50 मिलीग्राम सल्फर का उत्सर्जन करते थे वह सिर्फ 10 मिलीग्राम सल्फर का उत्सर्जन करेंगे। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण में करने की ओर यह क्रांतिकारी सुधार है।

सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) के चेयरमैन संजीव सिंह ने बताया कि कंपनी की सभी रिफाइनरी में बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल-डीजल का उत्पादन पिछले वर्ष के आखिर से शुरू कर दिया गया है। आइओसी घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होने वाले कुल पेट्रोल-डीजल में आधी हिस्सेदारी रखती है। सिंह ने बताया कि ऑयल कंपनियां नए मानकों के तहत पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति के लिए तैयार हैं। भंडारण क्षेत्रों से यह ईंधन पेट्रोल पंपों को पहुंचाया जा रहा है। हम पहली अप्रैल से बीएस-6 पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति के लिए 100 फीसद तैयार हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

वर्ष 2010 के दौरान देश में बीएस-3 कार्बन उत्सर्जन वाले मानक को अपनाया गया था। इसमें सल्फर की मात्रा 350 पार्ट पर मिलियन (पीपीएम) थी। इसके बाद बीएस-4 पर जाने में सात वर्ष का समय लग गया। इस मानक के पेट्रोल-डीजल में सल्फर का स्तर 50 पीपीएम था। इस बीच बीएस-5 मानकों का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे बीएस-6 पर जाने का फैसला किया गया। यह कई मायनों में अहम है। इससे तमाम खर्चीले तकनीकी सुधारों से निजात मिल गई और दूसरे प्रदूषण से बचाव के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने का अवसर प्राप्त हुआ।

संजीव सिंह ने बताया कि नए ईंधन के इस्तेमाल से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में खासी कमी आएगी। पेट्रोल वाहन के मामले में 25 और डीजल वाहन में 70 परसेंट तक का नाइट्रोजन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी। देश के महानगरों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) हवा में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। नए मानकों के तहत पीएम उत्सर्जन में कमी आएगी। पुराने वाहनों में बीएस-6 ईंधन इस्तेमाल करने से पीएम उत्सर्जन में कमी आएगी।

स्वच्छ ईंधन की ओर देश के कदम

- देश में सबसे पहले वर्ष 1990 में ईंधन सुधार कार्यक्रम अपनाया गया
- कम लेड (सीसा) वाले गैसोलीन ईंधन का प्रयोग वर्ष 1994 में शुरू हुआ
- इसके बाद पहली फरवरी 2000 से अनलेडेड गैसोलीन का इस्तेमाल पूरे देश में शुरू हो गया, इसी वर्ष अप्रैल से बीएस-1 मानक प्रकाश में आए
- वर्ष 2001 तक देश के लगभग सभी महानगरों में बीएस-2 मानक के ईंधन का इस्तेमाल होने लगा। यही वह दौर था जब ईंधन में बेंजीन की मात्रा पांच परसेंट से घटाकर एक परसेंट कर दी गई थी।
- वर्ष 2003 में बीएस-3, वर्ष 2010 में बीएस-4 और वर्ष, 2017 में बीएस-4 मानक लागू हुए

12 और मेट्रो स्टेशनों से मिलेगी ई-रिक्शा की सुविधा। अब ऐसी सुविधा वाले मेट्रो स्टेशनों की संख्या 29 हो गई है। पहले दो किलोमीटर के लिए दस रुपये फिर प्रत्येक एक किमी के लिए पांच रुपये किराया लगेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 फरवरी 2020

काम शुरू ▸ मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में सभी मंत्रियों, विभागाध्यक्षों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक

10 गारंटी को लागू करने के लिए मांगा रोड मैप

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

सत्ता संभालते ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने विकास कार्यों पर तेजी से काम करने की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सभी मंत्रियों, विभागाध्यक्षों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान एक सप्ताह में दस गारंटी कार्ड लागू करने का रोड मैप मांगा है।

एक सप्ताह में प्लान बनने के बाद सभी विभागों के सचिवों व अन्य अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की अलग-अलग बैठक होगी। इसमें एक-एक गारंटी कार्ड पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ विस्तार से चर्चा होगी। इसमें अधिकारियों को खास तौर पर यह निर्देश दिया गया कि एक-एक गारंटी को लागू करने की समय सीमा और बजट के बारे में विस्तार से योजना बनाएं। साथ ही इसमें यह भी शामिल किया जाए कि गारंटी कार्ड को कितने चरण व कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा। गारंटी कार्ड को लागू करने में खर्च होने वाले पैसे को बजट में दिल्ली सरकार शामिल करेगी। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय कुमार देव समेत सभी मंत्री मौजूद थे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले पांच साल में जन उपयोगी काम करने के लिए अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि दोबारा 90 फीसद से ज्यादा सीटों के साथ सरकार की वापसी हुई है। इस कारण जिम्मेदारी भी बहुत है, जिसे अगले पांच साल में सभी को मिलकर पूरा करना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगले पांच साल भी सभी मुफ्त सुविधाएं जारी रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में जितना जबरदस्त तरीके से काम हुआ था, अगले पांच साल में उससे भी ज्यादा तेजी से काम होगा। सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। सिर्फ एक दो मंत्रियों के विभाग में बदलाव हुआ है।

बैठक में सभी 10 गारंटी पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। सभी विभागों के प्रमुखों और सचिवों से शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, बिजली, सुरक्षा, पानी, यातायात, प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी पर चर्चा की गई। विभाग यह प्लान बनाएगा कि उस गारंटी को वह कितने महीने या साल में पूरा करेगा और उसको पूरा करने में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। पहले साल में कितने पैसे लगेंगे और कितने काम पूरे होंगे। दूसरे साल में कितना काम हो जाएगा और कितने पैसे लगेंगे।

ये हैं केजरीवाल की 10 गारंटी

जगमगाती दिल्ली
- सबको 24 घंटे लगातार बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना रहेगी जारी।
- बिजली तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडर ग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली।

हर घर नल का जल
- हर घर 24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा।
- हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना रहेगी जारी।

बेहतर शिक्षा व्यवस्था
- दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था।

सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज
- दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक के जरिए इलाज की समुचित व्यवस्था।

सस्ती शहरी सरकारी यातायात व्यवस्था
- 11 हजार से अधिक बसें और 500 किमी से ज्यादा लंबी मेट्रो लाइनें बिछाना।
- महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा।

प्रदूषण मुक्त दिल्ली
- वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम 3 गुना घटाने का लक्ष्य।
- 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली।
- स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा।

स्वच्छ एवं चमचमाती दिल्ली
- दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ, सुंदर और हरी बनाई जाएगी दिल्ली।

महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली
- सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और बस मार्शल के साथ-साथ मोहल्ला मार्शल की भी होगी तैनाती।

मूलभूत सुविधायुक्त कच्ची कॉलोनियां
- सभी कच्ची कॉलोनियों में होगी सड़क, पीने का पानी, सीवर, मोहल्ला क्लीनिक और सीसीटीवी की सुविधा।

जहां झुग्गी, वहीं मकान
- दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्वक जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान।

कोई विभाग अपने पास नहीं रखने का मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास इस कार्यकाल में कोई भी विभाग नहीं है, जबकि पिछले कार्यकाल में अंतिम के सालों में उनके पास दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी थी, जो इस बार मंत्री सत्येंद्र जैन के पास है। दिल्ली सचिवालय में बुधवार को हुई प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैंने अपने पास कोई विभाग क्यों नहीं रखा? पिछली बार भी मैंने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा था। जल बोर्ड की जिम्मेदारी मैंने बाद में ली थी। इससे सभी मंत्रियों की मॉनिटरिंग करने में ज्यादा आसानी रहती है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम सभी मंत्रियों के काम की लगातार निगरानी करना है। यदि हम किसी विभाग में फंस जाएंगे तो बड़े काम करने में समस्या आएगी। दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस बड़ी जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए ही मैंने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा है।

शाह-केजरीवाल मिलकर काम करने पर सहमत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सौजन्य : ट्विटर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहा शाहीन बाग शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई पहली मुलाकात में चर्चा से गायब रहा। अमित शाह के आवास पर लगभग 20 मिनट चली मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मुलाकात में दिल्ली के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। शाहीन बाग के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने साफ किया कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।

वैसे अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से मुलाकात को 'बहुत ही फलदायी' बताया। उनके अनुसार दोनों नेता दिल्ली के विकास के लिए साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए। इससे साफ है कि दोनों नेताओं ने चुनावी बयानबाजी की कड़वाहट को भूलकर आगे बढ़ने का संकेत दिया है। चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कहा था कि वह दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आशीर्वाद की अपेक्षा भी की थी।

न्यूज गैलरी

स्कूलों में अतिरिक्त कमरे अप्रैल तक हो जाएंगे तैयार

नई दिल्ली : उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली के स्कूलों में 12 हजार से ज्यादा कमरे अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए कमरे आगामी अकादमिक सत्र से एक अप्रैल से छात्रों के लिए खुल जाएंगे। निर्माण में देरी की वजह उन्होंने मई 2019 के लोकसभा के लिए मार्च से आचार संहिता लग जाने को बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी देरी हुई क्योंकि कोर्ट ने अक्टूबर 2019 से दिल्ली में सभी निर्माण पर रोक लगा दी थी, ऐसा गंभीर वायु प्रदूषण की वजह से किया गया था। (जासं)

ऊषा का तबादला, जल्द मिलेगा एएसआइ को नया मुखिया

नई दिल्ली : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की महानिदेशक उषा शर्मा का तबादला हो गया है। अब उन्हें युवा एवं खेल मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। महानिदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने एएसआइ में उत्कृष्ट कार्य किए। एएसआइ संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। एएसआइ का नया महानिदेशक कौन होगा अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन जल्द ही किसी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। ऊषा शर्मा ने लालकिला के संरक्षण कार्य में काफी दिलचस्पी दिखाई और संरक्षण कार्य के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से लालकिले में बहुत काम कराए गए। आजादी के बाद भारतीय सेना के समय बनाए गए 150 के करीब निर्माण लालकिला से हटाए गए और उन स्थानों पर हरियाली विकसित की गई। ज्ञात हो कि ऊषा शर्मा ने एएसआइ का अपना पद अभी नहीं छोड़ा है। (जासं)

सिख प्रतीक के साथ छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दें

नई दिल्ली : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख धर्म के प्रतीक धारण करने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देने की मांग की है। कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि पिछले दिनों कई सिख छात्रों को परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया था। इस मामले में कमेटी अदालत में भी गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने शपथ पत्र देकर कहा है कि धातु की बनी वस्तुओं से नकल की संभावना है इसलिए इसे परीक्षा केंद्र में लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर अदालत में रोक लगाने के लिए शपथ पत्र दिया जा रहा है। (जासं)

मार्च के शुरू में मिल सकता है दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▸ **विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए इस बार लेटलतीफी करने के मूड में नहीं पार्टी**

▸ **विधिवत प्रभार संभालने से पहले ही अंतरिम प्रभारी ने की करीब 70 नेताओं से मुलाकात**

मार्च के पहले सप्ताह तक नेतृत्वविहीन दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर विचार विमर्श का दौर अभी भी जारी है। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से सबक लेते हुए पार्टी इस बार नए अध्यक्ष के चयन में अधिक लेटलतीफी करने के मूड में नहीं है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक नव नियुक्त प्रदेश कांग्रेस के अंतरिम प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए विधिवत कार्य प्रभार संभालने से पूर्व ही उन्होंने दिल्ली के नेताओं से मिलना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम तक वह दिल्ली के छोटे-बड़े करीब 70 नेताओं से मिल चुके थे। सभी से शिकायतों एवं सुझावों को नोट कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए सुझाव भी दे रहे हैं। इसी के आधार पर गोहिल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट और अनुशंसा प्रेषित करेंगे।

सूत्रों ने बताया कि संगठन को मजबूत करने की मंशा के साथ पार्टी इस बार पिछली गलतियां नहीं दोहराना चाहती। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता दिख रहा था, लेकिन गत 20 जुलाई को शीला दीक्षित के निधन के बाद प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष के लिए तीन महीने से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। 23 अक्टूबर को सुभाष चोपड़ा को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने थे। इसी का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। इसलिए इस बार नए अध्यक्ष के चयन में देरी नहीं होगी। नए अध्यक्ष के रूप में संगठन चलाने की क्षमता को विशेष रूप से केंद्र में रखा जाएगा।

दूसरी ओर जानकारी मिली है कि शक्ति सिंह गोहिल सोमवार या मंगलवार को अपना प्रभार संभाल सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि गोहिल ने सभी हारे हुए प्रत्याशियों को सकारात्मक संदेश वाला पत्र लिखकर पॉजिटिव राजनीति की शुरुआत की है। इससे भविष्य में भी बेहतर नतीजों की उम्मीद की जा सकती है।

स्वाति मालीवाल और नवीन जयहिंद ने सहमति से लिया तलाक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया है। इसकी जानकारी स्वाति ने ट्वीट कर दी।

स्वाति मालीवाल

स्वाति ने ट्वीट किया, वह बहुत दुखद समय होता है, जब परियों की कहानी खत्म होती है। मेरी कहानी भी खत्म हो गई है। मैंने और नवीन ने तलाक ले लिया है। कभी-कभी दो बेहतरीन शख्स भी साथ नहीं रह पाते हैं। मुझे उनकी व उनके साथ गुजारी जिंदगी की कमी हमेशा खलेगी। रोज मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि वह हमें और हमारे जैसे अन्य लोगों को यह दर्द सहने की क्षमता दें।

उल्लेखनीय है कि स्वाति मालीवाल और नवीन जयहिंद ने अपना राजनीतिक सफर आम आदमी पार्टी से शुरू किया। स्वाति दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जबकि नवीन जयहिंद के पास हरियाणा की कमान है। हरियाणा में वर्ष 2019 में हुआ विधानसभा चुनाव पार्टी ने नवीन जयहिंद की अगुआई में लड़ा था।

सगाई पर खाईं थीं पुलिस की लाठियां

जागरण संवाददाता, रोहतक

◂ स्वाति मालीवाल द्वारा किए गए ट्वीट का स्क्रीनशॉट।

▸ **दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल**

▸ **आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष हैं नवीन जयहिंद**

नवीन जयहिंद और स्वाति मालीवाल की सगाई और शादी का संयोग खास रहा है। जिस दिन सगाई हुई, उसी दिन इंडिया गेट पर निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसमें नवीन जयहिंद और स्वाति मालीवाल पुलिस की लाठियां खाकर चोटिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दोनों ने बिना दहेज के साधारण शादी की। शादी के बाद अनाथ आश्रम में पहुंचे और उनके बीच ही खाना खाया। एक-दूसरे के लिए जान छिड़कने वालों के वैवाहिक जीवन में तलाक की बात उनके परिचितों को समझ नहीं आ रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग दोनों की शादी को नहीं टूटने के लिए प्रयास में भी जुट गया है।

रोहतक के गांव भैंसरू कलां निवासी नवीन जयहिंद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में छात्र नेता रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गए। जन लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान नवीन जयहिंद सुर्खियों में आए। इसी आंदोलन के दौरान स्वाति मालीवाल से उनका संपर्क हुआ। दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। नवीन जयहिंद और स्वाति मालीवाल के साथ जिस दिन सगाई हुई, उसी दिन निर्भया के विरोध में इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में दोनों ने भाग लिया। भीड़ उग्र होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें नवीन जयहिंद चोटिल हो गए। नवीन जयहिंद को पुलिस की मार से बचाने के लिए स्वाति उनके ऊपर गिर गई, जिससे वह भी चोटिल हो गईं।

2014 लोकसभा चुनाव की स्वाति ने संभाली थी कमान : नवीन जयहिंद ने 2014 में आप के टिकट पर रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रचार के लिए अपनी लकी नीले रंग की कार भेंट की थी। स्वाति मालीवाल ने ही नवीन जयहिंद के चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली थी। पार्टी कार्यालय में स्वाति ही कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाती थीं और उनके प्रचार के लिए कई बार गांव में भी जनसंपर्क किया।

सोशल मीडिया पर समर्थकों ने दोनों को फिर से एक करने का बीड़ा उठाया : स्वाति मालीवाल ने बुधवार को जैसे ही नवीन जयहिंद के साथ तलाक की सूचना का ट्वीट किया तो समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इसे चिंताजनक बताया। समर्थकों ने दोनों को फिर से एक करने का बीड़ा भी उठा लिया है।

शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में आइआइटी दिल्ली 38वें स्थान पर

जासं, नई दिल्ली : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली की विश्व स्तर की शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। यूनाइटेड किंगडम (यूके) की दुनिया भर के शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग देने वाली पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) ने 2020 की रैंकिंग जारी की हैं। इसमें आइआइटी दिल्ली की पिछले वर्ष 2019 की रैंकिंग में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। पिछले वर्ष आइआइटी दिल्ली की रैंकिंग 66वें स्थान पर थी। इस वर्ष 28 रैंक ऊपर जाते हुए आइआइटी दिल्ली ने 38वां स्थान प्राप्त किया है।

आइआइटी दिल्ली के निदेशक प्रो. वी रामगोपाल राव ने कहा है कि संस्थान ने सभी रैंकिंग मानदंडों को सुधारने के लिए बहुत काम और प्रयास किया। हमें खुशी है कि यह मेहनत सफल हुई है। हमने पिछले तीन वर्षों में अपनी रैंकिंग में 300 फीसद तक की वृद्धि देखी है। यह शिक्षक व छात्रों के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत हुआ है।

जेएनयू देशद्रोह मामले में अदालत ने सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जेएनयू देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस की एक अदालत ने सरकार से कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से संबंधित प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि 3 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करें। साथ ही दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सरकार को फिर से लिखें।

इससे पहले पिछले साल 18 सितंबर को अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा था कि एक माह में तय करें कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू देशद्रोह प्रकरण में पिछले साल 14 जनवरी को आरोपपत्र दायर किया था। इसमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित अन्य छात्रों को आरोपित बनाया गया था। अभी तक इस आरोपपत्र पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दिल्ली सरकार से नहीं मिली है।

कन्हैया पर मुकदमे की अनुमति दे सरकार : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने दिल्ली सरकार से देश विरोधी नारे लगाने के जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अदालत ने दिल्ली सरकार को देश विरोधी नारे लगाने के आरोपितों के खिलाफ मुकदमे की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आज तक टुकड़े-टुकड़े गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी गई जिससे देश विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ा है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की वजह से देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सका है। यह चिंता की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले में तुरंत अनुमति देने की अपील की है।

भाजपा में विधानसभा क्षेत्रवार हार की समीक्षा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कार्यालय में मंथन करने के बाद अब नेता क्षेत्र में जाकर भाजपा की हार के कारण तलाश रहे हैं। बुधवार से विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। पहले दिन पांच संगठनात्मक जिलों में बैठक करके कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने नेताओं की गुटबाजी, प्रत्याशियों के चयन और चुनाव प्रचार शुरू करने में देरी और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज करने को हार का कारण बताया।

पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली व शाहदरा जिलों में पड़ने वाले कई विधानसभा क्षेत्रों में समीक्षा बैठक हुई। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडेय, उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सोनकर शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई नेताओं की गुटबाजी चुनाव में भी खत्म नहीं हुई। इसी तरह से कई नेता टिकट नहीं मिलने की वजह से क्षेत्र में मेहनत नहीं की ।

विधानसभा सत्र 24 से, साहनी हो सकते हैं प्रोटेम स्पीकर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की नवगठित सातवीं विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। यह सत्र तीन दिनों तक चलेगा। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 26 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन सबसे वरिष्ठ एवं अनुभवी विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा जो सभी विधायकों को शपथ दिलाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रहलाद सिंह साहनी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि बुधवार को उनकी कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। कैबिनेट ने विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र का अनुमोदन कर दिया है। सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल अनिल बैजल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे फिर प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 25 फरवरी को उपराज्यपाल का भाषण होगा और 26 पर इस भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आएगा। उपराज्यपाल भाषण में दिल्ली के विकास एवं सरकार की योजनाओं के बारे में विचार रखेंगे। इसमें सरकार के अगले पांच साल की योजनाओं का खाका होगा। वहीं, धन्यवाद प्रस्ताव में विधायक अपने-अपने विचार रखेंगे। इस दौरान आपसी सहमति से विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। दिल्ली विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी (आप) के 62 और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आठ विधायक हैं। कांग्रेस का खाता भी नही खुल पाया है।

आम आदमी पार्टी की सरकार के पिछले कार्यकाल में रामनिवास गोयल विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में कई बड़ी योजनाओं पर काम किया है। इनमें विधानसभा को पेपरलेस किए जाने की योजना भी शामिल है।

अध्ययन

टॉक्सिक लिंक की रिपोर्ट 'सिंगल यूज प्लास्टिक : द लास्ट स्ट्रॉ' में सामने आई जानकारी, महाराष्ट्र फैला रहा सबसे ज्यादा कचरा, गुजरात प्लास्टिक कचरा फैलाने में दूसरे स्थान पर, पांच नंबर पर है उत्तर प्रदेश

प्लास्टिक कचरा फैलाने में छठे नंबर पर राजधानी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

प्लास्टिक कचरा फैलाने में देश भर में दिल्ली छठे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का नंबर पांचवां है। महाराष्ट्र पहले, गुजरात दूसरे जबकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर हैं। विडंबना यह कि प्लास्टिक कचरा साल दर साल बढ़ रहा है और मानव जीवन में अभिन्न हिस्से के रूप में शामिल होकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं देश भर में इस पर नियंत्रण के लिए अभी तक भी कोई कारगर व्यवस्था नहीं की गई है।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन : ए ग्लोबल थ्रेट' विषय पर शुरू हुई दो दिवसीय कार्यशाला में 'सिंगल यूज प्लास्टिक : द लास्ट स्ट्रॉ' रिपोर्ट जारी की गई। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही गैर सरकारी संस्था टॉक्सिक लिंक द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट देश में तेजी से बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण की पड़ताल करती है। रिपोर्ट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के हवाले से बताया गया है कि देश में हर साल 3.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। मतलब 9,206 टन प्लास्टिक कचरा हर रोज। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने की दर 0.03 टन है।

3.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल देश में हो रहा उत्पन्न

09 हजार 206 टन प्लास्टिक कचरा हर रोज हो रहा उत्पन्न

> प्लास्टिक कचरा नासूर बनता जा रहा है। माइक्रोप्लास्टिक के अति सूक्ष्म कण पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर नियंत्रण के लिए गंभीर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
> –डॉ. सतीश सिन्हा, एसोसिएट निदेशक, टॉक्सिक लिंक।

प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने की नहीं कोई पुख्ता व्यवस्था : रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने की तो कोई पुख्ता व्यवस्था है ही नहीं, इसे रीसाइकिल करने की प्रक्रिया भी रामभरोसे चल रही है। रीसाइकिलिंग यूनिटों की कोई निगरानी नहीं होती। यह यूनिटें हैं भी स्लम बस्तियों और रिहायशी क्षेत्रों में जहां इनसे वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। हालांकि रीसाइकिलिंग से अलग कहीं-कहीं प्लास्टिक कचरे का उपयोग सीमेंट, स्टील उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के प्राथमिक ईंधन और सड़क बनाने में भी किया जा रहा है, लेकिन इसका प्रभाव दीर्घावधि में ही सामने आ पाएगा।

कैंसर का कारक बन रहे माइक्रोप्लास्टिक के कण

रोजमर्रा के काम में आने वाली ज्यादातर चीजों में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक के कण धीरे-धीरे न केवल हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, बल्कि फेफड़ों और आंतों को हानि पहुंचाने के साथ-साथ कैंसर तक का कारक बन रहे हैं। दरअसल, ये कण त्वचा से चिपक जाते हैं। घंटों चिपके रहने के कारण इससे त्वचा में खिंचाव होता है। इससे एलर्जी भी होती है। आंखों में चले जाए तो कॉर्निया को नुकसान पहुंचने का भय रहता है। सड़क पर जब गाड़ी चलती है तो टायरों की रगड़ से भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पैदा होते हैं। ये कण हवा में मिलकर सांस के जरिये हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख बातें

- 46 फीसद लोग अभी भी खरीदारी में प्लास्टिक बैग का करते हैं इस्तेमाल
- 17 फीसद ही प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करते
- 46 फीसद लोग इस्तेमाल में लाते हैं कपड़े या जूट का बैग
- 77 फीसद लोगों ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग की पैकिंग में प्लास्टिक का काफी उपयोग होता है। 91 फीसद ने कहा कि अगर उन्हें विकल्प मिलता है तो वे ज्यादा पैकिंग से परहेज करते हैं।
- 91 फीसद लोगों का कहना है कि सरकार को प्लास्टिक कचरे पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए।
- 32 फीसद लोगों का कहना है कि धार्मिक-सांस्कृतिक समारोहों में पत्तल पर भोजन परोसा जाए। 33 फीसद ने इसके लिए बायो प्लास्टिक और 25 फीसद ने स्टील के बर्तनों के उपयोग का सुझाव दिया।
- 86 फीसद लोगों ने कहा कि अगर उन्हें विकल्प मिलें तो वे प्लास्टिक पैकिंग में खाना ऑर्डर नहीं करेंगे।
- 87 फीसद लोगों का कहना है कि अगर उन्हें विकल्प दिया जाए तो वे प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देंगे।
- 61 फीसद लोग प्लास्टिक कचरा नियमों की जानकारी ही नहीं रखते।

आज से मौसम लेगा करवट कल हल्की बारिश के आसार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिनोंदिन गर्म हो रहा दिल्ली का मौसम गुरुवार शाम से कुछ करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से देर शाम भी बूंदाबांदी हो सकती है और शुक्रवार को भी हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में आंशिक गिरावट आ सकती है और हल्की ठंडक का भी एहसास हो सकता है।

बुधवार को दिन भर बादलों और सूरज के बीच आंखमिचौली का खेल चलता रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 26.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू-कश्मीर की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप गुरुवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। रात के समय बूंदाबांदी भी हो सकती है। शुक्रवार को भी हल्की बारिश होने के आसार हैं।

127 घुसपैठियों ने हैदराबाद में फर्जी दस्तावेज के आधार पर आधार कार्ड हासिल कर लिया है। पुलिस से इस संबंध में रिपोर्ट मिलने के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) ने इन सभी को नोटिस जारी किया है।

न्यूज गैलरी

आधार को लेकर नोटिस पर यूआइडीएआइ ने दी सफाई

नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने हैदराबाद क्षेत्रीय दफ्तर की तरफ से आधार को लेकर कुछ लोगों को नोटिस भेजे जाने पर सफाई दी है। प्राधिकरण का कहना है कि पुलिस की शिकायत पर 127 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। मीडिया ने इस पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया है। नोटिस का नागरिकता साबित करने से कुछ लेना-देना नहीं है। यूआइडीएआइ ने मंगलवार रात जारी बयान में कहा कि राज्य पुलिस को प्रारंभिक जांच में इनके घुसपैठिया होने का संदेह है। आधार का नागरिकता से लेना देना नहीं है, लेकिन घुसपैठियों को आधार नंबर नहीं जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात कही है। (एजेंसियां)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाएंगे जस्टिस एस मुरलीधरन

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधरन को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में कोलेजियम ने 12 फरवरी की बैठक ने बांबे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंजीत वी. मोरे को मेघालय हाई कोर्ट भेजे जाने की सिफारिश की है। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रवि विजयकुमार मालीमथ को उत्तराखंड हाई कोर्ट स्थानांतरित किए जाने की अनुशंसा की है। जस्टिस मुरलीधरन ने सितंबर 1984 में चेन्नई में वकालत शुरू की थी। 1987 में वह दिल्ली आ गए। वह सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के लिए वकील के रूप में सक्रिय रहे। दिल्ली हाई कोर्ट के वकीलों ने मुरलीधरन के इस्तीफे के विरोध में काम न करने की घोषणा की है। (प्रेट्र)

जीएसटी 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन : सुब्रमण्यम

हैदराबाद : भाजपा नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को बुधवार को 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन बताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को उनके कार्यकाल में किए गए सुधारों के लिए देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' दिए जाने की भी मांग की। स्वामी यहां प्रज्ञा भारती द्वारा 'भारत- वर्ष 2030 तक एक आर्थिक महाशक्ति' विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, देश को 2030 तक 'महाशक्ति' बनने के लिए सालाना 10 फीसद वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आगे कहा, 'ऐसे में हम उस 3.7 प्रतिशत (निवेश इस्तेमाल के लिए जरूरी दक्षता कारक) को कैसे हासिल करेंगे। इसके लिए हमें भ्रष्टाचार से लड़ने और दूसरे निवेश करने वालों को पुरस्कृत करने की जरूरत है। आप उन्हें (निवेशकों को) आयकर और जीएसटी, जो कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा पागलपन है, इसके जरिए आतंकित मत कीजिए।' (प्रेट्र)

आइएनएक्स मीडिया केस में सभी को नियमित जमानत

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने आइएनएक्स मीडिया मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा, फॉरन इंवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (एफआइपीबी) के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना, वित्त मंत्रालय की एफआइपीबी ईकाई के पूर्व सेक्शन अधिकारी अजीत कुमार डुंगडुंग, एफआइपीबी ईकाई में तत्कालीन अवर सचिव (एडिशनल सेक्रेटरी) रबिंद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार) अनूप के पुजारी को नियमित जमानत दे दी है। अभी तक विशेष अदालत ने इन सभी को अंतरिम राहत दे रखी थी। बुधवार को दो लाख के निजी मुचलके और कुछ पाबंदियों के साथ जमानत दी गई। अदालत ने निर्देश दिया है कि कोई भी अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाएगा। साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सीबीआइ ने पिछले माह इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था, जिसमें पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति सहित 12 के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग सहित कई आरोप लगाए गए हैं। (जासं)

राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी होंगे सीवीसी, जुल्का सीआइसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) चयनित किया गया है। जुल्का फिलहाल केंद्रीय सूचना आयोग में बतौर सूचना आयुक्त सेवारत हैं। इनका चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने किया।

एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि उच्चाधिकार समिति ने बहुमत से सुरेश पटेल को सतर्कता आयुक्त तथा अनीता पांडोव को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अनुमोदन के बाद इन नियुक्तियों के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।

संजय कोठारी हरियाणा काडर के 1978 बैच के और जुल्का मध्य प्रदेश काडर के 1979 बैच के सेवानिवृत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारी हैं। कोठारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में सचिव भी रह चुके हैं। उन्हें नवंबर 2016 में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था।

बिमल जुल्का औद्योगिक विकास विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क आयुक्त, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग में निदेशक व रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (जी/एयर) आदि पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्तियों पर विरोध जताया। तीन सदस्यीय समिति में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाला स्वतंत्र निकाय है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ विभिन्न प्राधिकारों को नियोजन, क्रियान्वयन व निगरानी से संबंधित सलाह देना है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार कानून के तहत किया गया है। इसकी परिधि में सभी केंद्रीय सार्वजनिक निकाय आते हैं।

संजय कोठारी (फाइल)। ट्विटर

- सुरेश पटेल को सतर्कता आयुक्त व अनीता पांडोव को सूचना आयुक्त चुना गया
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति ने लिया फैसला

बिमल जुल्का (फाइल)। प्रेट्र

गैरकानूनी ढंग से हुई केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति, रद करे सरकार : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पार्टी ने कहा, नियुक्ति खारिज नहीं हुई तो कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती
- चपरासी की भी ऐसी मनमानी नियुक्ति नहीं होती : मनीष तिवारी

कांग्रेस ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार देते हुए संजय कोठारी को सीवीसी नियुक्त करने के फैसले को रद करने की मांग की है। पूरी प्रक्रिया को मनमाना ठहराते हुए पार्टी ने सरकार को चेताया है कि इसे रद कर नए सिरे से नियुक्ति नहीं की गई तो वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सीवीसी की नियुक्ति में तमाम प्रक्रिया और कानूनों की धज्जियां उड़ाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि संजय कोठारी ने न इस पद के लिए आवेदन दिया था और न ही सर्च कमेटी ने अपनी ओर से उनके नाम का सुझाव दिया था। मनपसंद अधिकारी को सीवीसी बनाने के सरकार के फैसले से साफ है कि वह कुछ बड़ी गड़बड़ी छुपाना चाहती है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्त के लिए आए आवेदनों और उन्हें शार्टलिस्ट करने में सर्च कमेटी की खामियों को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चयन समिति की बैठक में मंगलवार को जब प्रमुखता से उठाया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी राय से सहमति जताई थी। लेकिन, इसके बाद खामियों को दुरुस्त करने की बजाय पीएम ने राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को सीवीसी नियुक्त करने का फैसला कर लिया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सीवीसी की इस तरह से की गई नियुक्ति से साफ है कि संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा-एनडीए सरकार किस तरह ध्वस्त कर रही है। सर्च कमेटी में वित्त सचिव राजीव कुमार भी थे, जबकि उन्होंने खुद सीवीसी के लिए आवेदन कर रखा था। इसकी वजह से वह दूसरे आवेदकों के मुकाबले गैरवाजिब लाभ की स्थिति में थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि चपरासी के पद पर नियुक्ति भी इस मनमाने तरीके से नहीं की जा सकती, जैसा कि सरकार ने सीवीसी के मामले में किया है।

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को सरकार की हरी झंडी

बड़ा कदम ▶ 'खुले में शौच' की समस्या से मुक्त होने के बाद ग्रामीण कचरा प्रबंधन पर जोर

स्वच्छता की स्थिति को बेहतर बनाने में केंद्र के साथ राज्यों की होगी समान भागीदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को सरकार ने आज मंजूरी दे दी। मिशन का दूसरा चरण 2024-25 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पत्रकारों को इसकी जानकारी देने आए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि दूसरे चरण में 'खुले में शौच' की समस्या से मुक्त (ओडीएफ) होने के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान जहां ओडीएफ अभियान को जारी रखा जाएगा, वहीं कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कार्यक्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी व्यक्ति न छूटे और हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे। स्वच्छता मिशन के दूसरे चरण को लागू करने में 2020-21 से 2024-25 के बीच 52,497 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होगी। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों की ओर से ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्रियान्वयन के लिए 30,375 करोड़ का प्रस्ताव किया है। ओडीएफ प्लस कार्यक्रम मनेरगा के साथ सम्मिलित होगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आइएचएचएल) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नए पात्र घरों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए वित्तपोषण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है और घरों की संख्या को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण (सीएमएससी) के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर दो से तीन लाख रुपये कर दिया गया है।

देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज दो अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की शुरुआत के समय 38.7 फीसद दर्ज की गई थी। इस मिशन के शुरू होने से 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, परिमाणस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को दो अक्टूबर, 2019 को ओडीएफ घोषित किया। हालांकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्यों को यह सलाह दी है कि वे इस बात की पुनः पुष्टि कर लें कि ऐसा कोई ग्रामीण घर न हो, जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो। अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती है तो उसको शौचालय निर्माण के लिए जरूरी मदद दी जाए ताकि कोई भी पीछे न छूटे।

अप्रासंगिक हो चुके कानूनों से मिलेगी मुक्ति

नई दिल्ली : देश को जल्द ही अप्रासंगिक हो चुके कानूनों से मुक्ति मिलेगी। सरकार ने इसे लेकर 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग ऐसे कानूनों की पहचान करेगा, जिनकी जरूरत नहीं रह गई है। साथ ही वह मौजूदा कानूनों को जांचेगा और सुधार का सुझाव देगा। फिलहाल आयोग का कार्यकाल तीन साल का होगा।

आयोग में अध्यक्ष समेत चार पूर्णकालिक, पांच अंशकालिक सदस्यों संग विधायी विभाग व कानूनी मामलों के विभागों के सचिव शामिल रहेंगे। आयोग के अध्यक्ष का फैसला होना बाकी है। देश में विधि आयोग का गठन 1955 से होता आ रहा है। 21 वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को पूरा हुआ था।

दिल्ली कैंट जाएगा सेना मुख्यालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : सेना मुख्यालय जल्द ही रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक से दिल्ली कैंटोनमेंट चला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नए सेना भवन के लिए शुक्रवार को वहां भूमिपूजन करेंगे।

सूत्रों ने बताया, 'दिल्ली कैंटोनमेंट क्षेत्र में स्थित मानेक शॉ सेंटर के करीब 39 एकड़ में नए सेना भवन का निर्माण पांच साल में हो जाएगा।' साउथ ब्लॉक रायसीना हिल्स कांप्लेक्स का भाग है, जिसे औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशराज की नई राजधानी के हिस्से के रूप में बनवाया गया था। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वायसराय हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) और संसद भवन हरित क्षेत्र से घिरा है। इनका निर्माण नई दिल्ली के निर्माण की शुरुआती दौर में वर्ष 1912 में किया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने जनवरी में कहा था कि सरकार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में विकसित करना चाहती है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबी हरित पट्टी को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। फिलहाल साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय हैं, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय व वित्त मंत्रालय हैं।

नई शिक्षा नीति के मसौदे को पीएम ने दी हरी झंडी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम ने कुछ सुझावों के साथ नई नीति के अंतिम मसौदे को दी मंजूरी

देश को नई शिक्षा नीति को लेकर अब और इंतजार नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ सुझावों के साथ नई शिक्षा नीति के अंतिम मसौदे को हरी झंडी दे दी है। अब यह नीति मार्च के पहले हफ्ते में कभी भी आ सकती है। प्रधानमंत्री ने इसके अमल को लेकर भी चर्चा की। मंत्रालय ने इसे लेकर एक प्रजेंटेशन भी दिया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में बुधवार को करीब चार घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा नीति से जुड़े सभी विषयों को गंभीरता से जांचा। साथ ही इससे जुड़े प्रजेंटेशन को देखा। बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ही मंत्रालय के सचिव अमित खरे सहित कई और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पीएम के सामने इस प्रजेंटेशन से पहले निशंक ने मंगलवार को आला अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर लंबी चर्चा की थी।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में नई नीति से जुड़े विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। नीति को जिस तरह से देश की भावी जरूरतों को समझते हुए रोजगारपरक बनाया गया है, उसकी तारीफ भी हुई। बदलते वैश्विक हालात में शिक्षा को नई दिशा देना जरूरी हो गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक के मुताबिक नई शिक्षा नीति नए भारत का निर्माण सुनिश्चित करेगी। 33 सालों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। सरकार ने नई शिक्षा नीति की जरूरत को काफी पहले ही समझ लिया था। यही वजह है कि सरकार के गठन के बाद 2015 में ही इस दिशा में काम हो गया था। हालांकि इसे अंतिम रूप देने में करीब पांच साल का समय लग गया।

नुकसान के आकलन के लिए क्रॉप कटिंग के बजाय स्मार्ट तकनीक पर जोर

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

फसल के नुकसान का आकलन करने वाली प्रणाली को स्मार्ट किया जाएगा। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि मुआवजे के भुगतान में राज्यों की हिस्सेदारी जमा न होने से विलंब होता रहा है। इसके लिए इस प्रावधान में तब्दीली कर दी गई है। अब राज्यों को खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च और रबी सीजन के लिए 30 सितंबर तक अपना हिस्सा जमा कराना ही होगा। ऐसा न करने वाले राज्य योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे।

हिस्सेदारी में बदलाव : योजना में राज्यों व केंद्र की हिस्सेदारी भी बदली गई है। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में योजना पर आने वाले खर्च का 90 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि राज्यों को केवल 10 फीसद वहन करना होगा। बाकी राज्यों में यह योजना 50-50 फीसद के आधार पर ही चलेगी। योजना में प्रशासनिक खर्च का पहले प्रावधान नहीं था, जिसे अब जोड़ दिया गया है। इसके तहत प्रशासनिक खर्च के लिए तीन फीसद राशि का प्रावधान किया गया है।

जिला जज सीधी भर्ती परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकते सिविल जज

अहम फैसला

- अभी भी सिविल जज आदि प्रोन्नति से या लिमिटेड कंपिटीटिव एक्जाम के जरिये ही जिला जज बन सकते हैं
- मुकदमा लंबित रहने के दौरान सीधी भर्ती से जिला जज नियुक्त हुए सिविल जज वापस लौटेंगे अपने मूल पद पर

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज पद पर भर्ती के बारे में कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वकीलों के लिए तय 25 फीसद कोटा की जिला जज (उच्च न्यायिक सेवा) सीधी भर्ती परीक्षा में निचली अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्य यानी सिविल जज हिस्सा नहीं ले सकते। सिविल जज उस परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य के निचली अधीनस्थ सेवा के सदस्य यानी सिविल जज प्रोन्नति के जरिये या उनके बीच (सिविल जजों में) होने वाले लिमिटेड कंपिटीटिव एक्जाम (एलसीइ) के जरिये जिला जज नियुक्त हो सकते हैं।

इसके अलावा, कोर्ट ने आदेश दिया है कि अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान जो सिविल जज वकीलों के कोटे की सीधी भर्ती परीक्षा से जिला जज नियुक्त हो गए हैं, वे अपने मूल पद पर वापस लौट जाएंगे। वे जिला जज पद पर बने नहीं रह सकते। हालांकि अगर उनकी प्रोन्नति का समय हो गया है या उनके जूनियर जिला जज पद पर प्रोन्नत हो चुके हैं, तो हाईकोर्ट उनके मामलों पर भी विचार कर सकता है। लेकिन वे कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत सीधी भर्ती परीक्षा से पाए पद के आधार पर कोई दावा नहीं कर सकते।

जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पूरे देश की अधीनस्थ न्यायिक सेवा से उच्च न्यायिक सेवा में जाने के मामले में लागू होगा। शीर्ष अदालत ने पूरे देश के लिए कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बुधवार को यह अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, विनीत शरण और एस रविन्द्र भट्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल बहुत सी याचिकाएं निपटाते हुए यह आदेश दिया।

वकीलों के लिए सात साल का अनुभव जरूरी

जिला जज (उच्च न्यायिक सेवा) पद पर नियुक्ति का नियम कहता है कि 25 फीसद पद वकीलों के कोटे से सीधी भर्ती परीक्षा के जरिये भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने वाले वकील के पास सात साल का वकालत का अनुभव होना जरूरी है। और वह आवेदन करते समय व नियुक्ति के समय सक्रिय वकालत के पेशे में हों। वह न्यायिक या किसी और सेवा में नहीं होना चाहिए। बाकी के 75 फीसद पदों में 50 फीसद प्रोन्नति से और 25 फीसद सिविल जजों के बीच होने वाली एलसीइ के जरिए भरे जाएंगे।

मूल पद पर वापस जाना होगा

इस मामले में निचली अधीनस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने उन्हें भी सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने की मांग की थी। कुछ लोग कोर्ट के अंतरिम आदेश के सहारे सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे हालांकि बाद में कोर्ट ने अंतरिम आदेश हटा लिया था लेकिन कुछ लोगों की इस बीच नियुक्ति हो गई थी। जिन्हें बुधवार के फैसले के बाद वापस मूल पद पर जाना होगा।

नियुक्ति, प्रोन्नति में राज्यपाल अथॉरिटी

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 233 की व्याख्या करते हुए कहा, इसे देखते हुए न्यायिक अफसरों को सीधी भर्ती परीक्षा में शामिल होने पर पाबंदी लगाने वाले नियम असंवैधानिक नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, न्यायिक सेवा के सदस्य प्रोन्नति या एलसीइ के जरिये जिला जज बन सकते हैं। नियुक्ति, प्रोन्नति और स्थानांतरण के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्यपाल ही अथॉरिटी हैं। ये अनुच्छेद 234 और 235 के तहत बने नियमों के तहत होगा।

चौंकाया

कैबिनेट की बैठक के बाद बिना किसी तय कार्यक्रम के राजपथ गए प्रधानमंत्री, विभिन्न स्टॉल पर की दस्तकारों और शिल्पकारों से बातचीत

हुनर हाट में पहुंचे मोदी, लिट्टी-चोखे का लिया स्वाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अचानक राजपथ के लॉन में आयोजित हुनर हाट में पहुंचकर लोगों को चौंका दिया। वहां उन्होंने बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी-चोखा खाया। कुल्हड़ में चाय पी। उन्होंने इसका भुगतान भी स्वयं किया। 'कौशल को काम' थीम पर आधारित हुनर हाट 13 फरवरी से 23 फरवरी तक राजपथ के लॉन में आयोजित किया जा रहा है। जहां देशभर के हुनर के उस्ताद दस्तकार, शिल्पकार, खानसामे भाग ले रहे हैं। इनमें 50 फीसद से अधिक महिला दस्तकार शामिल हैं।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने बिना किसी तय कार्यक्रम के हुनर हाट जाने का फैसला किया। रोचक तथ्य यह है कि हुनर हाट का आयोजन करने वाले कैबिनेट सहयोगी व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सुबह कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद नकवी अपने घर पहुंचे तो सूचना आई कि पीएम हुनर हाट जाने वाले हैं। वह भी आयोजन स्थल पर पहुंचे। पीएम ने यह फैसला अचानक लिया, जिसकी वजह से हुनर हाट के आसपास या अंदर सुरक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी।

पीएम ने ट्वीट भी किया : प्रधानमंत्री करीब 1.30 बजे हुनर हाट पहुंचे। यहां उन्होंने बिहारी व्यंजन स्टॉल पर लिट्टी-चोखा खाया और 80 रुपये का भुगतान किया। नकवी के साथ चाय पीने के बाद 40 रुपये दिए। बाद में ट्वीट कर बताया कि हुनर हाट में उन्होंने स्वादिष्ट लिट्टी-चोखा खाया और चाय पी। उन्होंने लिखा कि इंडिया गेट पर हुनर हाट में शानदार दोपहर बिताई। यह हस्तशिल्प, वस्त्र व स्वादिष्ट भोजन समेत उत्पादों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। इसे देखें।

लगे मोदी-मोदी के नारे, लागों ने ली सेल्फी : पीएम ने विभिन्न स्टॉल पर दस्तकारों व शिल्पकारों से भी बातचीत की। महिला दस्तकार मेहरूनिशां ने मोदी को बताया कि वह पहले दिल्ली हाट के बाहर ही कैंडल बेचती थीं। हुनर हाट योजना का लाभ लिया और अब अपना घर खरीद लिया है। पीएम ने लाल किले की पेंटिंग के साथ देश के विभिन्न राज्यों के ऐतिहासिक स्थलों के जरिये बनाए गए भारत के नक्शे की पेंटिंग को देखकर कलाकार की हौसला अफजाई की। मोदी के हुनर हाट पहुंचने पर उनके आसपास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए। कई ने तो उनके साथ सेल्फी भी ली।

इंडिया गेट पर चल रहे हुनर हाट में बुधवार को शिल्पकारों से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

कह के रहेंगे माधव जोशी

500 प्रश्न हस्तलिखित भेजे हैं विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में 25 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में। इससे विधानसभा की गतिविधियों को ऑनलाइन करने पर सवाल उठ रहे हैं।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 फरवरी 2020

न्यूज गैलरी

सीएम के बिस्तर के पास भ्रष्टाचार का सांप : गौतम

पंचकूला : नारनौंद से जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम ने अब सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। पहले अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लपेटे में लिया तो अब गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री के बिस्तर में भ्रष्टाचार का सांप घूम रहा है। बाहर का सांप खतरनाक नहीं होता, बल्कि बिस्तर के आसपास का सांप खतरनाक होता है। रामकुमार गौतम यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को रोक पाए तो सबसे कामयाब मुख्यमंत्री होंगे, यदि नहीं रोक पाए तो प्रदेश का भगवान ही मालिक होगा। इसके साथ ही गौतम ने दावा किया कि सीएम भ्रष्टाचार को 99.9 फीसद रोक नहीं पाएंगे। दुष्यंत का नाम लिए बगैर गौतम ने कहा कि कुछ लोग आए ही भ्रष्टाचार करने के लिए हैं। मुख्यमंत्री खुद ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें मजबूती से काम करना होगा। (जासं)

पीके की गतिविधि पर रहेगी जदयू की नजर

पटना : अपने पुराने रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) से निबटने के लिए जदयू ने नई रणनीति तैयार की है। अब उनकी हर गतिविधि पर पार्टी द्वारा नजर रखी जाएगी, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया से परहेज किया जाएगा। यही वजह है कि एक दिन पहले पीके पर हमलावर रहने वाले जदयू नेता और प्रवक्ता बुधवार को खामोश रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह और लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में पीके का नाम लेने से बचने की भी कोशिश की। हालांकि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने बुधवार को पीके का नाम लिए बिना टिप्पणी की। कहा, बिहार में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। धार्मिक, प्राकृतिक से लेकर कई तरह के। नया अध्याय राजनीतिक पर्यटन का जुड़ गया है। बोले अब कुछ लोग राजनीतिक पर्यटन के लिहाज से भी आते हैं। ऐसे लोगों पर क्या टिप्पणी करें। (राब्यू)

बंगाल में सियासत की भेंट चढ़ा स्कूल ड्रेस पर 'कमल' का लोगो

कोलकाता : भाजपा और तृणमूल के बीच जारी सियासी जंग की भेंट अब यहां के एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों का ड्रेस पर लगे 'कमल' का लोगो चढ़ गया है। सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के विरोध के बाद दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित रनिया प्री प्राइमरी स्कूल ने स्कूल ड्रेस से कमल का लोगो हटाने का फैसला किया है। स्कूल की प्रभारी शिक्षक बिजली दास ने इसकी पुष्टि की है। दास ने बताया कि हम पिछले 10–11 वर्षों से स्कूल ड्रेस में इस लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। अचानक कुछ लोगों ने इस पर आपत्तियां उठानी शुरू कर दी, इसलिए हमने इसे बदलने का फैसला लिया है। (जासं)

देश को अब रामराज चाहिए समाजवाद नहीं : योगी

विपक्ष पर बरसे ▶ बोले– रामभक्तों पर गोली चलाने वाले पूछ रहे सवाल

सीएम ने कहा– सीएए का विरोध करने वालों को मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

देश को रामराज चाहिए, समाजवाद नहीं, क्योंकि समाजवाद का अमानवीय चेहरा दुनिया देख चुकी है। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कही। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में योगी विपक्ष पर बरसे। उन्होंने कहा कि रामभक्तों पर गोली चलाने और देशद्रोहियों व उपद्रवियों की पैरोकारी करने वालों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है।

दो घंटे से अधिक के संबोधन में योगी ने अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर एतराज जताया। कहा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वही उसको तार-तार कर रहे हैं। संवैधानिक प्रमुख पर कागज के गोले फेंकने को बहादुरी समझा जाता है। जिन्होंने इसी सदन में विधायकों को चोटिल किया, वे विधायकों के सम्मान की बात करते हैं। तंदूर कांड जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले महिला सशक्तीकरण की दुहाई देते हैं।

लखनऊ में बुधवार को विधान मंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

बच्चों को सीएए विरोधियों के पास नारे लगाने भेज रहे बड़े लोग : सपा प्रमुख का नाम लिए बगैर योगी ने कहा कि सीएए का विरोध करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। अपराधी भी अपने बच्चों को अपराधी नहीं बनाना चाहता है पर मैं देख रहा हूं कि बड़े लोग अपनी बेटी और बच्चों को सीएए विरोधी नारेबाजी करने भेज रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुलिसिया कार्रवाई को सही करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 15 हजार छात्र अलीगढ़ को जला देना चाहते थे लेकिन, पुलिस की सक्रियता से कामयाब नहीं हो सके। तिरंगे की आड़ लेकर देश तोड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को उनकी भाषा में ही समझाया जाएगा। योगी ने कहा कि दो और तीन अक्टूबर 2019 को 36 घंटे सदन में गंभीर चर्चा से बाहर रहने वाले विपक्ष को प्रदेश की 22 करोड़ जनता से सरोकार नहीं है।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली मंजूर नहीं तो खारिज भी नहीं की : कमलनाथ

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि यह सच है कि प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली अब तक स्वीकार नहीं की गई है, लेकिन यह भी सच है कि इसे अब तक खारिज भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने यह बात आइपीएस मीट को संबोधित करते हुए कही।

भोपाल के मिंटो हॉल में दो दिनी आइपीएस मीट-2020 का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। कमलनाथ ने अप्रत्यक्ष तौर पर आइएएस और आइपीएस अधिकारियों के बीच चल रहे टकराव को लेकर कहा कि आप भी सरकार के अंग हैं। हम अंगों का विभाजन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदेश का चेहरा है इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा हो जाती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में बेहतर पुलिसिंग हथियार से नहीं होगी, बल्कि इसके लिए बेहतर टेक्नोलॉजी होगी। हम ऐसी पुलिस व्यवस्था देंगे जिससे अन्य राज्य प्रदेश की पुलिस से सीखेंगे। इसके लिए सरकार पर्याप्त फंड उपलब्ध कराएगी।

दिग्विजय ने भी किया समर्थन : मीट को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी प्रत्यक्ष तौर पर प्रदेश के बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आइएएस और आइपीएस के बीच टकराव का मामला बना दिया गया है जबकि हकीकत में 20 लाख की आबादी वाले शहरों में कानून-व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है इसे संभालने के लिए सिंगल अथॉरिटी की जरूरत है।

शरद बोले, तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा जाएगा विस चुनाव

राज्य ब्यूरो, पटना

▶ लालू से मुलाकात के बाद दिया बयान, खुद को रेस से बाहर किया

वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने कहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा-राजद, राज्य विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। विधानसभा चुनाव भी उनके चेहरे पर ही लड़ा जाएगा।

इन दिनों महागठबंधन में चेहरे का सवाल तेजी से उभर रहा है। खासकर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एलान के बाद यह सवाल और तीखा हुआ। शाह ने कहा था कि एनडीए विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेगा। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस के अलावा रालोसपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी भी असहज महसूस कर रही है। इस बीच, इन दलों ने शरद यादव के नाम को आगे करने की कोशिश की। शरद ने कहा-कुछ लोग मेरे चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। लेकिन, अंततः तेजस्वी का चेहरा ही ठीक रहेगा।

शरद यादव की पिछली बिहार यात्रा के समय रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने बंद कमरे में उनसे बातचीत की थी। इन नेताओं ने शरद से नेतृत्व करने का आग्रह किया था। पटना से शरद रांची गए। वहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई। समझा जाता है कि लालू प्रसाद के राजी न होने के बाद ही शरद ने अपने बदले तेजस्वी के चेहरे को पेश किया है।

बिहार में तीसरे फ्रंट की कोशिश में जुटे पप्पू यादव

राज्य ब्यूरो, पटना : पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि हम एक मजबूत संकल्प लेकर प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी, कन्हैया कुमार और अन्य वाम दलों के साथ एक नया मोर्चा बनाएंगे। राज्य को विकास के पथ पर ले जाएंगे। उन्होंने सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों को लेकर 23 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। बुधवार को पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। मेरे पास विकास का अगले तीन साल का ब्लू प्रिंट तैयार है। वहीं, पप्पू यादव ने कन्हैया कुमार की तारीफ की तो राज्यसभा सदस्य मीसा भारती भड़क गईं। मीसा ने पप्पू को बिना पेंदी का लोटा करार दिया और नसीहत दी कि वह पहले अपनी चिंता करें। फिर किसी पर टिप्पणी करें।

बिना काम कराए तीन साल में खर्च डाले सात करोड़

रमेश सिंगटा, शिमला

लोकायुक्त कार्यालय सरकार पर बोझ बनकर रह गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की फटकार के बावजूद सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाई है। इसके बगैर कार्यालय भी सुचारू तौर पर नहीं चल पा रहा है। लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तीन साल में लोकायुक्त कार्यालय के स्टाफ और अफसरों के वेतन, सुविधाओं पर करीत सात करोड़ खर्च किए गए हैं। इससे 50 हजार करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबी सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ा ही है, फिजूलखर्ची को भी बढ़ावा मिला है।

सूत्रों के अनुसार स्टाफ के कार्यालय आने और जाने का भी समय तय नहीं है। मुख्य सचिव के निर्देश को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है। सभी सरकारी कर्मचारियों को बॉयोमीट्रिक से हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सचिवालय में खुद मुख्य सचिव भी इसी मशीन से उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर स्थित लोकायुक्त कार्यालय ने इस दिशा में पहल नहीं की है।

हर माह 20 लाख खर्च : लोकायुक्त कार्यालय में सचिव, रजिस्ट्रार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) तीन अधिकारी हैं। इनके वेतन, सुविधाओं पर प्रतिमाह पांच लाख से अधिक का खर्च आता है। इसके अलावा 34 कर्मचारियों पर 15 लाख का खर्च आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में कहा था कि सेकेंडमेंट पर भेजे गए कर्मचारियों को वापस मूल विभाग में लाया जाएगा, लेकिन लोकायुक्त दफ्तर में मंत्री की भी परवाह नहीं की। दो कर्मियों को स्थायी तौर यहीं तैनाती दे दी गई है।

मानवाधिकार आयोग का है अतिरिक्त जिम्मा : प्रदेश में अरसे से मानवाधिकार आयोग का भी अध्यक्ष नहीं है। इस कारण आयोग कार्यालय का कामकाज भी लोकायुक्त कार्यालय के ही जिम्मे है। अभी नए अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्त नहीं हुई है। इसके चलते वहां ठीक से काम नहीं हो पा रहा है।

रजिस्ट्रार व एएसपी को नहीं दिखाते हाजिरी रजिस्टर : लोकायुक्त कार्यालय में रजिस्ट्रार (जज) और पुलिस विभाग से आए एएसपी को भी स्टाफ की हाजिरी नहीं दिखाई जाती है। उन्हें यह भी नहीं बताया जाता है कि जनता की ओर से कितनी शिकायतें आई हैं। सारा नियंत्रण सचिव ने अपने पास रखा है।

'कर्मचारी की मौत के बाद नहीं वसूल सकते बकाया'

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर सरकार पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने सरकार को आठ सप्ताह में सेवानिवृत्ति लाभ और पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने उपायुक्त को हर्जाने की राशि उस अधिकारी से वसूलने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से भुगतान में देरी हुई है। इस संबंध में रानी किस्कू ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

छह साल बाद किया रिटायर : सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शादाब बिन हक ने अदालत को बताया कि रानी किस्कू के पति बहरागोड़ा में पंचायत सेवक के पद पर कार्यरत थे। उन्हें 2000 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन विभाग ने उन्हें 2006 में सेवानिवृत्त किया। 2010 में उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति लाभ व पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। इस दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि 2000 में ही इनको सेवानिवृत्त होना था, लेकिन गलती से 2006 में सेवानिवृत्त हुए। इसलिए छह साल में मिले वेतन की राशि की रिकवरी की जाएगी और बाकी रकम को पेंशन में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कर्मचारी को समय पर सेवानिवृत्त नहीं करना सरकार की लापरवाही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर नितिन गडकरी को सुनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ इलेक्ट्रिक वाहन नीति से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान जताई इच्छा, नहीं किया समन

प्रदूषण स्तर घटाने और पेट्रोलियम आयात खर्च कम करने के लिए कई बार इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने की वकालत कर चुके केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुप्रीम कोर्ट इस नीति पर सुनना चाहता है। देश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू कराने की मांग पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंत्री को सुनने की इच्छा जताई। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर आपत्ति जताई गई थी।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल (एएसजी) एएनएस नंदकर्णी से कहा कि आपके मंत्री इस बारे में कई बार बोल चुके हैं। हम उन्हें सुनना चाहते हैं। क्या मंत्री आकर इलेक्ट्रिक वाहन की नीति के प्रस्ताव को बता सकते हैं। पीठ ने कहा कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आकर बताना चाहिए। इस पर नंदकर्णी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर मंत्री कोर्ट में पेश हुए तो यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है जो कि ठीक नहीं होगा। नंदकर्णी ने खुद इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में कोर्ट को जानकारी दी।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

इस पर जस्टिस बोबडे ने कहा कि कोर्ट मंत्री को पेश होने के लिए समन नहीं कर रहा है। यह मामला राजनीति का नहीं है, बल्कि कई चीजों से जुड़ा है। कोर्ट का मानना है निर्णय लेने का अधिकार रखने वाली अथारिटी के साथ मिल कर सब पर एक साथ ही विचार होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहनों का असर सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा।

वाहनों से प्रदूषण पर ज्यादा बात नहीं होती : पीठ ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का असर वायु प्रदूषण कम करने पर पड़ेगा। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। लोग वायु प्रदूषण के लिए पटाखों की बात करते हैं, पराली जलाने की बात करते हैं लेकिन वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर उतनी बात नहीं होती जो कि प्रदूषण का बड़ा कारण है।

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन सीपीआइएल की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति को ठीक ढंग से लागू करना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देने के साथ ही ऐसे वाहनों की चार्जिंग के सिस्टम लगाए जाने चाहिए। याचिका में कोर्ट से सरकार की 2020 की इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति लागू कराने की मांग की गई है।

कैप्टन के पांच सलाहकारों ने दिया इस्तीफा

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

▶ मुख्यमंत्री ने इंतजार करने को कहा, वड़िंग पहले ही छोड़ चुके हैं पद

▶ राज्यपाल ने सरकार के पारित बिल पर सवाल उठाते हुए लौटाई थी फाइल

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पांच सलाहकारों ने नियुक्ति के पांच माह बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक सलाहकार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पहले ही पद छोड़ चुके हैं। इनकी नियुक्ति पिछले साल सितंबर में हुई थी। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (लाभ का पद) बिल-2019 पर लगाई आपत्ति की फाइल एडवोकेट जनरल (एजी) ऑफिस को लौटा दी है। इसके बाद ही पांचों विधायकों ने सीएम के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया।

कैप्टन सरकार ने छह विधायकों को सलाहकार नियुक्त करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल-2019 विधानसभा में लाकर विधायकों को इसके दायरे से बाहर कर दिया था, लेकिन जब फाइल राज्यपाल के पास गई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कई सवाल पूछ लिए। इन सवालों का जवाब तैयार करके फाइल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल अतुल नंदा को भेज दी। सूत्रों का कहना है कि अतुल नंदा ने मुख्यमंत्री से बात करने के बाद फाइल लौटा दी है।

कैप्टन सरकार ने विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, इंद्रबीर सिंह बुलारिया, संगत सिंह गिलजियां को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया था। तरसेम सिंह डीसी और कुलजीत नागरा को सलाहकार (योजना) नियुक्त किया गया था। सभी को कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया। इनमें से राजा वड़िंग अपना इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं। हालांकि, यह भी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और सभी विधायकों को आश्वासन दिया है कि वह अभी इंतजार करें। वह उनके लिए कुछ करेंगे।

विधायक बोले– बिल पास होने तक नहीं संभालेंगे पद : एक विधायक ने इस बात की पुष्टि की है कि वे मंगलवार शाम को सीएम से मिले थे। हमने उनसे कहा कि हम अपना पदभार तभी ग्रहण करेंगे, जब राज्यपाल बिल को पास कर देंगे। अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए हमारा इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन सीएम ने कहा कि वे अभी इंतजार करें। इन सभी विधायकों को पूरा स्टाफ व ऑफिस मुहैया करवा दिया गया था।

राज्यपाल ने अधिकार व वैधानिकता पर उठाया था सवाल : राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने मुख्यमंत्री के सलाहकारों के अधिकार व कर्तव्य, योग्यता व भत्ते, वैधानिकता व जवाबदेही से जुड़े सवाल पूछते हुए फाइल लौटा दी। उन्होंने नियुक्ति के वित्तीय प्रभाव पर भी सवाल पूछे थे। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने हालांकि फाइल लौटाने की बात का तब खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने विधेयक को लेकर राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है।

पर्यावरण संरक्षण व ग्राम विकास पर भागवत करेंगे मंथन

जागरण संवाददाता, रांची

▶ पांच दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत

▶ अलग-अलग दिन झारखंड और बिहार के प्रांत स्तर के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक

▶ 23 फरवरी को रांची से देवघर के लिए होंगे रवाना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत पांच दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम रांची पहुंचे। दौरे के पहले दिन कोई विशेष कार्यक्रम नहीं रखा गया है। 20 फरवरी की सुबह संघ प्रमुख रांची महानगर के स्वयंसेवकों एवं शहर के गणमान्य लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद झारखंड और बिहार के तीनों प्रांतों के अधिकारियों के साथ अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। इसमें पर्यावरण संरक्षण, ग्राम विकास, गो संवर्द्धन, सामाजिक समरसता तथा परिवार प्रबोधन विषय मुख्य हैं। वैसे देश एवं राज्य की वर्तमान स्थिति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। 23 फरवरी की शाम वह रांची से देवघर के लिए रवाना हो जाएंगे।

रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत कार्यवाह राकेश लाल ने कहा कि अपने संगठनात्मक कार्यों को गति देने के लिए सरसंघचालक पूरे देश का दौरा करते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। इसी दृष्टि से वह यहां पहुंचे हैं। 23 फरवरी तक वे रांची में रहकर अलग-अलग विषयों पर संघ प्रमुख संघ के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसमें पर्यावरण संरक्षण का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा चीन में कोरोना वायरस के रूप में दिख रहा है। संघ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर सालोंभर काम करता है। बैठक में इस कार्य में और तेजी लाने पर चर्चा होगी। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघसंचालक मोहन भागवत बुधवार को पांच दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे। वे इस दौरान कई विशिष्ट लोगों से मुलाकात करेंगे। प्रेट्र

राकेश लाल ने कहा कि बैठक में सामाजिक समरसता विषय पर भी चर्चा होगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण थी। बीच के काल खंड में उसे समाप्त करने की कोशिश की गई। उसे और मजबूत करने की जरूरत है। उसी तरह संयुक्त परिवार को कैसे बनाए रखा जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा।

जैविक खेती को बढ़ावा देने पर संघ कर रहा कार्य

राकेश लाल ने कहा कि संघ जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। आज रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। इसलिए जैविक खाद को बढ़ावा देने पर आरएसएस एवं अनुषांगिक संगठन काम कर रहा है। इसके लिए गौ पालन पर भी जोर दिया जा रहा है।

लोगों को गांव में ही मिले रोजगार

संघ का मानना है कि यदि लोगों को गांव में ही रोजगार मिले तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव मजबूत होगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लोग भी आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इस दिशा में संघ का प्रयास चल रहा। इस प्रेस वार्ता में प्रांत संघचालक सच्चिदानंद लाल अग्रवाल व सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार आजाद भी उपस्थित थे।

अंतर्कलह

विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर जोर आजमाइश तेज, पूर्व सीएम हरीश रावत व प्रीतम– इंदिरा खेमा है आमने–सामने

उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की जंग

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते कदमों के साथ ही कांग्रेस के भीतर जंग की सुगबुगाहट होने लगी है। आश्चर्यजनक ये है कि जंग बाहरी मोर्चे पर भाजपा के प्रचंड बहुमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में चुनाव में टिकट बंटवारे की भूमिका और इसके बहाने वर्चस्व कायम रखने की जोर-आजमाइश को माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होना भी तकरीबन तय माना जा रहा है। ऐसे में प्रदेश संगठन के साथ ही हाईकमान के लिए भी चुनावी जंग में पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती बढ़ना लगभग तय है।

प्रदेश में कांग्रेस के भीतर बहुध्रुवीय खींचतान के अब मुख्य रूप से दो खेमों में सिमटने के संकेत हैं। दोनों खेमे विधानसभा चुनाव से पहले निर्णायक स्थिति पाना चाहते हैं। इसमें एक मजबूत धड़े के नेता के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं तो दूसरे धड़े की कमान फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के हाथ में है।

हरीश रावत।

इंदिरा हृदयेश।

प्रीतम सिंह। सभी फाइल

इन दोनों ही खेमों के बीच तनातनी लंबे समय से बरकरार है। पार्टी पर रसूख कायम रखने की इस जंग ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह को अपनी कमेटी के गठित करने के लिए लंबा इंतजार कराया। हालांकि, इस बीच प्रदेश अध्यक्ष को ही बदले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर हल्ला भी मचता रहा। यह दीगर बात है कि पार्टी हाईकमान ने नई प्रदेश कमेटी पर मुहर लगाकर इस हल्ले पर ही विराम लगा दिया। अब पार्टी विधायक नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के खिलाफ लामबंद हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल नेता बदलने की मुहिम को धार देने की कोशिश क्या रंग लाती है, यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश संगठन और विधानमंडल दल पर दबाव लगातार बढ़ना तय है। इस बीच पार्टी के भीतर से ही यह मांग भी उठने लगी है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए अलग से चयन समिति बनाई जाए। दरअसल, टिकट बंटवारे में प्रदेश अध्यक्ष और नेता विधानमंडल दल, दोनों की ही अहम भूमिका होती है। टिकट बंटवारे मामले में दोनों अहम पद दूसरे खेमे के पास होने से भी पार्टी की अंदरूनी सियासत गरमाई हुई है।

रिटायर्ड अफसरों की नियुक्ति पर खेमका ने उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

सोशल मीडिया के जरिये सरकारी तंत्र पर चोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चर्चित आइएएस डॉ. अशोक खेमका ने अब मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी), मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी), लोकपाल और लोकायुक्तों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रिकॉर्ड तबादलों के चलते सुर्खियों में रहने वाले 1991 बैच के आइएएस ने ट्वीट किया कि इन संवैधानिक संस्थाओं से भ्रष्ट लोगों की कंपकंपी छूटनी चाहिए। इन संस्थाओं में सेवानिवृत्त लोगों को आसीन कर इन्हें दायित्वहीन क्यों किया जा रहा है।

54 तबादले झेल चुके खेमका ने ट्वीट में पूछा है कि कितने भ्रष्ट लोगों को दोषी ठहराया जाता है? कितने भ्रष्टाचारी छूट जाते हैं और कितने निर्दोषों को परेशान किया जाता है? खेमका ने यह ट्वीट ऐसे समय में किया है जब हरियाणा के 1978 बैच के रिटायर्ड आइएएस अफसर तथा राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को नया मुख्य सतर्कता आयुक्त और पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव बिमल जुल्का को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। खेमका पहले भी अनेक मुद्दों पर ट्वीट करते रहे हैं। पिछले दिनों खेमका ने भ्रष्टाचार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी तंज कसा था कि क्या ऐसे आयोजनों से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा।

अशोक खेमका फाइल

ट्वीट कर जड़ा सीवीसी, सीआइसी, लोकपाल–लोकायुक्तों को दायित्वहीन करने का आरोप

10.62 करोड़ टन गेहूं की पैदावार पहुंचने की संभावना है देश में 2019-20 में। फसल वर्ष 2018-19 में 10.36 करोड़ टन गेहूं का कीर्तिमान बना था। इस बार नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है।

36 घंटे में तीन शहरों का दौरा करेंगे ट्रंप

स्वागत की तैयारियां ▶ अहमदाबाद में ट्रंप दंपती का भव्य स्वागत होगा, आगरा और दिल्ली भी जाएंगे

मोदी और ट्रंप के सामने अहम रक्षा सौदों पर होंगे हस्ताक्षर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उनके स्वागत की जैसी तैयारी अहमदाबाद, आगरा और नई दिल्ली में की जा रही है। वैसा पूर्व में शायद ही किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए किया गया हो। भारत की पूरी कोशिश है कि ट्रंप दंपती हर लिहाज से भारत में बिताए 36 घंटे आजीवन याद रखें। ट्रंप इस यात्रा के दौरान सबसे पहले 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे, उसी दिन शाम को वह आगरा जाएंगे और आगरा से देर शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। यहां अगले दिन उनका राजकीय सम्मान होगा और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आधिकारिक वार्ता होगी। 25 फरवरी को ही देर रात वह अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे।

अहमदाबाद में ट्रंप के स्वागत की तैयारियां : अहमदाबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में सड़कों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं और फॉगिंग की जा रही है। एपी

गुजरात सरकार का कहना है कि अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के एयरफोर्स-वन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर 19 लोग शंख बजाकर उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करेंगे। इसके साथ ही 150 फीट चौड़े रेड कारपेट के दोनों ओर छह डांस ग्रुप पारंपरिक नृत्य करेंगे। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप व उनकी पत्नी मेलानिया का काफिला अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोटेरा में बनाये गए नए स्टेडियम तक का सफर करेगा। इस रास्ते में देश के 28 राज्यों के सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 28 मंचों का निर्माण किया गया है। इसे 'इंडिया रोड शो' का नाम दिया गया है। यही नहीं दोनों तरफ रास्ते में हजारों लोग उपस्थित होंगे। साथ ही रास्ते में जगह-जगह गांधी का दर्शन विभिन्न कला माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा। मोदी और ट्रंप मिल कर दुनिया के इस सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह वैसा ही आयोजन होगा जैसे ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था। स्टेडियम में एक लाख लोग उपस्थित होंगे जिन्हें दोनों नेता संबोधित करेंगे। यहां से ट्रंप व मेलानिया अपने दल के साथ आगरा जाएंगे और वहां एक घंटे तक ताजमहल का दीदार करेंगे। वहां का कार्यक्रम इस तरह से रखा गया है कि शाम के धुंधलके में ताजमहल में ट्रंप दंपती कुछ वक्त गुजार सकें। उसके बाद ट्रंप नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

दिल्ली में दो स्तर की वार्ता होगी : विदेश सचिव के मुताबिक नई दिल्ली में 25 फरवरी को मोदी और ट्रंप के बीच दो स्तरों पर बातचीत होगी। एक आधिकारिक स्तर की और दूसरी एकांत में। बातचीत काफी व्यापक होगी जिसमें सुरक्षा व रक्षा से लेकर कारोबार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वैश्विक हालात जैसे तमाम मुद्दे होंगे जो दोनो देशों के हितों को सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। दोपहर में ट्रंप की मुलाकात भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से होगी। देर शाम ट्रंप राष्ट्रपति भवन जाएंगे।

जयपुर एयरपोर्ट हो सकता है विकल्प : उसी रात वह अपने विशेष विमान से वापस अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के आइजीआइ एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर जयपुर हवाई अड्डे को भी तैयार रखा जा रहा है। अमेरिका वापस जाने के लिए जयपुर हवाई अड्डे को भी विकल्प के रूप में रखा गया है। ट्रंप अभी जबकि चुनाव की तैयारी में भी जुटे हैं और जबरदस्त राजनीतिक विरोध भी झेल रहे हैं, ऐसे में भारत आने का फैसला दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रिश्ते को बताता है।

संयुक्त बयान पर दुनिया की नजर : पिछले 20 वर्षों में पांचवी बार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत का आधिकारिक दौरा करेंगे जबकि उसके पहले के 50 वर्षों में सिर्फ तीन बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत का दौरा किया था। ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ अहम रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसमें एक समझौता भारतीय नौसेना के इस्तेमाल के लिए 24 अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की खरीद का भी होगा। भारत सरकार की रक्षा उत्पादों को खरीदने की उच्चस्तरीय समिति ने इसकी मंजूरी दे दी है। दोनों नेताओं की वार्ता के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान पर पूरी दुनिया की नजर होगी। खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देश किस तरह से आगे की रणनीति की तरफ इशारा करते हैं।

भारत को लेकर ट्रंप के बयान पर कांग्रेस ने जताया एतराज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

तीखे तेवर

- अतिथि के रूप में स्वागत पर उन्हें मेजबान की बेइज्जती का हक नहीं
- पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने विदेश मंत्रालय से मांगा जवाब
- ट्रंप क्या भगवान हैं, जो 70 लाख लोग अगवानी करें : अधीर रंजन

'भारत के साथ अब तक अमेरिका के उचित व्यवहार नहीं करने' पर कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर एतराज जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय से इसका उचित जवाब देने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि ट्रंप का बयान अपमानजनक है और उन्हें भारत की बेइज्जती का हक नहीं है।

भारत यात्रा को लेकर ट्रंप के ट्वीट किए वीडियो में दिए गए इस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि बेशक अतिथि देवो भवः की अपनी परंपरा के अनुरूप हम अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। मगर इसमें किसी को शक की गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि अतिथि को भारत की बेइज्जती का हक है। हम इसीलिए विदेश मंत्रालय से राष्ट्रपति ट्रंप की इस टिप्पणी का उचित जवाब दिए जाने की अपेक्षा करते हैं। तिवारी ने कहा कि भारत ने अमेरिका ही नहीं किसी भी देश या मेहमान का अनादर नहीं किया है और यह गलत बयान है।

ट्रंप की यात्रा के कूटनीतिक महत्व से जुड़े सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्तों के दौर की शुरुआत वाजपेयी सरकार के समय हुई। मनमोहन सिंह की संप्रग सरकार ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को नये आयाम तक पहुंचाया। जहां तक ट्रंप की प्रस्तावित भारत यात्रा का सवाल है तो खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसमें व्यापार समझौता नहीं होने की बात कह दी है। हालांकि कुछ हथियारों और हेलीकॉप्टर बेचने की ट्रंप की कोशिश फलीभूत होती दिख रही है क्योंकि भारत ने इन्हें खरीदने के अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। तिवारी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी वर्ष में हो रही डोनाल्ड ट्रंप की यह भारत यात्रा रणनीतिक नहीं बल्कि चलायमान है।

कांगेस ने कहा, ट्रंप यहां अपने हित साधन आ रहे हैं : इस बीच, एएनआइ की खबर के अनुसार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया है कि ट्रंप क्या भगवान हैं जो उनकी अगवानी के लिए 70 लाख लोगों को जुटाया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि ट्रंप यहां अपने हित साधन आ रहे हैं। वे भारत के साथ कोई व्यापारिक समझौता भी नहीं करेंगे। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। उन्हें अमेरिका के लिए धंधा करना है। वे कोई हम लोगों को खुश करने नहीं आ रहे हैं।

अभेद्य सुरक्षा, मानवरहित हमला रोकेगा डिफेंस सिस्टम

जागरण संवाददाता, आगरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन पर जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा घेरा रहेगा। पांच स्तरीय सुरक्षा घेरे में वह एयरपोर्ट से ताजमहल तक जाएंगे। रूट के आसपास ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे हवाई हमला भी कारगर न हो सके। अमेरिकी एडवांस टीम गहनता से जांच कर व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के 24 फरवरी के आगमन पर रूट पर पांच स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा। इसमें पहले घेरे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी रहेगी। तीन घेरों में एनएसजी और चेतक कमांडो सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। अंत के सुरक्षा घेरे में पुलिसकर्मी रहेंगे। जमीन की सुरक्षा पर मजबूती के साथ ही हवाई सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हवाई हमले की कोशिश अप्रभावी रहेगी। मानवरहित हवाई हमले को रोकने के लिए एंटी अनमैंड एरियल व्हीकल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिस्टम एनएसजी के पास है। गुरुवार को 20 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स यहां आ जाएगी। इसके बाद शहर में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।

स्कूलों में हुआ सत्यापन

अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन पर उनके स्वागत के लिए 26 हजार स्कूली छात्र-छात्राएं रूट पर खड़े होकर भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। इन सभी छात्र-छात्राओं और शिक्षकों का स्कूलों में जाकर पुलिस वेरीफिकेशन कर रही है।

बुलंदशहर से छोड़ा जा रहा यमुना में पानी : डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित आगरा आगमन को देखते हुए यमुना में पसरी गंदगी की सफाई के लिए आसपास के जिलों से गंगनहर के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। दरअसल, यमुना में पानी का बहाव कम है और गंदगी पसरी है। पानी का बहाव तेज करने के लिए बुलंदशहर और आसपास के अन्य जिलों को रोजाना 500-500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी गंगनहर के जरिए यमुना में पहुंचाने के आदेश हुए हैं। सिंचाई विभाग यमुना नदी में कोट एस्केप के जरिए 500 क्यूसेक पानी निरंतर उपलब्ध कराएगा। बुलंदशहर के डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि शासन से मिले आदेश के क्रम में सिंचाई विभाग को रोजाना 500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी गंग नहर के जरिए यमुना में पहुंचाने के आदेश दिए गए हैं।

अमेरिकी टीमों ने पांच घंटे की रूट की गहन पड़ताल

जागरण संवाददाता, आगरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन की तैयारियों का बुधवार को अमेरिकी टीमों ने उनके गुजरने वाले मार्ग पर पांच घंटे गहन जांच-पड़ताल की। टीमों ने पेड़ों से लेकर विद्युत पोल को भी जांचा। पोल पर लगाई गई नई एलईडी को उतारकर भी देखा।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी की दर्जनभर से अधिक टीमें आगरा में डेरा डाल चुकी हैं। बुधवार को एक टीम खेरिया एयरपोर्ट पहुंची। जहां सुरक्षा संबंधी जानकारी ली गई। दूसरी टीम ने एयरपोर्ट से लेकर होटल तक का निरीक्षण किया। तीसरी टीम ने होटल से ताजमहल तक का निरीक्षण किया। टीम के सदस्य कई चौराहों पर रुके। सदस्यों ने कई लोगों से बात भी की। इसके लिए अनुवादक की मदद भी ली गई। एक टीम ने इनर रिंग रोड, लखनऊ एक्सप्रेस वे का भी निरीक्षण किया। टीम ने कई फोटोग्राफ भी खींचे। उधर, मंडलायुक्त अनिल कुमार, डीएम प्रभु एन सिंह ने ताजमहल के आसपास सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया।

अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग : अमेरिकी टीम निर्धारित रूट की जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। पूरा डाटा एकत्रित कर उसका विश्लेषण किया जा रहा है।

जयपुर एयरपोर्ट विकल्प के रूप में तैयार : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 फरवरी की प्रस्तावित भारत यात्रा के समय दिल्ली का मौसम खराब रहने की स्थिति में जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में तैयार किया गया है। उनका विमान यदि दिल्ली में नहीं उतर सका तो जयपुर में उतारा जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में रामलीला से लेकर नौटंकी तक का इंतजाम

अमित दीक्षित, आगरा

- प्रदेशभर से आगरा आएंगे तीन हजार कलाकार
- 16 स्थलों पर आयोजित होंगे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम
- राधा-कृष्ण का स्वरूप धारण करेंगे पांच सौ कलाकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में उत्तर प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। काफिले के रास्ते में जगह-जगह खास कार्यक्रम होंगे। इसमें रामलीला से लेकर चरकुला और नौटंकी तक का इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेशभर से तीन हजार कलाकार बुलाए गए हैं।

खेरिया एयरपोर्ट से लेकर होटल अमर विलास और वहां से ताज पूर्वी गेट की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी मार्ग से गुजरेंगे। इस मार्ग पर 16 जगह बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मंच बनाकर आठ से दस कलाकार एक साथ प्रस्तुति देंगे। प्रदेशभर से बुलाए गए तीन हजार कलाकार 22 और 23 फरवरी को आगरा पहुंच जाएंगे। पांच सौ कलाकार राधा-कृष्ण का स्वरूप धारण कर रास रचाएंगे। एयरपोर्ट पर साढ़े तीन सौ कलाकार मयूर नृत्य प्रस्तुत करेंगे।

ये होंगे कार्यक्रम

ब्रज क्षेत्र : मयूर नृत्य, रसिया, चरकुला, बम रसिया, रासलीला, रामलीला, राधा-कृष्ण का स्वरूप। कुल कलाकार एक हजार।

बुंदेलखंड : नौटंकी, आल्हा, पाईडंडा। कुल कलाकार छह सौ।

पूर्वांचल क्षेत्र : कथक, रामलीला, स्टेज प्ले, धुनमुनिया कजरी। कुल कलाकार एक हजार

पश्चिम क्षेत्र : रागिनी, स्वांग, नौटंकी, गोजरी, घूमर। कुल कलाकार दो सौ।

अवध क्षेत्र : रामलीला, राम दरबार, फरुवाही, बहुरुपिया। कुल कलाकार एक हजार।

अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रस्तावित दौरा 24 फरवरी को है। उनके स्वागत में तीन हजार कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
-प्रभु एन. सिंह, डीएम

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

ट्रंप की अगवानी के लिए नहीं तोड़े गए ठेले

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें क्रेन की मदद से रेहड़ी-पटरी वालों के ठेले को नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात का है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अहमदाबाद में गरीबों के रोजगार के साधनों को तहस-नहस किया जा रहा है।

विश्वास न्यूज की जांच में यह दावा गलत निकला। जिस वीडियो को गुजरात का बताते हुए वायरल किया जा रहा है, वह ओडिशा के भुवनेश्वर का है। जब 20 जनवरी 2020 को भुवनेश्वर नगर निगम ने यूनिट 1 मार्केट में अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाते हुए फल विक्रेताओं के ठेले को जब्त करते हुए उसे क्रेन से नष्ट कर दिया था।

पड़ताल की प्रक्रिया : न्यूज सर्च में एक ट्वीट मिला, जिसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। ट्रंप की यात्रा से पहले गुजरात में झुग्गी-झोपड़ियों के सामने दीवार खड़ी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद नगर निगम सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क के किनारे झुग्गी के सामने एक दीवार का निर्माण कर रहा है। पड़ताल किए जाने तक इस वीडियो को करीब 4 हजार लोगों ने शेयर किया है और करीब 80,000 लोग इसे देख चुके हैं।

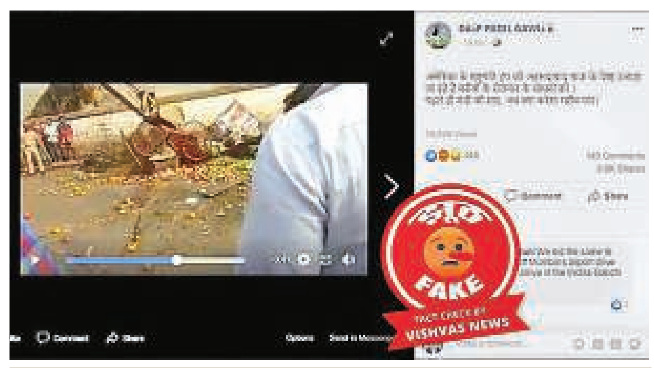

क्या है फेसबुक पोस्ट?

फेसबुक यूजर दिलीप पटेल गवली ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अहमदाबाद यात्रा के लिए उजाड़े जा रहे हैं गरीबों के रोजगार के साधन। पहले ही मंदी की मार, अब क्या करेगा गरीब यार।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें :
9205 270 923

मोटेरा स्टेडियम को मिली बिल्डिंग यूज परमिशन

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम को अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने बुधवार को बिल्डिंग यूज (बीयू) प्रमाणपत्र जारी कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इसका उद्घाटन करेंगे।

मोटेरा में करीब 63 एकड़ में 700 करोड़ रुपये की लागत से बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बीते दो-तीन माह से युद्धस्तर पर निर्माण और फिनिशिंग का काम चल रहा था। मनपा आयुक्त विजय नेहरा ने बताया कि स्टेडियम में 125 हाईड्रेंड प्वाइंट, नौ हजार स्प्रिंकलर, ड्रिंकिंग वाटर पाइप लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वर्षा जल भूगर्भ रिचार्ज सिस्टम बनाया गया है। इसकी बैठने की क्षमता दुनिया के सबसे बड़े मेलबोर्न स्टेडियम से भी अधिक 1.10 लाख की है। मनपा ने स्टेडियम के फायर सेफ्टी सिस्टम का भी बारीकी से निरीक्षण किया और बुधवार को बीयू परमिशन जारी कर दी। स्टेडियम में एक मुख्य मैदान के अलावा दो छोटे मैदान और 11 पिच बनी हैं। यहां पार्किंग में तीन हजार कारें और 10 हजार दोपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं।

उद्घाटन के लिए तैयार मोटेरा स्टेडियम : अहमदाबाद में सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। प्रेट्र

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यहां आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम में भी शिकरत करेंगे। पूरी यात्रा के कॉऑर्डिनेशन के लिए आइएएस और आइपीएस की 12 टीमें बनाई गई हैं जो विविध स्तर और स्थल पर यात्रा की मॉनिटरिंग करेंगी। वहीं स्वास्थ्य सेवा के लिए 17 एंबुलेंस भी तैनात रहेंगी।

एंटी ग्लेयर चश्मे न पहनें अधिकारी : गुजरात सरकार ने ट्रंप और मोदी की यात्रा को लेकर अपने अधिकारियों को प्रोटोकॉल के तहत दिशानिर्देश जारी किए हैं। आइएएस और आइपीएस अधिकारी इस दौरान एंटी ग्लेयर चश्मा, गोगल्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे। अफसर यात्रा के दौरान सादा चश्में पहन सकेंगे।

गरबा से होगा स्वागत

एयरपोर्ट से गांधी आश्रम और गांधी आश्रम से मोटेरा स्टेडियम तक सड़क के दोनों ओर महिला, पुरुष और बच्चे हाथ में भारत का तिरंगा और अमेरिकी ध्वज लहराकर ट्रंप और मोदी का स्वागत करते नजर आएंगे। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उप्र, झारखंड, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु सहित विविध राज्यों के 52 सांस्कृतिक समूह अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकलते ही पारंपरिक परिधानों में सजी-धजी युवतियां गरबा करते हुए ट्रंप का स्वागत करेंगी।

'हमेशा अलर्ट मोड में रहें स्टेशन कमांडर'

रखी बात

वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा, अलग-अलग श्रेणी में सर्वोत्तम रहने वाले स्टेशन किए गए सम्मानित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान मुख्यालय बमरौली में कमांडर सम्मेलन के दूसरे दिन बुधवार को वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने सभी स्टेशन कमांडरों को हर समय अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। भदौरिया ने एयरफोर्स स्टेशनों पर हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही हरियाली और स्वच्छता पर भी जोर दिया।

कमांडरों को संबोधित करने के बाद वह दिल्ली रवाना हो गए। बुधवार को सम्मेलन की अध्यक्षता मध्य वायु कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार ने की। इस सम्मेलन में मध्य वायु कमान परिक्षेत्र में आने वाले गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, वाराणसी, दरभंगा, बिहटा, भवाली, नागपुर एयरफोर्स स्टेशन के कमांडर शामिल हुए। गुरुवार को सम्मेलन का समापन होगा।

सम्मानित किए गए एयरफोर्स स्टेशन

वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। फाइल

कमांडर सम्मेलन के समानांतर क्षेत्रीय अफवा (एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन) की अध्यक्ष जया कुमार ने स्टेशन कमांडरों की पत्नियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्थानीय स्तर पर चलने वाली गतिविधियों की समीक्षा की और अलग-अलग कैटेगरी में सर्वोत्तम रहने वाले स्टेशनों को पुरस्कृत किया। वायु सेना स्टेशन बक्शी का तालाब को सर्वोत्तम मेडिकेयर और दंत केंद्र गोरखपुर को डेंटलकेयर की ट्रॉफी दी गई। वायु सेना स्टेशन भवाली को सर्वोत्तम चिकित्सा जांच कक्ष की ट्रॉफी दी गई। सर्वोत्तम प्ले स्कूल की ट्रॉफी गोरखपुर, सर्वोत्तम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ट्रॉफी वायु सेना विद्यालय बमरौली को, सर्वोत्तम प्री प्राइमरी स्कूल की ट्रॉफी वायु सेना विद्यालय दरभंगा को, दि बेस्ट अफवा एवं मोस्ट प्रोएक्टिव अफवा की ट्रॉफी नागपुर को और बेस्ट अफवा वेंचर की ट्रॉफी बरेली को दी गई।

कश्मीरी छात्रों से मारपीट पर कर्नाटक पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

हुबली, एएनआइ : कोर्ट परिसर में तीन कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट के मामले में कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हुबली जिले के विद्यानगर थाने में 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देशद्रोह के मामले में 17 फरवरी को जब एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के तीनों छात्रों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ कोर्ट परिसर में मारपीट कर दी थी। पुलिस ने इन्हें 15 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर पुलवामा हमले की पहली बरसी पर पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करने और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप है। ये छात्र केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली छात्रवृत्ति की मदद से हुबली के केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं।

एएमयू में फायरिंग, शासन ने तलब की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

- एमएम हॉल में दो गुटों में हुआ विवाद
- आरोपित छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए इंतजामिया से कहा

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के मोहसिन उल मुल्क (एमएम) हॉल में मंगलवार रात छात्रों के दो गुटों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। मामले में शासन ने इंतजामिया से रिपोर्ट तलब की है। प्रमुख सचिव गृह का हवाला देकर डीएम ने इस आशय का पत्र इंतजामिया को लिखा है। आरोपित छात्रों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी इंतजामिया से कहा है।

एएमयू स्थित एमएम हॉल के प्रोवोस्ट ने मंगलवार को हॉल की सीनियर पोस्ट पर छात्रों के नामों का एलान किया था। जिन छात्रों को पद नहीं मिले, उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। इसी बात पर उनका दूसरे छात्रों से विवाद हो गया, जिनके नाम सूची में थे। दोनों ही गुट गाजीपुर जिले के बताए जा रहे हैं।

प्रॉक्टर प्रो. एम वसीम अली ने बताया कि छात्रों के दो गुटों में हॉल की पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था। लेकिन मारपीट नहीं हुई है। एक पक्ष की ओर से फायर करने की भी सूचना मिली थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मामले की जांच की जा रही है। इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग की इस घटना को शासन व जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।

एएमयू में सीएए को लेकर 15 दिसंबर को हुए बवाल के बाद से प्रशासन नजर रखे हुए है। कई बार माहौल खराब करने के प्रयास भी हुए लेकिन प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को सफल नहीं होने दिया।

14,100 टन लिथियम का भंडार मिला है कर्नाटक के मंड्या में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के रिसर्चर्स को। मंड्या, बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है।

कश्मीरी पंडितों को रास नहीं आया केंद्र का गृह जिलों में बसाने का सुझाव

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- कश्मीर के दस जिलों में अलग-अलग नहीं, एक ही जगह पर बसना चाहते हैं पंडित
- कहा- सरकार द्वारा उनके पुश्तैनी मकानों में आकर बसाने की बातें सिर्फ दिखावा

केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों को घाटी के दस जिलों में बसाने का सुझाव रखा है, लेकिन कश्मीरी पंडित इससे खुश नहीं हैं। उन्हें केंद्र का यह सुझाव रास नहीं आ रहा है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें घाटी में एक ही जगह पर बसाया जाए। इस मांग को लेकर वह जल्द ही बैठक कर रणनीति बनाने वाले हैं।

तीन दशक पहले कश्मीर से पलायन कर आए कश्मीरी पंडित घाटी वापसी के तहत अपने-अपने जिलों में बसाने का सुझाव किसी भी शर्त पर मंजूर नहीं करेंगे। केंद्र का सुझाव सामने आने के बाद पनुन कश्मीर और समान विचारधारा वाले दलों ने होमलैंड की मांग बुलंद करने की मुहिम तेज करने के संकेत दिए हैं। इस दौरान प्रयास किया जाएगा कि केंद्र सरकार घाटी वापसी की योजना का स्वरूप तय करने से पहले पंडित समुदाय के प्रतिनिधियों को भी विश्वास में ले। पनुन कश्मीर के चेयरमैन डॉ. अग्निशेखर का कहना है कि पंडितों के बिना कश्मीर के अधूरा होने, उन्हें वहां पुश्तैनी मकान में आकर बसाने की बातें सिर्फ दिखावा हैं। पिछली सदी के अंतिम दशक में कश्मीर से निर्वासन, एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बीच धर्म के आधार पर हुआ। जब ऐसा हो रहा था तब कश्मीर में इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडितों को यह यकीन दिलाया गया कि कश्मीर मे उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में उनकी घाटी वापसी तभी संभव है तब वहां पर उन्हें अलग होमलैंड दिया जाए।

सतर्क हुए पंडित, पनुन कश्मीर की बैठक जल्द : मंगलवार को दिल्ली में कश्मीरी पंडित संगठनों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के दौरान पंडितों को घाटी में उनके पुराने जिलों में बसाने का जिक्र आया था। इससे कश्मीर में होमलैंड की मांग करने वाले कश्मीरी पंडित दल सचेत हो गए हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडित संगठनों ने आगे की रणनीति बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

होमलैंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा पनुन कश्मीर जल्द बैठक कर इस बारे में रणनीति की घोषणा करेगा। पनुन कश्मीर देश विदेश में अपनी मुहिम में कई बार स्पष्ट कर चुका है कि पंडितों को कश्मीर वापसी नहीं, वहां पर पुनर्वास चाहिए। यह तभी संभव होगा जब पंडितों को अलग-अलग नहीं, एक जगह पर साथ बसाया जाएगा।

दूसरी बार पलायन का जोखिम नहीं उठा सकते : डॉ. अग्निशेखर ने बताया कि घाटी वापसी पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए होमलैंड की मांग का समर्थन करने वाले कश्मीरी पंडितों के दल को विश्वास में लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यह तय है कि कश्मीर पंडितों की वापसी तभी संभव होगी जब उन्हें कश्मीर में एक ही जगह पर बसाया जाएगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कश्मीर पंडित समुदाय कश्मीर से दूसरी बार पलायन करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन में सिखों ने मांगीं दो आरक्षित सीटें

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित सीटों में से आठ रिफ्यूजियों को देने की आवाज भी उठी
- परिसीमन से भेदभाव खत्म होने की उम्मीद जगी

केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में प्रस्तावित परिसीमन आयोग के गठन की प्रक्रिया से सिख संगठन खुश हैं। हालांकि, वह चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उनके समुदाय के लिए दो सीटें आरक्षित की जाएं ताकि सिखों को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। यही नहीं, गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित सीटों में से आठ सीटें वहां से आए रिफ्यूजियों को देने की आवाज भी उठाई गई है।

शिरोमणि अकाली दल बादल के प्रदेश प्रधान जत्थेदार महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक में कहा गया कि केंद्र की इस कवायद से जम्मू वासियों की लंबित मांग पूरी होगी। राजनीतिक असंतुलन दूर होगा। राज्य में सिख समुदाय की आबादी एक जगह पर नहीं है। यह जम्मू और कश्मीर के कई जिलों में अधिक और कई जगहों पर कम है। इसलिए वे अपना प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में एक-एक सीट सिख समुदाय के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इससे वे विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेज पाएंगे। समुदाय की समस्याओं को उठाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों के लिए 24 सीटें निर्धारित की गई है। इसमें से आठ सीटों को गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों को दे देनी चाहिए।

वहीं, सिख नेता मंजीत सिंह ने प्रस्तावित परिसीमन आयोग पर कहा कि सिख समुदाय को आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समुदाय के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। परिसीमन से उन्होंने उम्मीद जताई कि अब कोई भेदभाव नहीं होगा। परिसीमन से हर क्षेत्र को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलेगा। नेशनल सिख फ्रंट के चेयरमैन वीरेंद्र जीत सिंह ने कहा कि परिसीमन आयोग के गठन से विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। इससे भेदभाव दूर होगा। हर क्षेत्र के साथ इंसाफ होगा। सिख समुदाय के लिए दो सीटें आरक्षित की जानी चाहिए।

न्यूज गैलरी

उप्र में कुपोषण से चार मौतों पर एनएचआरसी ने मांगा जवाब

बस्ती : कुछ वर्षों के भीतर कुपोषण से एक परिवार में चार मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जवाब मांगा है। उप्र के बस्ती जिला स्थित ओझागंज बाजार की रहने वाली मासूम विंध्यवासिनी के कुपोषित होने का शनिवार को कप्तानगंज सीएचसी में आयोजित सुपोषण मेला में पता चला था। पिता हरिश्चंद्र विंध्यवासिनी को लेकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वह गरीब हैं। परिवार में एक बेटा, दो बेटियां और पत्नी गीता पांडेय को गंभीर बीमारियों के चलते खो चुके हैं। अब विंध्यवासिनी को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सीएमओ जेपी त्रिपाठी ने बातचीत में स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस मिला है। जल्द ही जवाब भेजा जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी सावित्री देवी ने बताया कि सीडीपीओ कप्तानगंज से विंध्यवासिनी व उसके परिवार की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। विभाग में विंध्यवासिनी पंजीकृत है। उसको पोषाहार दिया जा रहा है। (जासं)

त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव को पुलिस हिरासत में भेजा गया

अगरतला : त्रिपुरा के पूर्व मुख्य सचिव यशपाल सिंह को कोर्ट ने चार दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। करोड़ों रुपये के पीडब्ल्यूडी घोटाले के मुख्य आरोपित पूर्व अधिकारी को सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था। ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जिला एवं सत्र कोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची दत्ता पुरकायस्थ ने सिंह को पुलिस हिरासत में भेज दिया। सरकारी वकील रतन दत्ता ने 10 की हिरासत की मांग की थी। महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) पुनीत रस्तोगी ने कहा कि पूर्व मुख्य सचिव करीब पांच महीने से गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे। त्रिपुरा पुलिस एक महीने से ज्यादा समय से छापेमारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आइआरएस अपार्टमेंट से सोमवार को सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुष्टि के लिए उन्हें इंदिरापुरम थाने लाया गया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनहें गिरफ्तार किया गया। 600 करोड़ से ज्यादा के पीडब्ल्यूडी घोटाले का मामला दर्ज होने के 128 दिनों बाद सिंह को गिरफ्तार किया जा सका। (प्रेट्र)

अगले महीने तक रद रहेंगी कई ट्रेनें

जम्मू : गत वर्ष दिसंबर में कोहरे के चलते भारतीय रेलवे ने जम्मू से चलने वाली कई रेलगाड़ियों को फरवरी माह तक रद कर दिया था। रेलवे ने अब नया आदेश जारी कर इन रेलगाड़ियों को मार्च तक रद करने की घोषणा की है। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू से हरिद्वार के बीच चलने वाली रेलगाड़ी संख्या 14606 जम्मू हरिद्वार एक्सप्रेस एक, 8, 15, 22 और 29 मार्च को रद रहेगी। वापसी में यह रेलगाड़ी संख्या 14605 हरिद्वार-जम्मू तवी एक्सप्रेस 2, 9, 16, 23 और 30 मार्च को भी नहीं चलेगी। (जासं)

त्राल में भीषण मुठभेड़, तीन कुख्यात आतंकी ढेर

कामयाबी ▶ मारे गए दहशतगर्दों में एक हिजबुल का जिला कमांडर

जिला कमांडर पर पांच लाख और अन्य दो पर था तीन-तीन लाख का इनाम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के अपने अभियान को जारी रखते हुए बुधवार तड़के सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर के त्राल में एक भीषण मुठभेड़ में तीन कुख्यात आतंकियों को मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी स्थानीय हैं। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर जहांगीर रफीक वानी और अंसार-गजवात-उल-हिंद का सद्दात अहमद ठोकर व राजा मकबूल है। मुठभेड़ में तीन आतंकियों की मौत के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे इलाके में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

दक्षिण कश्मीर के त्राल में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान मुस्तैद सुरक्षाकर्मी। इस मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए। जागरण

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार आधी रात के बाद अवंतीपोरा पुलिस को अपने तंत्र से पता चला कि त्राल के दीवर क्षेत्र में चार से पांच आतंकी अपने किसी संपर्क सूत्र से मिलने आए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस के विशेष अभियान दल ने सीआरपीएफ और सेना के आरआर के जवानों के साथ दीवर का रुख किया। सुरक्षाबलों ने घेराबंदी करने के बाद तड़के तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच, आतंकियों को सुरक्षाबलों की घेराबंदी की भनक लग गई। उन्होंने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी प्रहार किया। इस दौरान करीब एक घंटे चली मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए। पुलिस ने तीनों के शव और उनके पास पड़े हथियार व अन्य साजो सामान भी अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय सूत्रों की मानें तो मुठभेड़ में एक या दो आतंकी बच निकले हैं। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ तीन आतंकी थे और तीनों ही मारे गए हैं।

पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ में तीन आतंकियों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि जहांगीर रफीक वानी को इसी साल त्राल में हिजबुल कमांडर हमाद खान की मौत के बाद हिजबुल ने जिला कमांडर बनाया था। वह एक कुख्यात आतंकी था। उसने सुरक्षाबलों पर हमले की विभिन्न वारदातों को अंजाम देने के अलावा दो नागरिकों महराजदीन जरगर और गुलाम नबी मीर की हत्या भी की थी। उसके साथ मारे गए अन्य दो आतंकियों सद्दात व राजा ने भी सुरक्षाबलों पर हमले करने के अलावा कई अन्य विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम दिया था। मारे गए आतंकियों से दो पिस्तौल, ग्रेनेड और एक एसाल्ट राइफल भी मिली है।

तीनों आतंकियों पर घोषित था इनाम : सूत्रों के अनुसार, जहांगीर रफीक वानी जुलाई 2018 को आतंकी बना था। उस पर सुरक्षाबलों ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। वह अमीराबाद, त्राल का रहने वाला था। उसके साथ मारे गए राजा मकबूल और सद्दात क्रमशः त्राल और बिजबिहाड़ा के रहने वाला था। इन दोनों पर तीन-तीन लाख का इनाम था।

नामी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार : इस बीच, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक नामी ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) जुबैर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हथियार व अन्य आपत्तिजनक सामान मिला है। फिलहाल, उससे पूछताछ जारी है।

डीजीपी ने कहा, आखिरी सांसें ले रहा आतंकवाद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- इस साल सुरक्षाबलों ने 10 बड़े अभियानों में 23 आतंकी ढेर किए
- सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की फिर चेतावनी
- ट्रंप के प्रस्तावित दौरे के दौरान राज्य में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। आतंकी अब अपनी जान बचाते भाग रहे हैं। सुरक्षाबल उन पर पूरी तरह हावी हैं। इस साल हमने आतंकियों के खिलाफ 10 बड़े सफल अभियान संचालित किए हैं। इनमें 23 आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर में 19 और जम्मू में चार आतंकी मारे गए हैं। हम सुनियोजित तरीके से आतंकरोधी अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। किसी आतंकी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।

दक्षिण-कश्मीर के त्राल में बुधवार की सुबह सुरक्षाबलों द्वारा मुठभेड़ में तीन आतंकियों को मार गिराने के बाद पत्रकारों संग बातचीत में दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ ग्राउंड खुफिया नेटवर्क मजबूत हुआ है, आम लोग भी आतंकियों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली गर्मी में कश्मीर में स्थिति पूरी तरह शांत व सामान्य रहेगी। वहीं, उन्होंने हिंसा फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है।

आतंकियों को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ पूरे सुबूत : डीजीपी ने कहा कि वीपीएन एप के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों तक मदद पहुंचाने और उन्हें कुछ खास स्थानों पर हमले के निर्देश देने वाले तत्वों के खिलाफ पूरे सुबूत हैं। हम सोशल मीडिया के दुरुपयोग में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी निशानदेही कर रहे हैं। सभी को पता है कि राज्य प्रशासन ने 14 फरवरी को एक आदेश जारी कर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। इसके बावजूद बहुत से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस इन सभी के खिलाफ नहीं, बल्कि इसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

श्रीनगर में बुधवार को प्रेसवार्ता करते जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह। जागरण

आतंकी साजिश को नाकाम बनाने के पूरे प्रबंध : डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के प्रस्तावित भारत दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर में किसी आतंकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं।

पीडीपी के पूर्व विधायक पीरजादा पर लगा पीएसए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उपजिला एमएलए हॉस्टल अगले चंद दिन में बंद हो सकती है। उपजेल में अब पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पीरजादा मंसूर हुसैन और अवामी इत्तेहाद के बिलाल सुल्तान ही रह गए हैं। पीरजादा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत बंदी बनाने की सूचना है। हालांकि देर रात तक अधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। इसी बीच, प्रशासन पीएसए के तहत बंदी बनाए गए लोगों में से 55 को अगले एक माह रिहा करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पीरजादा पर पीएसए लगाया जाता है तो वह छह माह के दौरान इस कानून के तहत कैद होने वाले मुख्यधारा के नौवें वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के राजनीतिक सलाहकार रह चुके पीरजादा 2008 में दक्षिण कश्मीर में शांगस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। 2014 में वह चुनाव हार गए थे। उन्हें प्रशासन ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की घोषणा के मद्देनजर एहतियातन हिरासत में लिया गया था। उन्हें पहले शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआइसीसी) में रखा था और बाद में उपजेल एमएलए हॉस्टल में रखा गया था। नवंबर में जब एमएलए हॉस्टल को उपजेल का दर्जा दिया था तो इसमें 33 राजनीतिक नेताओं को हिरासत में रखा था। बाद में इनमें अधिकांश नेताओं को रिहा कर दिया या फिर पीएसए के तहत बंदी बनाकर अन्य जगहों पर भेजा गया। सूत्रों ने बताया कि प्रशासन ने मंगलवार रात को पीरजादा मंसूर हुसैन पर पीएसए के फैसले को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग और पुलिस ने पीरजादा मसूंर हुसैन को पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने पर पूरी चुप्पी साध रखी है।

चंपत राय को मिला मुकदमे की पैरवी का इनाम

जासं, बिजनौर

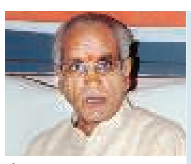

चंपत राय फाइल

संघ प्रचारक रहे, 1977 में इमरजेंसी के दौरान गए थे जेल

अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में महासचिव बनाए गए चंपत राय बंसल उप्र के बिजनौर स्थित नगीना के निवासी हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय सुप्रीम कोर्ट में चली राम मंदिर के मुकदमे की सुनवाई में विहिप की ओर से मुख्य पैरोकार एवं पक्षकार रहे। राम जन्मभूमि के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें प्रस्तुत करने में उनकी अहम भूमिका रही। माना जा रहा है कि उन्हें इसी मेहनत और लगन का इनाम मिला है।

नगीना के सरायमीर मोहल्ले में रामेश्वर प्रसाद बंसल के परिवार में 1946 में जन्मे चंपत राय बंसल बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। युवावस्था में ही आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। पढ़ाई में तेज-तर्रार रहे, लिहाजा धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए।

उनके चचेरे भाई हितेश बंसल बताते हैं कि 1977 में इमरजेंसी के दौरान पुलिस ने चंपतराय को कॉलेज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह करीब 18 माह प्रदेश की विभिन्न जेलों में रहे। जेल से छूटने के बाद वह घर नहीं लौटे। 1980 में विहिप में शामिल हुए। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के काफी नजदीकी रहे। राय की देखरेख में श्रीराम मंदिर आंदोलन भी चला। निचली कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई में विहिप की ओर से चंपत राय मुख्य पैरोकार एवं पक्षकार रहे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वह नियमित न्यायालय में मौजूद रहते थे।

यदा-कदा आते हैं नगीना

भाइयों में दूसरे नंबर के चंपत राय अविवाहित हैं। वह किसी खास कार्यक्रम में ही नगीना पहुंच पाते हैं। परिवार में सगे भाई लाजपत राय बंसल, सुनील कुमार बंसल, सुधीर बंसल व संजय बंसल हैं। इनके तीसरे नंबर के भाई माधव राय बंसल का निधन हो चुका है। उमेश कुमार बंसल, हितेश बंसल, राकेश कुमार, नरेश बंसल उनके चचेरे भाई हैं।

नगीना में जश्न का माहौल

बुधवार को जैसे ही चंपत राय को श्रीराम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में शामिल करने की खबर चली, नगीना के लोग झूम उठे। भाजपा और विहिप कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।

पहले दिन ही राम मंदिर निर्माण के लिए मिला लाखों का दान

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- ट्रस्ट की पहली बैठक में स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ ने पांच लाख का चेक सौंपा
- रामनवमी के दिन नहीं शुरू होगा श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य

अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में ही लाखों का दान मिला है। बुधवार को ट्रस्ट की पहली बैठक में ट्रस्टी उडुपी के पेजावर मठ के स्वामी विश्वप्रसन्नतीर्थ जी महाराज ने राम मंदिर निर्माण के लिए पांच लाख का चेक सौंपा। इसके अलावा पिछले दस दिनों में ट्रस्ट के आधिकारिक कार्यालय वरिष्ठ वकील व ट्रस्टी के. परासरन के घर मंदिर निर्माण के लिए दान के रूप में आए लाखों रुपये के चेक 10 से 15 चेक भी ट्रस्ट को सौंपे गए। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कुल कितने रुपये के चेक मिले हैं।

बैठक में ट्रस्टियों ने रामनवमी के दिन राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। रामनवमी के त्योहार और उस दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के अनुमान के आधार पर यह फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से उम्मीद लगाई जा रही थी कि रामनवमी के शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है।

इस संबंध में जब दैनिक जागरण ने चंपत राय से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस तिथि पर मुहूर्त की बात वही कर सकता है जिसे अयोध्या के बारे में जानकारी नहीं होगी। रामनवमी वहां का बहुत बड़ा पर्व है और उस दिन अयोध्या में कम से कम 15 से 20 लाख श्रद्धालु होते हैं। ऐसे में उस दिन वहां मंदिर निर्माण का मुहूर्त कार्य कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि तय की जाएगी। चंपत राय ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि अगली बैठक में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी उपस्थिति हों। बुधवार को ही उन्हें मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए वह ट्रस्ट की पहली बैठक में मौजूद नहीं थे। अगली बैठक में उनकी मौजूदगी में मंदिर निर्माण की तिथि तय करने पर विचार होगा।

बैठक में निर्मोही अखाड़ा के महंत और ट्रस्टी दिनेंद्र दास ने ट्रस्ट को एक पत्र सौंपा। इसमें महंत दिनेंद्र दास जी के अलावा अखाड़ा के सरपंच राजाराम चंद्राचार्य और पांच अन्य पंचों को भी ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर पूजा-पाठ, आरती व भोग का अधिकार निर्मोही अखाड़ा को देने की मांग भी की गई है। निर्मोही अखाड़ा लंबे समय से वहां पूजा अर्चना करता रहा है। हालांकि इस पत्र को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई।

2-3 मार्च को हो सकती है अगली बैठक

ट्रस्ट की अगली बैठक की तिथि तो अभी तय नहीं है, पर जल्द अगली बैठक की बात कही जा रही है। ऐसे में अगली बैठक 2 या 3 मार्च को होने की चर्चा तेज है।

तैयारी

अधिगृहीत परिसर के रामचरितमानस भवन की दक्षिण दिशा में स्थापित होगा वैकल्पिक गर्भगृह, लकड़ी के मौजूदा सिंहासन के विपरीत संगमरमर का बनाया जाएगा सिंहासन

मंदिर निर्माण तक फाइबर के गर्भगृह में विराजेंगे रामलला

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की उलटी गिनती के साथ ही वर्षों से टेंट में विराजमान रामलला के लिए फाइबर का वैकल्पिक गर्भगृह भी तैयार होगा। इसे अधिगृहीत परिसर स्थित रामचरितमानस भवन के दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों ने बुधवार तड़के रामलला के मौजूदा गर्भगृह और सिंहासन की नाप-जोख की। कवायद के पीछे कोशिश है कि जब तक भव्य मंदिर का निर्माण चले, रामलला के लिए अपेक्षित सुविधा-सहूलियत उपलब्ध होती रहे और पूजा-अर्चन में भी कोई व्यवधान न आए।

रामलला का मौजूदा गर्भगृह 35 गुना 25 फीट में है। जिस सिंहासन पर चारों भाइयों सहित रामलला विराजमान हैं, वह तकरीबन पांच गुना चार फीट का है। अब इसी माप के अनुरूप वैकल्पिक गर्भगृह बनेगा। यह पूरा परिक्षेत्र प्रस्तावित मंदिर के मुख्य ढांचे से अलग है।

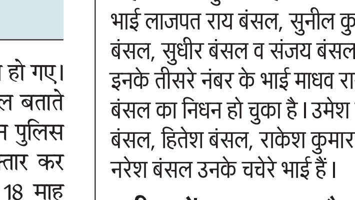

उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला। जागरण आर्काइव

वैकल्पिक गर्भगृह भी होगा खास : ढांचा ध्वंस के बाद रामलला करीब 27 वर्ष से टेंट में विराजमान हैं। लिहाजा, अब भव्य मंदिर से पहले उनका वैकल्पिक गर्भगृह भी खास होगा। इसे फाइबर से तैयार किया जाएगा। लकड़ी के मौजूदा सिंहासन के विपरीत वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला संगमरमर के सिंहासन पर विराजमान होंगे। रामलला के प्रधान अर्चक आचार्य सत्येंद्रदास ने वैकल्पिक गर्भगृह की माप लेने आए विशेषज्ञों से बात की। उन्होंने ही सुझाव दिया कि वर्तमान गर्भगृह जिस आकार का है, वैकल्पिक गर्भगृह उसी के अनुरूप रहे ताकि रामलला की पूजा-अर्चना में कोई दिक्कत न आए। तर्क दिया कि वैकल्पिक गर्भगृह में रामलला का साजो-सामान भी सहेजने की जरूरत होगी।

अयोध्या में खुलेगा ट्रस्ट का बैंक खाता

प्रथम पृष्ठ से आगे

बैठक में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का दायित्व गोविंद देव गिरि को सौंपा गया। ट्रस्ट का बैंक खाता अयोध्या में खोलने का निर्णय लिया गया, जिसका संचालन स्वामी गोविंद देव गिरि, चंपत राय व एक अन्य सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। दिल्ली की फर्म वी. शंकर अय्यर एंड कंपनी को ट्रस्ट का चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किया गया। बैठक में चर्चा की गई कि देशभर के श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर निर्माण होगा। हालांकि, पहली बैठक में मंदिर निर्माण के मुहूर्त पर फैसला अगली बैठक के लिए टाल दिया गया, जो अयोध्या में अगले माह होनी तय हुई है।

बिना बुलाए पहुंचे महंत धर्मदास : बैठक जारी रहने के बीच में निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास पहुंचे। हालांकि, वह ट्रस्ट के सदस्य नहीं है और न ही उन्हें आमंत्रित किया गया था, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ बैठक से अलग दूसरे कमरे में बैठाया गया। बैठक में 490 सालों से चले आ रहे राम जन्मभूमि विवाद के हल होने और इस मामले को सही तरीके से संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और उप्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके बाद देश की संवैधानिक संस्थाओं तथा न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास प्रकट किया गया।

चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था मॉडल : विहिप ने गुजरात के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा से राम मंदिर का मॉडल तैयार करवाया था। यह मॉडल भगवान विष्णु के पसंदीदा अष्टकोणीय आकार में है। नागर शैली में पूर्णतया पत्थरों से बनने वाले दो मंजिला मंदिर में पांच प्रखंड होंगे। सोमपुरा का परिवार अक्षरधाम जैसे प्रमुख मंदिरों की डिजाइन तैयार कर चुका है।

मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बनाकर मदद दे सरकार : शरद पवार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने सरकार पर लोगों को मजहब के हिसाब से बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है लेकिन, मस्जिद के लिए कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया, जबकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। पवार ने मस्जिद बनाने के लिए सरकार से ट्रस्ट बनाकर मदद देने की मांग की है।

एनसीपी अध्यक्ष अपनी पार्टी के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुधवार को लखनऊ में थे। यहां पवार ने उप्र के बजट पर चुटकी ली। बोले, इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है, जबकि बेरोजगारों को मासिक प्रशिक्षण भत्ता देने का प्रावधान किया गया है।

2018 में निपाह के प्रकोप के कारण केरल में पहले मरीज का इलाज करने वाली नर्स सहित 17 लोगों की जान गई थी। इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में राज्य प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा।

न्यूज गैलरी

स्वास्थ्य की जांच को मेदांता पहुंचे मुलायम

गुरुग्राम : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बुधवार को गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया गया। वह दोपहर एक बजे के करीब पहुंचे थे। शाम पांच बजे के करीब वह वापस दिल्ली चले गए। बताया जा रहा है कि कैंसर विशेषज्ञ डॉ. नीतिन सूद की देख-रेख में उनके स्वास्थ्य की जांच हुई। कई माह से डॉक्टर सूद ही पूर्व मुख्यमंत्री का इलाज कर रहे हैं। (जासं)

बंगाल के वीरभूम में मिले 100 देसी बम

कोलकाता : बंगाल के वीरभूम जिले के बोलपुर इलाके में स्थित एक गांव से बुधवार को बड़ी संख्या में देसी बम बरामद हुए हैं। ये बम पंचायत कार्यालय के सामने पड़े थे और कुछ दूरी पर तृणमूल कांग्रेस का भी स्थानीय पार्टी दफ्तर है और पास ही में बैंक की एक शाखा भी है। बोलपुर इलाके के सियान गांव के लोगों ने बताया कि में नानूर जाने के रास्ते में पंचायत कार्यालय के सामने मैदान में दर्जनों देसी बम पड़े हुए हैं। यही नहीं तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तार और पास ही में स्थित राष्ट्रीय बैंक के पास भी बुधवार की सुबह-सुबह कई बम पड़े हुए थे। बाद में बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस व बम निरोधी दस्ते ने वहां पड़े हुए 100 से अधिक बमों को उठा कर सुरक्षित स्थान पर ले गए, जिसे निष्क्रिय किया गया। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस तरह से वहां किसने और क्यों बम फेंके इसका पता लगाया जा रहा है। (राब्यू)

सिर पर पत्थर मार कर पत्नी की हत्या

गुरुग्राम : बिहार के नालंदा जिला के गांव काजूचक निवासी धर्मेंद्र ने चरित्र पर शक के चलते बुधवार सुबह अपनी पत्नी अनुपमा की हत्या कर दी। उसने अनुपमा के सिर पर पत्थर से कई वार किए। हत्या के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस केस दर्ज करने के बाद उसकी तलाश कर रही है। धर्मेंद्र पत्नी अनुपमा के साथ गांव नवादा फतेहपुर में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। वह एक कंपनी में श्रमिक था। दोनों के दो बच्चे हैं, लेकिन वे दादा-दादी के पास रहते हैं। पड़ोसियों के मुताबिक, धर्मेंद्र पत्नी के चरित्र पर शक करता था। इस बात को लेकर कलह रहती थी। मंगलवार रात पति-पत्नी में लड़ाई हुई और दोनों बगैर खाना खाए सो गए। सुबह दोनों में कहासुनी हो गई। अनुपमा ने अपने गांव जाने की धमकी दी तो धर्मेंद्र ने गुस्से में पास में ही पड़े पत्थर को उठा कर अनुपमा के सिर पर कई वार किए। जब अनुपमा अचेत होकर गिर गई तो वह भाग गया। शोरगुल सुनकर कुछ दूरी पर रहने वाले पड़ोसी पहुंचे तो अनुपमा की मौत हो चुकी थी। (जासं)

पूर्व डीआइजी को आठ साल व डीएसपी को चार साल कैद

न्याय ▸ मृतक परिवार के चार रिश्तेदारों को भी आठ-आठ साल की कैद

जागरण संवाददाता, अमृतसर

16 साल पहले 30 अक्टूबर, 2004 को पंजाब के चौक मोनी में घटित सामूहिक आत्महत्या प्रकरण में अदालत ने बुधवार को पूर्व डीआइजी कुलतार सिंह को आठ साल और गोइंदवाल साहिब के वर्तमान डीएसपी (तत्कालीन इंस्पेक्टर) हरदेव सिंह बोपाराय को चार साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह बाजवा की अदालत ने मरने वालों के परिवार के चार रिश्तेदारों ताया मोहिंदर सिंह, उसकी बहू सबरीन कौर, बेटी परमिंदर कौर और दामाद पलविंदर पाल सिंह को भी आठ-आठ साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी डीआइजी को 23 हजार रुपये, डीएसपी हरदेव सिंह को 20 हजार और चार सदस्यों को 17-17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने सोमवार को इन सभी को दोषी करार दिया था।

पूर्व डीआइजी कुलतार सिंह के वकील अमरपाल सिंह रंधावा और दोषी मोहिंदर सिंह के वकील कंवर मुबारक सिंह ने बताया कि वे अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। वे फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। उन्होंने बताया कि केस के कई पहलुओं पर सुनवाई नहीं हो पाई है।

सी डिवीजन थाना पुलिस ने सामूहिक आत्महत्या का मामला दर्ज करना था। तब इंस्पेक्टर हरदेव सिंह थाना प्रभारी थे। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो दीवारों पर कुलतार सिंह की सारी कहानी लिखी हुई थी। हरदेव सिंह ने कुलतार के आदेश पर दीवारों पर लिखा सुसाइड नोट मिटाने का प्रयास किया था, लेकिन ऐन मौके पर मीडिया ने पहुंच कर मामला उजागर कर दिया था।

अमृतसर में सामूहिक आत्महत्या प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व डीआइजी कुलतार सिंह को जेल ले जाती पुलिस। जागरण

क्या है मामला

- 30 अक्टूबर 2004 की रात चौक मोनी निवासी हरदीप सिंह ने पत्नी रोमी, मां जसवंत कौर, मासूम बेटे इमरत और सनमीत के साथ आत्महत्या कर ली।
- आत्महत्या करने से पहले हरदीप ने घर की दीवारों पर सारी कहानी लिखी। लिखा था कि वह तत्कालीन एसएसपी कुलतार सिंह से दुखी होकर सामूहिक आत्महत्या कांड को अंजाम दे रहा है।
- 11 अगस्त 2004 को झगड़े में हरदीप के हाथों पिता सुंदर सिंह की हत्या हो गई थी। ताया महिंदर सिंह और उसकी बहू सबरीन कौर ने उसे शव ठिकाने लगाते देख लिया था और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसकी बहन परमिंदर कौर व जीजा पलविंदर पाल सिंह ने भी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। चारों ने मिलकर कुल 13 लाख रुपये वसूल लिए थे।
- केस को कमजोर बनाने के लिए पूर्व डीआइजी कुलतार ने ली पांच लाख की रिश्वत।

बाइक पर पीछे बैठी महिला को हाथी ने खींच कर कुचला

जासं, बेतला (लातेहार) : झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व के पूर्वी छिपादोहर वन क्षेत्र के औंराझरिया जंगल में मंगलवार देर शाम जंगली हाथी ने अपने पति के साथ बाइक पर पीछे बैठी एक महिला सुषमा देवी को सूंड़ से खींचकर पैरों तले रौंद दिया। महिला के पति सतन यादव ने किसी तरह बच्चे के साथ भागकर जान बचाई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने केड़ मोड़ के पास बुधवार सुबह बेतला-महुआडांड़-नेतरहाट मुख्य मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीण पीटीआर के आला अधिकारियों को घटना स्थल पर बुलाने, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे।

सूचना मिलने पर छिपादोहर थाना से पुलिस टीम और वनकर्मी घटना स्थल पर रात में ही मौके पर पहुंचे और महिला के क्षत-विक्षत शव को थाना लेकर आए। शव को पोटली में बांध कर उठाना पड़ा।बरवाडीह एसडीपीओ अमरनाथ व छिपादोहर थाना प्रभारी फागुनी पासवान जाम स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकारियों ने सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा राशि दिलवाने के आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण पीटीआर के आला अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने व पीड़ित परिवार को 10 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे।

बस्तर में शुरू हुआ ऑपरेशन प्रहार, दो नक्सली ढेर

नईदुनिया, रायपुर

- मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक जवान भी घायल
- ऑपरेशन में एसटीएफ, डीआरजी के 1400 और सीआरपीएफ कोबरा के 450 जवान शामिल

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षाबलों की ओर से 2020 का पहला ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ कर दिया गया है। 18 फरवरी की शाम से शुरू ऑपरेशन में अब तक सुकमा और नारायणपुर में एक-एक नक्सली को मारने में सफलता मिली है। वहीं, चार नक्सलियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। इस अभियान के दौरान एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ है।

डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया कि यह अभियान तेलंगाना की सीमा से लेकर महाराष्ट्र की सीमा तक एक साथ चलाया जा रहा है। इसमें एसटीएफ एवं डीआरजी के लगभग 1400 जवान और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 450 जवान शामिल हैं। सुकमा जिले के टोंडामरका इलाके में एसटीएफ एवं डीआरजी के साथ हुई मुठभेड़ में एक नक्सली का शव, हथियार के साथ बरामद हुआ है। यहां चार घंटे तक मुठभेड़ चली। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि यहां सौ से अधिक वर्दीधारी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर चिंतागुफा और बुरकापाल कैंप से 600 से अधिक जवानों ने मंगलवार शाम ऑपरेशन लांच किया था। इलाके में अब भी सर्चिंग चल रही है। एसपी शलभ सिन्हा ने घायल नक्सलियों की संख्या आठ-नौ होने की उम्मीद की है। मृत नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है।

प्रतीकात्मक

हार्डकोर नक्सली नागेश कर रहा था नेतृत्व : एसपी शलभ ने बताया कि काली वर्दीधारी नक्सलियों का नेतृत्व हार्डकोर नक्सली नागेश कर रहा था। अंदेशा है कि नक्सली हिड़मा भी वहां मौजूद था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 20-25 किमी पैदल चलकर जवान तोंडामरका पहुंचे थे। वहीं, नारायणपुर जिले के पुसपाल इलाके में इकुल ग्राम के पास एसटीएफ एवं डीआरजी के साथ अन्य मुठभेड़ में एक माओवादी का शव बरामद हुआ है। कुछ माओवादियों के घायल होने की सूचना है।

मां बनने के लिए लड़की की उम्र पर शोध के लिए टास्क फोर्स गठित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : लड़के व लड़की के विवाह की एक समान न्यूनतम उम्र तय करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मां बनने के लिए लड़की की आयु पर शोध के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हाई कोर्ट को लोकसभा में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने लड़की के मां बनने की आयु पर चर्चा की थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि शारदा एक्ट-1929 में संशोधन करते हुए 1978 में लड़की की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई थी।

उन्होंने कहा था कि लड़की के मां बनने के पूरे मुद्दे को देखे जाने की जरूरत है और इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है, जोकि आगामी छह महीने में अपनी सिफारिशें पेश करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने केंद्र को इस मामले पर जवाब दाखिल करने का और समय स्वीकृत किया।

भोपाल गैस त्रासदी मामले का भगोड़ा नागपुर से गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी मामले में फरार एक दोषी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी रहे एसआइ कुरैशी को मंगलवार को पकड़ा गया। कुरैशी को 2010 में भोपाल की एक अदालत ने गैस त्रासदी मामले में दोषी ठहराया था।

सीबीआइ के प्रवक्ता के अनुसार कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोषियों ने सत्र अदालत, भोपाल में अपील दायर की थी। सीबीआइ ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और सजा बढ़ाने का आग्रह किया था। कुरैशी अपील के लंबित रहने के दौरान 2016 में फरार हो गया। प्रवक्ता ने कहा कि इस पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जिसे तामील कराने की जिम्मेदारी पहले मध्य प्रदेश पुलिस को दी गई।

उन्होंने बताया कि हालांकि राज्य पुलिस इसे तामील कराने में विफल रही, इसलिए सीबीआइ से आग्रह किया गया कि गैर

शिकंजा

- सीबीआइ ने कहा, यूनियन कार्बाइड का कर्मचारी रह चुका है

जमानती वारंट को वह तामील कराए। मध्य प्रदेश सरकार के आग्रह पर सीबीआइ ने 1984 में हुई इस त्रासदी की जांच की थी। भोपाल की एक अदालत ने सात जून 2010 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआइएल) के सात कर्मियों को घटना के संबंध में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन (यूसीसी) के अध्यक्ष वारेन एंडरसन मामले में प्रमुख आरोपित थे, लेकिन वह मुकदमे के दौरान पेश नहीं हुए। भोपाल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक फरवरी 1992 को एंडरसन को भगोड़ा घोषित कर दिया था। सितंबर 2014 में एंडरसन की मौत हो गई। ज्ञातव्य है कि कुछ लोगों का दावा है कि भोपाल गैस त्रासदी में 15000 से अधिक लोगों की जान गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने गैस से 3787 की पुष्टि की थी।

सट्टेबाज संजीव चावला को तिहाड़ में पिकनिक के लिए नहीं लाया गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दिया जवाब, फैसला सुरक्षित
- कहा, संजीव चावला के खिलाफ जांच को लेकर यूके कोर्ट में नहीं दिया कोई आश्वासन

भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच फिक्सिंग मामले में प्रत्यर्पण कर दिल्ली लाए गए देश के बड़े सट्टेबाजों में शामिल संजीव चावला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ को बताया कि चावला को तिहाड़ जेल में पिकनिक के लिए नहीं लाया गया है। उसे इस केस में जुटाए गए सुबूतों से सामना करने के लिए लाया गया है। कहा कि सरकार ने कभी भी यूके (यूनाइटेड किंगडम) की अदालत को यह आश्वासन नहीं दिया कि संजीव चावला से जुड़े मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने पीठ को बताया कि निष्पक्ष ट्रायल के लिए संजीव के खिलाफ जुटाए गए सुबूतों से सामना कराना पड़ेगा, ताकि षड्यंत्र का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल अन्य आरोपितों की पहचान की जा सके। 12 दिन की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली चावला की याचिका पर

संजीव चावला। (फाइल)

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिका पर गृह मंत्रालय की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि चावला तिहाड़ जेल में रहेंगे और जांच एजेंसी वहीं पर उनसे पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा कि अगर जांच के लिए चावला को जेल से बाहर ले जाने की जरूरत होगी तो अदालत से इसकी अनुमति ली जाएगी।

19 साल बाद लाया गया है भारत : फरवरी-मार्च 2000 में भारत में आयोजित हुई भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिक्रेट मैच सीरिज में हुई फिक्सिंग मामले में 19 साल बाद संजीव चावला को लंदन से प्रत्यर्पण पर दिल्ली लाया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए भी इस फिक्सिंग में शामिल थे और 2002 में निधन हो गया था।

14 को भेजा था तिहाड़ : 14 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने चावला को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से राहत देते हुए अगले आदेश तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था। 13 फरवरी को निचली अदालत ने मामले में पूछताछ के लिए संजीव चावला को 12 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया था। निचली अदालत के फैसले को संजीव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सुपरस्टार रजनीकांत के साथ 'मैन वर्सेज वाइल्ड' का मोशन पोस्टर जारी

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत डिस्कवरी चैनल के लोकप्रिय शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड' में नजर आएंगे। शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर शो का मोशन पोस्टर जारी किया। इस शो में नजर आने वाले रजनीकांत दूसरे भारतीय होंगे।

15 सेकेंड के मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए बेयर ग्रिल्स ने ट्वीट किया, 'जंगल में ब्रेयर ग्रिल्स मोशन पोस्टर के साथ रजनीकांत के ब्लॉकबस्टर टीवी डेब्यू के लिए तैयारी कर रहा हूं। मैंने दुनिया में कई स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन यह मेरे लिए सबसे खास है। लव इंडिया।' यह एपिसोड मार्च में प्रसारित होगा। अभी उसकी तारीख घोषित नहीं की गई है। गत जनवरी में रजनीकांत ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूटिंग की थी। इससे पहले पीएम मोदी इस शो में नजर आ चुके हैं। पिछले साल फरवरी में ग्रिल्स ने उत्तराखंड के जंगलों में पीएम मोदी के साथ इस शो के लिए शूटिंग की थी। पिछले साल 12 अगस्त को इस शो का प्रसारण हुआ था। बेयर ग्रिल्स अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई नामचीन हस्तियों के साथ यह शो कर चुके हैं।

डिस्कवरी चैनल ने अपने शो मैन वर्सेज वाइल्ड का मोशन पोस्टर जारी किया। इसमें शो के होस्ट बेयर ग्रिल्स (दाएं) व दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत हैं। ट्वटर

गैंगस्टर लकड़ावाला की बेटी को फिरौती मामले में क्लीन चिट

मुंबई, एएनआइ : मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला की बेटी शिफा शेख को फिरौती के एक मामले में क्लीनचिट दे दी है। हालांकि, उसके खिलाफ फर्जी तरीके से पासपोर्ट हासिल करने का मामला जारी रहेगा। पुलिस ने मामले की जांच के नतीजों और एजाज लकड़ावाला के बयान को क्लीन चिट का आधार बनाया है। मकोका के प्रावधानों के अनुसार आरोपित का एसपी के रैंक से ऊपर के एक अधिकारी के सामने दिया गया इकबालिया बयान कोर्ट में सुबूत के तौर पर मान्य है।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संतोष रस्तोगी ने कहा कि सब कुछ कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। गौरतलब है कि एक समय लकड़ावाला को अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता था। मुंबई पुलिस को फिरौती और हत्या के प्रयास सहित करीब 25 मामलों में उसकी तलाश थी। पिछले साल एक बिल्डर ने लकड़ावाला के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंप फिरौती मांगने का आरोप लगाया था।

विमान का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली से सऊदी अरब के जेद्दा जा रहे यात्रियों के समूह में से एक ने उड़ान भरने के लिए तैयार इंडिगो के विमान का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश की। नियम के खिलाफ इस आचरण को गंभीरता से लेते हुए एयरलाइन ने आरोपित समेत पांच यात्रियों के समूह को विमान से उतार दिया। आरोपित अपने उन दो साथियों को विमान में लेने की मांग कर रहा था, जिन्हें बोर्डिंग पास गुम होने के कारण रोक दिया गया था। मंगलवार को हुई इस घटना के कारण पायलट को विमान टैक्सी-वे से वापस पार्किंग-बे में लाना पड़ा। इस क्रम में फ्लाइट ने दिल्ली हवाईअड्डे से करीब तीन घंटे की देर से उड़ान भरी।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, 'इंडिगो के ए321नियो विमान से 110 यात्रियों का एक समूह यात्रा कर रहा था। समूह ने अपनी यात्रा की शुरुआत श्रीनगर से की थी और यह उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। इनमें से दो यात्रियों को दिल्ली में बोर्डिंग गेट के पास ही रोक दिया गया, क्योंकि उनके बोर्डिंग पास गुम हो गए थे।'

- एयरलाइन ने आरोपित समेत पांच यात्रियों को विमान से उतारा
- श्रीनगर से दिल्ली होते हुए जेद्दा जा रहा था 110 यात्रियों का समूह

उन्होंने बताया, 'विमान टैक्सी-वे से उड़ान भरने के लिए तैयार था कि समूह के नेता ने बोर्डिंग गेट पर रोके गए साथियों को भी विमान में लेने की मांग शुरू कर दी। चालक दल के सदस्यों ने उसे रोका और सीट पर बैठे रहने को कहा। लेकिन, वह चिल्लाने और विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा।'

इसके बाद कैप्टन ने विमान को टैक्सी-वे से वापस पार्किंग-बे में ले जाने का फैसला किया। टैक्सी-वे वह स्थान है, जहां विमान को पार्किंग-बे से उड़ान भरने के लिए लाया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि समूह के नेता के साथ-साथ तीन महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति को भी विमान से उतार दिया गया। इंडिगो ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकार को भेज दी गई है।

प्रोमो में दिखाया गाना फिल्म में नहीं किया शामिल, देना होगा हर्जाना

नई दिल्ली, प्रेट्र : शाह रुख खान अभिनीत फिल्म 'फैन' के प्रोमो में दिखाए गए गाने को रिलीज की गई फिल्म में शामिल नहीं करने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने फिल्म निर्माता कंपनी यशराज फिल्म्स को 10 हजार रुपये हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद निवासी शिक्षिका आफरीन फातिमा जैदी ने याचिका में कहा, उन्हें यह देखकर निराश हुई कि प्रोमो में दिखाए जाने के बावजूद 'जबरा फैन' गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। एनसीडीआरसी ने इसे अनुचित व्यापार पद्धति मानते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने प्रोमो में दिखाए गए गाने के आधार पर फिल्म को देखने का फैसला किया उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया होगा। आयोग ने यशराज फिल्म्स की उस दलील को खारिज कर दिया कि फिल्म के निर्माता और अभिनेता ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी कि उक्त गाना फिल्म का हिस्सा नहीं होगा। आयोग ने कहा कि जरूरी नहीं कि जिसने प्रोमो देखा हो उसने वह साक्षात्कार भी देखा हो।

भाजपा विधायक सहित सात पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा

जागरण संवाददाता, भदोही

उत्तर प्रदेश स्थित भदोही के भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य सचिन त्रिपाठी सहित उनके पुत्र दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी, नीतेश, भतीजे संदीप त्रिपाठी व चंद्रभूषण तिवारी पर भदोही कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोप में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही तीन सदस्यीय टीम गठित कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

वाराणसी की एक महिला ने 10 जनवरी को एसपी से शिकायत कर आरोप लगाया था कि 2014 से ही विधायक का भतीजा संदीप उसे शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती करता रहा। इस दौरान गर्भपात भी कराया। मई 2017 में भदोही विधानसभा चुनाव के समय भदोही स्थित होटल में विधायक सहित सभी ने दुष्कर्म किया।

- वाराणसी की महिला ने एसपी से की थी शिकायत, गर्भपात कराने का भी आरोप

> प्रथमदृष्टया मामला सही पाते हुए सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना करने के लिए भदोही कोतवाली में टीम गठित कर दी गई है।
> – रामबदन सिंह, पुलिस अधीक्षक

इसकी शिकायत भी वह संदीप से करती रही लेकिन वह मामले को नजरअंदाज करते रहे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौ फरवरी 2020 को जब उसने शादी करने को कहा तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। एसपी ने मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा को सौंपी थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

शाहीन बाग में कभी तालियों तो कभी विरोध के बीच हुई वार्ता

गौरव बाजपेई, नई दिल्ली

शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बात करने लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकारों को धरना स्थल पर कभी तालियां मिलीं तो कभी विरोध का भी सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पहल का ताली बजाकर स्वागत किया, लेकिन जब वार्ताकारों ने कहा कि वह मीडियाकर्मियों के सामने बात नहीं करेंगे तो इस पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। हालांकि वार्ताकार संजय हेगड़े ने कहा कि वह मीडिया को अपनी बातचीत की जानकारी बाद में साझा करेंगे जिसके बाद लोग शांत हुए।

शाहीन बाग में लोगों से बात करने के लिए पहुंचे वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़कर सुनाया, साथ ही उन्हें उसका अर्थ भी समझाया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बताया कि वह किस हैसियत से बात करने के लिए पहुंचे हैं। इस पर प्रदर्शनकारियों ने उनका तालियों के साथ स्वागत किया। वरिष्ठ वकील साधना रामचंद्रन ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम यहां आप लोगों से बात करने आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों की बातें सुनीं। प्रेट्र

प्रदर्शनकारी बोले-हमने नहीं, पुलिस ने बंद की है सड़क : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने जब कहा कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क को बंद कर रखा है तो वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि हम सड़क पर केवल 150 मीटर के हिस्से पर बैठे है। जबकि सड़क को तीन तरफ से पुलिस ने बंद किया हुआ है। ऐसे में सड़क बंद होने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है।

सरकार क्यों नहीं कर रही प्रदर्शनकारियों से बात : प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकारों से पूछा कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बात क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट ने उनको बातचीत के लिए क्यों भेजा है। इस पर साधना रामचंद्रन ने कहा कि इस बात का जवाब सरकार से ही मांगें।

हजारों लोग करना चाहते हैं बात : सुप्रीम कोर्ट द्वारा वार्ताकार नियुक्त होने के बाद से प्रदर्शनकारी खुश हैं कि उनकी बात सुनने के लिए कोई आ रहा है, लेकिन वार्ताकारों के पहुंचने पर सभी लोग उनसे बात करने के लिए उमड़ पड़े। ऐसे में हजारों लोगों से बात करना संभव नहीं था। जिसके चलते बिना किसी ठोस बातचीत के वार्ताकार गुरुवार को दोबारा आने की बात कह कर निकल गए।

साधना रामचंद्रन ने हालांकि यह बात कही कि वह किसी फैसले के लिए यहां नहीं आई हैं। वह सिर्फ लोगों से बात करने और उनकी बात कोर्ट को बताने के लिए धरनास्थल पर आई हैं।

67 दिनों से चल रहा प्रदर्शन

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

शाहीन बाग में पिछले 67 दिनों से सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिसके कारण दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला कालिंदी कुंज मार्ग पूरी तरह से बंद है। इसे खुलवाने को लेकर आस-पास के लोगों ने पहले विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मार्ग न खुलने पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में दखल देने की अपील की थी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के नेतृत्व में साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को वार्ताकार नियुक्त किया।

दैनिक जागरण
प्रकृति ईश्वर से एकाकार कराने वाला माध्यम है

नई शिक्षा नीति की प्रतीक्षा

प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता यह उम्मीद जगाती है कि यह नीति जल्द सामने आएगी। ऐसा होना समय की मांग भी है, क्योंकि वायदे के अनुसार नई शिक्षा नीति मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही आ जानी चाहिए थी। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि देर से आ रही शिक्षा नीति दुरुस्त भी हो। वास्तव में आवश्यक केवल यह नहीं है कि नई शिक्षा नीति यथाशीघ्र सामने आए, बल्कि यह भी है कि ऐसी तैयारी की जाए जिससे उस पर अमल का काम तेजी के साथ हो सके। नई शिक्षा नीति से अपेक्षाएं इसलिए बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि एक तो वह तीन दशक बाद आ रही है और दूसरे, हर कोई शिक्षा के ढांचे में व्यापक बदलाव के लिए प्रतीक्षारत है। यह बदलाव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर तो अपेक्षित है ही, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के स्तर पर भी है। यह ठीक नहीं कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में रटने और ज्यादा से ज्यादा अंक लाने पर जोर है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य अधिक अंकों से परीक्षा पास करना भर रह गया है। इसका कोई औचित्य नहीं कि शिक्षा परीक्षा का पर्याय बनकर रह जाए। शिक्षा तो वह है जो छात्रों में जानने एवं सीखने की सामर्थ्य बढ़ाए और बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करे। दुर्भाग्य से यह काम हमारी उच्च शिक्षा भी नहीं कर पा रही है।

हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय येन-केन-प्रकारेण डिग्री हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। इससे भी खराब बात यह है कि उनमें पठन-पाठन का माहौल दिन-प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा के केंद्रों से ऐसे युवा अधिक निकल रहे हैं जो समाज एंव राष्ट्र निर्माण में अपेक्षित सहयोग दे पाने में असमर्थ हैं। इसी कारण उद्योग-व्यापार जगत से संबंधित संगठन एक अर्से से यह कह रहे हैं कि उन्हें जैसे युवाओं की जरूरत है वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति का मूल कारण है अप्रासंगिक-अनुपयोगी पाठ्यक्रम और स्तरहीन शोध। उच्च शिक्षा केंद्रों में हो रहे शोध के स्तर में केवल सुधार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी होना चाहिए। अभी तो ऐसा लगता है कि शोध के नाम पर केवल खानापूरी हो रही है। स्तरहीन शोध केवल शिक्षा व्यवस्था के साथ ही नहीं, एक तरह से समाज और देश के साथ किया जाने वाला छल हैं। इसे देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि नई शिक्षा नीति में ऐसे उपाय हों जो शैक्षिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव ला सकें।

फर्जी नियुक्ति पत्र

बेरोजगारी का ही यह आलम है कि लोग सही व गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि बेरोजगार लूट के भी शिकार हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि शातिर बड़ी चालाकी से हरकतों को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को किसी तरह का शक भी नहीं हो रहा है। ताजा मामला शिमला स्थिति हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) में आया है। यहां चंबा निवासी चार युवा नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइनिंग के लिए पहुंचे। तीन युवा पैरामेडिकल स्टाफ व युवती नर्स के पद के लिए आई थी। जब वे नियुक्ति के लिए पहुंचे तो पाया कि सभी नियुक्ति पत्र फर्जी हैं। ये नियुक्ति पत्र इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा और मेडिकल कॉलेज चंबा के प्रिंसिपल के नाम से जारी किए गए थे। इन पर डिप्टी एमएस की मुहर भी लगी थी। फर्जी ज्वानिंग लैटर होने पर आइजीएमसी प्रशासन ने पुलिस को भी सूचित कर दिया है। शिमला पुलिस ने मामला चंबा पुलिस को जांच के लिए भेज दिया है। अब इस मामले की जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसने बड़ी ही होशियारी से पत्र तैयार किए हैं और इन लोगों से ठगी की। प्रदेश में इससे पहले भी नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी के मामले सामने आए हैं। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय वित राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यालय में भी नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी के आरोपित पकड़े थे। लोगों को समझना चाहिए कि नौकरी के नाम पर किसी की बातों में न आएं। यदि कोई नौकरी से संबंधित पत्र आता है तो संबंधित विभाग में जानकारी अवश्य ली जानी चाहिए। सरकार की ओर से सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही किसी को ज्वाइनिंग लैटर जारी किया जाता है। अगर कोई नौकरी दिलाने का झांसा देता है तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए ताकि कोई गरीब व्यक्ति इनकी ठगी का शिकार न हो।

बेरोजगारी की समस्या बेशक गंभीर है, पर नौकरी के लिए गलत राह पर चलना भी सही नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि नौकरी के नाम पर किसी की बातों में न आएं

दोधारी तलवार है मुफ्त का अर्थशास्त्र

प्रदीप सिंह

कोई सरकार मुफ्त में क्या और कितना दे सकती है, यह इससे तय होना चाहिए कि उसके पास अतिरिक्त पैसे हैं या नहीं?

अवधेश राजपूत

आमतौर पर लोगों को जीतने वाले में कोई कमी नजर नहीं आती और हारने वाले में शायद ही कोई खूबी दिखती हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत का असर यह है कि देश भर में विकास के दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। नेता जब विकास के मॉडल की बात करते हैं तो उनका आशय अपनी पार्टी के विकास से होता है यानी विकास वह जो चुनाव में जीत दिलाए। 15 साल लगातार दिल्ली का विकास करके शीला दीक्षित आखिर में हार गईं। पांच साल मुफ्त के अर्थशास्त्र से अरविंद केजरीवाल जीत गए। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की एक किताब है 'देअर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच'। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इसका भुगतान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों करना ही पड़ता है। मुफ्त कही जाने वाली चीजों का भुगतान भी जनता के टैक्स के पैसे से ही करना पड़ता है। यह टैक्स केवल अमीर ही नहीं गरीब भी देते हैं। इस पर अर्थशास्त्रियों में कोई मतभेद नहीं है कि मुफ्त या सस्ती शिक्षा और इलाज से केवल उस व्यक्ति को ही नहीं पूरे समाज का फायदा होता है।

कोई भी सरकार मुफ्त में क्या और कितना दे सकती है, यह इससे तय होना चाहिए कि सरकार के पास इस मद में खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसे हैं या नहीं? केजरीवाल सरकार के पास अतिरिक्त धन था। इसलिए उनके बजट घाटे पर इसका असर नहीं पड़ा। दिल्ली सरकार का कर्ज जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा उसकी आमदनी बढ़ी है, पर यही काम बंगाल की सरकार नहीं कर सकती या कहें कि उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही कर्ज के बोझ से दबी हुई है। इसलिए एक ही दवा सबके मर्ज का इलाज नहीं हो सकती।

मुफ्त की राजनीति की आर्थिक और सियासी कीमत भविष्य में चुकानी ही पड़ती है। कभी राज्य सरकारों में किसानों को मुफ्त बिजली देने की होड़ लगी थी। नतीजा यह हुआ कि राज्यों के बिजली बोर्ड दिवालिया हो गए। न बिजली रह गई और न बिजली खरीदने के लिए पैसा। इसलिए जिन मुख्यमंत्रियों को लग रहा कि चुनाव जीतने का फार्मूला हाथ लग गया उन्हें थोड़ा ठहरकर विचार करना चाहिए कि केजरीवाल के सामने क्या मुश्किलें आने वाली हैं? मुफ्त बिजली-पानी केवल गरीबों को नहीं, बल्कि अमीरों को भी मिल रहा है। इससे सरकार का अधिशेष कोष घट रहा है।

पिछले पांच साल में केजरीवाल सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 2013 के बाद से दिल्ली शीला दीक्षित के बनवाए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ही चल रही है। इस बीच न तो नए स्कूल, कॉलेज बने हैं न कोई अस्पताल। केजरीवाल सरकार ने न तो कोई फ्लाइओवर बनवाया, न कोई सड़क। डीटीसी का घाटा बढ़ता जा रहा है। तिस पर महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त हो गई। पांच साल में सरकार ने नई बसों की खरीदारी नहीं की। इतना कुछ मुफ्त देने के बाद भी केजरीवाल को चुनाव जीतने के लिए हनुमान जी की शरण में जाना पड़ा। अब पार्टी सुंदर कांड के पाठ का भी आयोजन करवाएगी।

जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बहुत जरूरी होता है। मुफ्त का अर्थशास्त्र दोधारी तलवार है। यह यदि समाज के गरीब तबके को मिले तो उसका उस वर्ग को ही नहीं पूरे सामाजिक वातावरण पर असर पड़ता है। यह समाज में आपसी वैमनस्य को रोकता है। गरीब व्यक्ति को लगता है कि सरकार उसके बारे में भी सोचती है। इससे अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई से उत्पन्न होने वाले आक्रोश का कुछ हद तक शमन होता है। दूसरा पक्ष यह है कि इससे अपेक्षा बढ़ जाती है। एक समय बाद लाभार्थी के जीवन की यह सामान्य घटना हो जाती है यानी न्यू नॉर्मल बन जाता है। उसे अपेक्षा होती है कि अब कुछ और मिलना चाहिए।

आम आदमी पार्टी और अन्य भाजपा विरोधी दल कहते हैं कि मोदी सरकार भी तो मुफ्त देती है। दो फर्क हैं। उज्ज्वला, शौचालय, पीएम आवास, बिजली कनेक्शन और इसी तरह की दूसरी योजनाओं में से कोई भी योजना लगातार या महीने दर महीने कुछ भी मुफ्त नहीं देती। एक बार सब्सिडी मिलती है। बाकी लोगों को अपना पैसा लगाना पड़ता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। उज्ज्वला की ही बात करें तो आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को सिर्फ गैस का कनेक्शन मुफ्त मिला। अब वे गैस सिलिंडर खुद भरवा रहे हैं। इससे उसी अनुपात में सिलिंडरों का उत्पादन, रसोई गैस की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना है। इससे लोगों को रोजगार मिला है। रसोई गैस के इस्तेमाल से गरीब तबके के लोगों में सशक्तीकरण का भाव आता है और लकड़ी एवं कोयले के धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिलती है तो उस पर होने वाला खर्च भी बचता है।

किसानों को साल में छह हजार रुपये की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को 'यूनिवर्सल बेसिक पे' की दिशा में पहला कदम मानना चाहिए। सरकार इसे लागू इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि उसका खजाना इसकी इजाजत नहीं दे रहा। दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि लोगों के हाथ में सीधे नकद राशि देने से उपभोग पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए सब्सिडी के जरिये सामान सस्ता देने के बजाय सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में देने को बेहतर माना जाता है। केंद्र सरकार कई जिंसों के लिए ऐसा कर चुकी है। अब उर्वरक सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे भेजने की तैयारी है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बुनियादी ढांचे के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार इसीलिए अगले पांच साल में इस मद में एक सौ तीन लाख करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है।

दिल्ली की बात करें तो शीला दीक्षित ने 15 साल में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया वह सिर्फ आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, भविष्य के बारे में सोचकर किया। वह भी अब मरम्मत और इजाफा मांग रहा है। आप सरकार के लिए अगले पांच साल बीते पांच साल से ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। जो दल दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद यूरेका-यूरेका कहकर खुश रहे हैं और यह मान रहे कि उन्हें जीत का फार्मूला मिल गया वे जरा दूध को ठंडा करके पिएं। चुनाव किसी एक योजना से नहीं जीते जाते। मुफ्त लैपटॉप, समाजवादी पेंशन जैसी सौगातें बांटने के बाद भी अखिलेश यादव का काम नहीं बोला। शीला दीक्षित का भी नहीं बोला था, पर केजरीवाल का बोल गया।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कृषि उत्थान में चाहिए राज्यों का सहयोग

मधुरेंद्र सिन्हा

कुछ राज्यों ने अभी तक पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों की पूरी सूची तक नहीं बनाई है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कुल 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसके लिए कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय को कुल 1,42,761 करोड़ रुपये की राशि दी गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक राशि 75,000 करोड़ रुपये पीएम किसान निधि योजना के लिए दी गई है। इसके बाद नंबर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जिसके लिए इस बार 15,695 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वहीं रासायनिक उर्वरक वगैरह के लिए कुल राशि में 9,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की कमी की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कृषि को तकनीक प्रधान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। भारत में कृषि और कटाई के काम अधिकांशतः मानव श्रम आधारित हैं। देश में श्रम की बढ़ती लागत यानी बढ़ती मजदूरी और समय पर श्रमिकों के नहीं मिलने की समस्या के मद्देनजर यह एक महत्वपूर्ण आवंटन है। किसानों के लिए भी यह जरूरी होता जा रहा है कि वे अपनी लागत कम करें। इसका सीधा तरीका है कि कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। हालांकि पूरे देश को देखते हुए यह राशि छोटी लगती है, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। वित्त मंत्री ने कृषि अनुसंधान के लिए भी 8,362 करोड़ रुपये की राशि दी है जो पहले से कहीं अधिक है। कृषि में अनुसंधान की सफलता के कारण ही भारत आज अनाज उत्पादन के मामले में दुनिया के पांच शीर्ष देशों में है। इसी कारण आज भी देश की कुल कामगार आबादी का 50 प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है। सरकार ने खेती पर से कामगारों की निर्भरता कम करने के लिए पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन वगैरह को बढ़ावा देना शुरू किया है। इस बजट में उनके लिए आवंटन बढ़ाकर 3,289 करोड़ रुपये किया है। इससे इन क्षेत्रों में तरक्की होगी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। केंद्रीय बजट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह साफ है कि राशि में बढ़ोतरी वैज्ञानिक ढंग से हुई है और कुछ क्षेत्रों को सरकार ने वरीयता दी है।

सवाल है कि क्या बड़े बजट से ही इस देश के किसानों का भला होगा? नहीं। किसानों की मदद केवल बजट में बहुत बड़ी राशि आवंटित करने से ही नहीं हो सकती। इसके लिए और भी कई उपाय करने होंगे। देखा जाए तो कृषि राज्यों का विषय है। ऐसे में इसकी बेहतरी के लिए उन्हें भी काफी कुछ करना चाहिए। सच्चाई है कि जहां कुछ प्रांत इस पर काफी कुछ कर रहे हैं तो वहीं कई इसमें विफल भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय बढ़ाकर दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह राज्यों की मदद के बिना हो नहीं सकता। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को कर्ज से तो मुक्त कराया ही जाए, साथ ही उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर दिलाया जाए। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह इस पर बहुत जोर देते थे कि किसानों को कर्ज देने के बजाय उनकी फसल या उपज का उचित मूल्य सही समय पर दिया जाए। इससे उनकी आर्थिक समस्याओं का हल निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हम देखें तो पाएंगे कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है। इसमें राज्य सरकारों की भूमिका सबसे बड़ी है।

इस समय गन्ने की पेराई चल रही है। अभी भी कई राज्यों के किसानों को उनकी उपज का पैसा नहीं मिला है। पंजाब में तो इस मुद्दे पर आंदोलन भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश में गन्ना और चीनी उत्पादन में सबसे आगे है। देश के कुल चीनी उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। वहां एक समय चीनी मिलों के पास किसानों के 19,000 करोड़ रुपये बकाया थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के अथक प्रयासों से अब यह राशि घट गई है। हालांकि कुछ बड़ी मिलें उधार चुकाने में अभी भी आनाकानी कर रही हैं। ऐसा नहीं कि ये मिलें घाटे में चल रही हैं। ये मुनाफे में ही हैं, लेकिन अभी भी गन्ना किसानों के पिछले साल के 1,000 करोड़ रुपये तथा इस साल के लगभग 9,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनिंदा बड़ी चीनी कंपनियों में सरकारी बैंकों का काफी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंपनी में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी तो बढ़कर 40 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। इसके बावजूद ये बैंक किसानों को उनका बकाया दिलवाने में मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। अगर सरकारी बैंक किसानों की मदद करें तो वे अपनी उपज का सही मूल्य सही समय पर पा लेंगे और अगले सत्र के लिए कर्ज लेने से भी बच जाएंगे। किसानों की मदद करना बैंकों का सामाजिक उत्तरदायित्व है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो रहा है।

कृषि के विकास के लिए राज्यों को केंद्र सरकार के साथ आना होगा, लेकिन कुछ राज्य इसके विपरीत काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत हर किसान को मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की राशि को बांटने में अड़ंगा लगा दिया। कुछ राज्यों ने तो अभी तक किसानों की पूरी सूची तक नहीं बनाई गई है जिससे किसान इस राशि से वंचित हैं। ऐसी और भी कई योजनाएं हैं जिनमें प्रांतीय सरकारों का योगदान कुछ खास नहीं रहता। इससे किसानों का हित पूरी नहीं हो पाता। कुल मिलाकर किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर चलना होगा।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चिंता और चिंतन

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब वह चिंता से ग्रस्त हो जाता है या फिर चिंतन के मार्ग का पथिक बनता है। दोनों शब्द सुनने में प्रायः एक जैसे ही लगते हैं, परंतु दोनों के अर्थ विपरीत हैं। चिंता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शांति को नष्ट कर देती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति सोचता अधिक है और करता कम है। वह सफलता और असफलता के मध्य की दूरी नापने में ही सारा दिन व्यतीत कर देता है।

चिंतन भी एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार या बात को गंभीरतापूर्वक सोचा जाता है। किसी विषय पर सकारात्मक सोच के साथ मनन करना चिंतन कहलाता है। विचार अवस्था का नाम ही चिंतन है। चिंतन में हम किसी भी विचार या विषय की समालोचना करते हैं तथा उसके प्रति जागरूक होते हैं। चिंतन का यह मतलब नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंता में डूबे रहें। चिंतन वह साधन है जिसमें मनुष्य को उन्नति एवं कार्य में सफलता का मार्ग दिखता है। चिंतनशील व्यक्ति समस्या के समाधान तक पहुंचता है। जहां चिंता समस्या को जन्म देती है वहीं चिंतन समस्याओं का हल करता है। चिंतनशील व्यक्ति मानसिक रूप से सुदृढ़ एवं परिपक्व होता है।

साधना एवं अध्यात्म के मार्ग में चिंता सबसे बड़ी बाधक है, जबकि चिंतन साधना एवं अध्यात्म के शिखर की ओर ले जाता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति स्वयं तो निराशा एवं अवसाद की स्थिति में रहता ही है और जो भी उसकी संगति में रहते हैं उनको भी प्रभावित करता है। चिंतनशील व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त एवं सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है तथा अपने संपर्क में रहने वालों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर देता है। चिंतन और चिंता में वही अंतर होता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी में होता है। हमारे मनीषियों ने भी चिंता को विष के समान तथा चिंतन को अमृत के समान माना है।

आचार्य दीपचंद भारद्वाज

बेटियों के सम्मान से खिलवाड़

सुनीता मिश्रा

नियमों का हवाला देकर पीरियड्स चेक करने के लिए छात्राओं के कपड़े उतरवाना कहीं से भी जायज नहीं है

हाल में गुजरात के भुज के सहजानंद गर्ल्स कॉलेज के बाहर सैनिटरी पैड के मिलने के बाद 68 लड़कियों के पीरियड्स चेक करने के लिए उनके कपड़े उतरवाए गए। यह घटना शिक्षा के उस मंदिर में हुई है, जहां लड़कियों को माहवारी के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। नियमों का हवाला देकर छात्राओं को अपमानित करना कहीं से भी जायज नहीं है। कोई भी नियम छात्राओं के सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता है। यह कुकृत्य धार्मिक दृष्टि से भी गलत है। उस हॉस्टल में गरीब घरों से आने वाली लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। वे पढ़ना चाहती हैं। कुरीतियों को खत्म कर समाज को नई दिशा देना चाहती हैं। ऐसे में अगर उनके साथ ही इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाएगी तो क्या वे भीतर से टूट नहीं जाएंगी?

आज भी देश के कई इलाकों में महिलाएं सैनिटरी पैड्स को लेकर जागरूक नहीं हैं। अभी भी वे इसके इस्तेमाल से गुरेज करती हैं और पुरानी पद्धति का प्रयोग कर रही हैं, जिससे उनमें कई बीमारियां पनप रही हैं। कई इलाकों में तो पैड्स का प्रयोग करने वाली महिलाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है, जिसके कारण वे इसे सबसे छिपाकर इस्तेमाल करती हैं। वहीं जहां लड़कियां इसके प्रति जागरूक हैं, वहां उनके कपड़े उतरवाकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया किया जा रहा है। ऐसे में जब ग्रामीण महिलाएं इस घटना को सुनेंगी एवं देखेंगी तो वे इसे अपनाने में और झिझकेंगी और अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालने में भी डरेंगी।

खैर हॉस्टल में इतने सख्त नियमों के बाद शायद ही कोई छात्रा गार्डन में इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड फेंकेगी। हो सकता है कोई कुत्ता या बिल्ली कचरे के डिब्बे से वह पैड गार्डन में ले आई हो, क्योंकि कोई भी शिक्षित छात्रा अपने छात्रावास को इस तरह से गंदा करने की हिमाकत नहीं कर सकती है। वहीं यदि गार्डन में सबसे पहले इस पैड को देखने वाले ने समझदारी दिखाई होती और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया होता तो इस मुद्दे पर इतना बवाल नहीं होता। दूसरी ओर यदि शक था कि किसी छात्रा ने इसे अपने कमरे की खिड़की से फेंका होगा तो इसकी जांच करवानी चाहिए थी। यदि जांच में साबित हो जाता तो उस छात्रा को समझाया जा सकता था।

साथ ही घटना को संज्ञान में लेते हुए हॉस्टल के अधिकारी लड़कियों की सुविधा के लिए सैनिटरी पैड्स के निस्तारण के लिए मशीन लगवा सकते थे, ताकि इससे कोई बीमारी भी न फैले और आगे से इस तरह की कोई घटना भी सामने न आए, लेकिन प्रशासन ऐसा करने में विफल रहा, जिससे लड़कियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी देनी चाहिए, ताकि फिर इस तरह की कोई घटना सामने न आए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

नेहरू का तंग नजरिया

अवधेश कुमार का आलेख 'नेहरू-पटेल के रिश्तों में कटुता तो थी' सच्चाई बयान करता है। पं. नेहरू ने पटेल के प्रति जो बेरुखी दिखाई, उनके देहांत के बाद भी वह कम नहीं हुई। 15 दिसंबर, 1950 को पटेल के देहावसान के तुरंत बाद उनकी पुत्री मणिबेन उनकी सरकारी गाड़ी लौटाने नेहरू की कोठी पर गईं। उनके साथ एक छोटा ट्रंक था जो पटेल के आदेशानुसार मणिबेन साथ लाई थीं। उस ट्रंक में कांग्रेस पार्टी के वे 25 लाख रुपये थे, जो सरदार को विभिन्न प्रांतीय इकाइयों से चंदे के रूप में प्राप्त हुए थे, पर कहीं खर्च नहीं हुए थे। मणि ने पं. नेहरू के पास उसे रख दिया। उन्होंने ट्रंक खोलकर रुपयों को देखा और कहा ठीक है। मणि बोलीं कि बापूजी ने कार भी वापस की है। पं. नेहरू ने कार की चाबी लेकर मणि को बगैर किसी सांत्वना या सूखे धन्यवाद के ही विदा कर दिया। मणि पैदल ही चलकर वापस लौटीं। उनके पास ऑटो के लिए भी पैसे नहीं थे। नेहरू ने जरा भी स्नेह प्रदर्शित नहीं किया। इसके बाद पटेल का शव गुजरात भिजवाया गया। दिल्ली में उनकी अंत्येष्टि तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि जैसा कि निजलिंगप्पा ने बाद में एक बार कहा था कि नेहरू खानदान ने स्वराज्य भवन देश को देकर पूरी दिल्ली अपने नाम कर ली थी! नेहरू ने न सिर्फ सरदार पटेल सोसायटी को ही दिल्ली में कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि पटेल की स्मृति तक नहीं मनाने दी। नेहरू की मृत्यु के बाद ही शास्त्रीजी के समय में 14 अगस्त, 1965 को लाल किला में उनकी याद में पहला कार्यक्रम संपन्न किया जा सका। पटेल को भारत रत्न न देने के पीछे भी यही नेहरूवादी तंग नजरिया काम कर रहा था। सरदार के जीवनकाल में जब 1950 में हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से खदेड़े जा रहे थे और पटेल ने पाकिस्तान से उनके पुनर्वास हेतु भूमि की मांग की थी तो नेहरू ने बड़े गुस्से में नॉन-सेंस बोला था। ऐसी कितनी ही बातें इतिहास के पन्नों में छुपी हैं। वक्त आ गया है कि जनता से उनका परिचय कराया जाए।

पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ

राह रोक रहा धरना

दिल्ली के शाहीन बाग में आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन राह रोकने वाला धरना समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस धरने से परेशानी केवल आम जनता तथा उन लोगों को हो रही है जिनका यहां से रोज का आना जाना है। लोगों की परेशानी न तो सरकार समझ पा रही है और न ही धरना देने वाले लोग। प्रशासन व प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाया गया है जिससे प्रदर्शन को समाप्त किया जा सके। शाहीन बाग में सड़कों को पूर्ण रूप से बंद कर रखा है जिससे वहां से आवाजाही पूर्ण रूप से प्रभावित हो रही है। स्कूल बस से लेकर एंबुलेंस किसी को भी जाने की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सड़क को बंद कर प्रदर्शन न करने की बात दोहराई है। इस धरने को दिल्ली चुनाव का मुद्दा भी बनाया गया था। सवाल यह है कि दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं, पर शहीन बाग का प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसमें महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी शामिल है जिस कारण प्रशासन भी कड़ी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। अंत में सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर कब धरने का अंत होगा।

amanmaheshwari0501@gmail.com

दो राहे पर शिवसेना

अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि के लिए मशहूर शिवसेना बदली नजर आ रही है। स्वयं को हिंदुओं की पार्टी बताने वाली शिवसेना ने जब से कांग्रेस व एनसीपी के साथ गठबंधन किया है तब से वह किसी भी मुद्दे पर संभल कर बोल रही है। चाहे सीएए हो या एनआरसी या एनपीआर हर मुद्दे पर फूंक- फूंक कर कदम बढ़ा रही है। सरकार बचाने की कवायत में उद्धव सहयोगी दलों को नाराज भी नहीं करना चाहते और हिंदू वोटरों व हिंदुत्ववादी छवि से दूर भी नहीं हटना चाहते हैं। उनके बयानों से स्पष्ट होता है कि शिव सेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद दो राहे पर खड़ी नजर आ रही है। एक ओर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है तो दूसरी ओर अपनी पहचान खोने का डर।

bhattkamleshbk123@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1.47 करोड़ कुल पंजीकृत मतदाता हैं दिल्ली में, जिनमें से 81.05 लाख पुरुष और 66.8 लाख महिला मतदाता हैं। विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 62.59 फीसद हुआ। इसमें 62.62 प्रतिशत पुरुषों ने तो 62.55 फीसद महिलाओं ने वोट डाला।

आजकल

गहरे संकट में फंसती कांग्रेस

दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत से पार्टी पूरी तरह से उत्साह में है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्टी धीरे-धीरे अन्य राज्यों में भी अपना विस्तार करेगी। ऐसे में सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में भी कमोबेश कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर ही आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई है

संतोष पाठक
वरिष्ठ पत्रकार

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत से एक बात साफ है कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। सही मायनों में कहा जाए तो शीला दीक्षित के जमाने में जो वोट बैंक कांग्रेस के पास था, आज उससे भी ज्यादा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पास है। शीला दीक्षित के जमाने में भी दिल्ली में मायावती की बसपा समेत कुछ अन्य दलों का भी अस्तित्व था जिनके पास मजबूत वोट बैंक था। लेकिन केजरीवाल की बयार में यह सब बह गया। दिल्ली के मतदाताओं पर आज 'आप' का राज है और मुकाबले में सिर्फ भाजपा है। कांग्रेस के लिए तो इतना ही कहा जा रहा है कि वह दिल्ली में आखिरी सांसें गिन रही है।

जो हालत दिल्ली में आज कांग्रेस की हुई है, उसी तरह की हालत देश के कई राज्यों में पैदा होने का खतरा उसके लिए बढ़ता जा रहा है। देश भर में कांग्रेस इसीलिए कमजोर होती चली गई, क्योंकि उसका वोट बैंक दूसरे दलों की तरफ खिसकता चला गया। उत्तर प्रदेश में एक जमाने की मजबूत पार्टी कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया तो मुसलमान हमेशा के लिए सपा के साथ चले गए। बसपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा तो बचा-खुचा दलित मतदाता भी बसपा के पाले में चला गया है। बिहार में लालू प्रसाद की सरकार बचाने के लिए समर्थन दिया तो आज नतीजा यह है कि अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसी राजद से सीटों की मिन्नत करनी पड़ती है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कांग्रेस की यही कहानी रही है। ज्यादातर राज्यों में नए राजनीतिक दलों ने पहले कांग्रेस का साथ लेकर अपनी जमीन को मजबूत किया और फिर कांग्रेस के वोट बैंक को साधकर ही सरकार बनाई और बेहाल कांग्रेस अपनी हालत से दुखी होने के बजाय भाजपा की हार का जश्न मनाने में लगी है।

आप की विस्तार योजना : दिल्ली की प्रचंड जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय विस्तार तो करना चाहती है, लेकिन इस बार तरीका 2014 से अलग होगा। पार्टी 2014 की गलती नहीं दोहराना चाहती है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण के बाद अरविंद केजरीवाल का वहां मौजूद लोगों से यह कहना कि 'अपने गांव फोन करके बता देना कि आपका बेटा चुनाव जीत गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है' अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार राज्य से बाहर भी करना चाहते हैं।

लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी संभल कर राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करते हुए दिखाई देगी। बताया जा रहा है कि पार्टी ने इसके लिए तीन सूत्री कार्ययोजना तैयार कर ली है। इसके तहत पहले सभी राज्यों में सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी। पार्टी की योजना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव में हाथ आजमाया जाए। देश के कई राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं और जहां-जहां भी संभव हुआ पार्टी पूरे दम खम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी सकारात्मक राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ विस्तार अभियान चलाएगी। इस बार पार्टी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद ही चुनावी मैदान में उतरेगी।

कांग्रेस के वोट बैंक पर नजर : आम आदमी पार्टी खुद भी इस बात को समझती है कि कांग्रेस से निराश लोगों ने उसकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह फॉर्मूला देश के अन्य राज्यों में आजमाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। सोनिया गांधी फिलहाल पार्टी की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता इसलिए वह चाहती हैं कि फिर से राहुल गांधी ही पार्टी की बागडोर संभाल लें। राहुल इन्कार कर चुके हैं और सोनिया गांधी परिवार के बाहर किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहती हैं। राज्यों में भी जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है वहां-वहां गुटबाजी चरम पर है। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई चल रही है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम सिंधिया की। कई राज्यों की जनता तो यह मान ही चुकी है कि कांग्रेस में भाजपा का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। दिल्ली के चुनाव ने यह बता दिया है कि देश का मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से पूरी तरह विमुख हो चुका है और जहां-जहां उसे भाजपा को हराने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा, वो उसके साथ चला जाएगा। भाजपा विरोधी अन्य मतदाताओं का भी बड़ा समूह अब कांग्रेस की बजाय भाजपा से मुकाबला करने वाले दल के साथ ही जाएगा।

कांग्रेस पर मंडराता संकट : वर्ष 2022 में दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव को 'आप' जोर-शोर से लड़ेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में भी पार्टी निकाय चुनावों में उतर सकती है। जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में जैसे-जैसे आप मजबूत होती जाएगी, वैसे-वैसे कांग्रेस कमजोर होती जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में 'आप' की मजबूती का नुकसान सपा और राजद को भी उठाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल चुनौती कांग्रेस के समक्ष ज्यादा है। कांग्रेस के दिग्गज और अनुभवी नेता इस खतरे को महसूस कर रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान के सामने सच बोलने की हिम्मत भला किसमें है।

विडंबना देखिए कि कई कांग्रेसी दिग्गज पार्टी की हार की समीक्षा करने की बजाय आप की जीत पर खुश होकर बयान दे रहे हैं। राजनीतिक हालात भी आज आप के अनुकूल है। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत से कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। देश भर में केजरीवाल मॉडल की चर्चा हो रही है। सॉफ्ट हिंदुत्व वाला केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कामयाब होता भी नजर आ रहा है तो भला 'आप' देश भर में छाने की कोशिश क्यों ना करे।

नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की फाइल फोटो।

महिलाओं के योगदान की अनदेखी

अलका आर्य
स्वतंत्र टिप्पणीकार

दिल्ली की महिला मतदाताओं ने 'आप' की जीत व अरविंद केजरीवाल को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर मंत्रिमंडल में जगह नहीं देकर निराश किया है। इस पर चर्चा से पहले राजनीतिक माहौल में महिला मतदाताओं की भूमिका व उनके प्रभाव को याद करना प्रासंगिक लग रहा है। ममता बनर्जी ने 2011 के बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद कहा था, 'मैं महिलाओं की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मतदाताओं को घर से बाहर निकाल पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए भेजा।'

वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव का फैसला महिला वोट करेंगे। उस साल पहली मर्तबा बिहार में मतदान करने में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2015 में भी नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के बाद सूबे में शराबबंदी लागू करने का वादा कर महिलाओं के साथ मजबूती से खड़े होने का सामाजिक-राजनीतिक संदेश दिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली की आधी आबादी और 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों और मंत्रिमंडल पर लौटते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदाता 1.47 करोड़ में से 81.05 लाख पुरुष और 66.8 लाख महिला मतदाता थे। कुल मतदान 62.59 प्रतिशत हुआ। 62.62 प्रतिशत पुरुषों ने तो 62.55 प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला। इस तरह महिला व पुरुषों के मत प्रतिशत में अंतर महज 0.7 प्रतिशत का है। आंकड़े बताते हैं कि यह फासला कम हो रहा है।

इस विधानसभा चुनाव में बतौर महिला मतदाताओं के कई रुझानों के राजनीतिक- सामाजिक महत्व हैं। बेशक इस बार दिल्ली में 2015 की तुलना में 4.54 प्रतिशत कम मतदान हुआ, पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में आप को अधिक वोट डाले। लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 60 प्रतिशत महिलाओं ने आप के पक्ष में वोट डाला तो 49 प्रतिशत पुरुषों का वोट ही आप को मिला। इस अंतर का एक मतलब पार्टी को समझना चाहिए कि अगर यह नहीं होता तो आप को चुनाव में जो एकतरफा जीत मिली है, वह नहीं मिलती। इस सर्वे में यह बात सामने आई है कि इस बार 69 प्रतिशत महिलाओं ने वोट के लिए आप को चुना तो 35 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा को। यहां भी आप को लीड मिली। किसी भी जाति, समुदाय, आयुवर्ग की बात करें तो दिख रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के अधिक वोट आप को मिले।

लोकनीति 1998 से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन कर रही है और आंकड़े यही बोलते हैं कि पहली मर्तबा 2020 में ऐसा व्यापक लैंगिक फासला वोट की प्राथमिकता संबंधी रुझान में देखने को मिल रहा है। यहां तक कि जब शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री बनीं तब भी यह रुझान नहीं देखने को मिला था। दिल्ली की युवा महिला मतदाता व महिला मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट क्यों डाला, इसके पीछे मुख्य वजह शिक्षा, स्कूली इमारतें, मोहल्ला क्लीनिक, एक सीमा तक मुफ्त बिजली-पानी, महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, सीसीटीवी कैमरे आदि बताया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि दिल्ली के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी मंत्री पुरुष हैं, जबकि आप की आठ महिला उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में पहुंची हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इस बारे में कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली की जनता ने सरकार के कार्यों में भरोसा जताया है, लिहाजा मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का कोई औचित्य नहीं नजर आता। जहां तक महिला सशक्तीकरण का सवाल है, वह आंकड़ों में नहीं बल्कि आप की सोच, नीतियों व प्रयासों से झलकती है।

खरी-खरी

डंडे का फंडा और ट्यूबलाइट

ओम वर्मा

महज एक धोती तन पर लपेट और लाठी टेककर चलने वाला एक राजनीतिक संत कभी जिस दल का आदर्श हुआ करता था, आज वहां डंडे चलाने का आह्वान किया जा रहा है। दल का पितृपुरुष कभी बरतानिया हुकूमत को बिना हाथ उठाए भगाना चाहता था, वहीं आज दल के पुत्रपुरुष सत्ता को डंडे का भय दिखा रहे हैं। देश में झंडे तो हर कहीं हैं, मगर झंडे में डंडा निकालकर उसका अपनी सुविधा व जरूरत अनुसार प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस डंडे को प्राप्त करने के लिए मनचाहे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

उन्होंने डंडा मारे जाने की बात तो कही है, मगर छह माह का वक्त भी दिया है। यहां यह समझना मुश्किल है कि यह अवधि प्रहारकर्ताओं को तैयार हो जाने के लिए दी गई है या बचाव पक्ष को बचाव की तैयारी के लिए? वैसे छह माह का समय दोनों पक्षों के लिए पर्याप्त ही नहीं, उपयोगी भी साबित होगा। बचाव पक्ष ने तो आत्मरक्षार्थ अपने दैनिक व्यायाम में सूर्य-नमस्कार की आवृत्ति बढ़ा दी है। इस धमकी से उन्हें एक लाभ यह हुआ है कि इस व्यायाम से वे अपनी पीठ शायद दधीचि की तरह वज्र-सी कठोर बनाकर किकी चैलेंज टाइप कोई नया फिटनेस चैलेंज सामने रख दें।

हालांकि छह माह में स्थिति बहुत बदल भी सकती है। इस बीच सैम अंकल का भारत दौरा हो चुका होगा, कुछ सूरमा टीवी चैनल तब तक पाकिस्तान को बीसियों बार बरबाद कर चुके होंगे, तो कुछ नेता दूसरे दल के प्रमुख नेता को अपनी सौवीं और कोई दो-सौवीं गाली दे चुके होंगे। कुछ लोग एक समुदाय विशेष के कई लोगों को पड़ोसी मुल्क में भेजने की धमकी दे चुके होंगे, पड़ोसी मुल्क से परमाणु बम की इक्कीसवीं धमकी मिल चुकी होगी, बंद पड़ी सभी ट्यूबलाइटें जल गई होंगी (जो नहीं चेतेंगी, वे या तो बदल दी जाएंगी या कबाड़खाने में पटक दी जाएंगी)... एंड सो ऑन!

जो ट्यूबलाइटें पंद्रह वर्षों तक बिना लुपलुपाए जलती रहीं, उन्होंने पिछले पांच वर्षों में लुपलुपाना भी छोड़ दिया है। बीच-बीच में कोई आकर सिर्फ रॉड घुमा देता है, जबकि जरूरत स्टार्टर बदलने की है। कहीं ऐसा न हो कि सारे डंडे इन न चेतने वाली ट्यूबलाइटों पर ही चल जाएं!

ट्वीट-ट्वीट

इतने बड़े षड्यंत्र की जानकारी होने के बावजूद राकेश मारिया ने सत्य बताने के लिए इतने वर्ष क्यों लगा दिए! जबकि गृह मंत्रालय के आरवीएस मणि ने वर्ष 2012 में ही इस बात का खुलासा किया था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को 26/11 की घटना की जांच दोबारा बैठानी चाहिए।
मालिनी अवस्थी@maliniawasthi

अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बजाय सिंधिया महाराज को नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहिए।
आचार्य प्रमोद@AcharyaPramodk

शाहीन बाग धरना एक पार्टी को हराने के लिए किया गया था, और वह पार्टी चुनाव में हार गई। यह एक पार्टी को जिताने के लिए था, और उसे बड़ी जीत भी हासिल हो गई। अब उसी पार्टी ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है।
स्मिता मिश्रा@missartola

'भारत में महिला उद्यमिता' शीर्षक से आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार इसके जरिये देश भर में 15 से 17 करोड़ रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। यह देश में बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में मददगार तो होगा ही। वहीं इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी तो अर्थव्यवस्था को स्वाभाविक रूप से लाभ होगा।
किरण मजूमदार शॉ@kiranshaw

जागरण जनमत
कल का परिणाम

क्या बाबूलाल मरांडी के वापस आने से झारखंड में भाजपा मजबूत होगी?

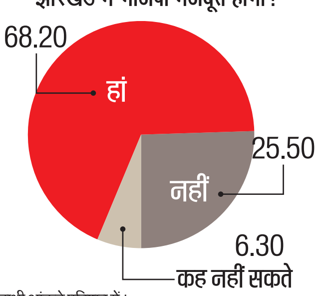

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या कोरोना वायरस विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नया खतरा बन गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

लालू के स्थान पर पुत्र करेगा राज,
सेवक गण पहनाइए सिर्फ उसे ही ताज।
सिर्फ उसे ही ताज यही है 'डेमोक्रेसी',
शरद सरीखे लोग समझ लें भाषा देसी!
बंधु समोसा बीच भले ही रहे न आलू,
राजद में तो राज करेंगे केवल लालू।
– ओमप्रकाश तिवारी

जम्मू-कश्मीर डायरी

अलग-थलग पड़ते अलगाववादी

अभिमन्यु शर्मा
संपादक, जम्मू-कश्मीर

केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश को लेकर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलाव साफ नजर आने लगा है। जम्मू-कश्मीर के भीतर भी सोच में बदलाव महसूस किया जा रहा है। अब कश्मीर मुद्दे और जम्मू कश्मीर की सियासत दोनों की चर्चा होती है, हंगामा नहीं। कश्मीर, जिसे कल तक पाकिस्तान एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा करार देता रहा और इसकी मध्यस्थता पर जोर देता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को अलग-थलग पाकर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कह दिया कि हिंदुस्तान को कश्मीरियों को स्वायत्तता देनी चाहिए।

मतलब यह कि वह कश्मीर से खुद को अलग रखने के लिए कोई 'सेफ पैसेज' तलाश रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू किए जाने का ही असर है कि कश्मीर का दौरा करने वाले किसी भी विदेशी राजदूत या राजनयिक ने कश्मीर मुद्दे पर अलगाववादियों और पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली टिप्पणी नहीं की। बीते छह माह में इन सभी प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान को अपना रवैया बदलने और कश्मीर में हस्तक्षेप न करने की नसीहत ही दी। करीब 70 विदेशी राजनयिक और राजदूत बीते छह माह में कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। इनमें से करीब डेढ़ दर्जन विदेशी राजदूतों और राजनयिकों के दल ने इसी माह जम्मू-कश्मीर की यात्रा की। उन्होंने कश्मीर के हालात को देखा और समझा भी है। इनमें से किसी ने भी हुर्रियत कांफ्रेंस के किसी नेता से ना तो मुलाकात की और ना ही उनका जिक्र किया। अमेरिका, जिस पर अक्सर दो गुटों में बंटी हुर्रियत कांफ्रेंस के उदारवादी गुट के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी उमर फारुक और कट्टरपंथी सईद अली शाह गिलानी और जेकेएलएफ चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक मध्यस्थता के लिए जोर देते थे, उसके राजदूत भी कश्मीर का जायजा लेकर लौट गए। उन्होंने भी अलगाववादियों का जिक्र नहीं किया। जर्मनी के राजदूत ने भी अलगाववादी खेमे से दूरी बनाए रखी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू-कश्मीर को लेकर बदली सोच का असर कश्मीर की आंतरिक सियासत पर भी हुआ है। अलगाववादी खेमा जहां अब पूरी तरह से खामोश होकर अपने लिए कोई जगह तलाश रहा है, तो वहीं छद्म अलगाववाद के नाम पर सियासत करने वाली कश्मीर केंद्रित पार्टियां भी अब अपने रवैये में बदलाव ला रही हैं। जम्मू-कश्मीर में रिक्त पड़े लगभग 13 हजार पंच-सरपंच हल्कों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने एलान किया।

वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर में हुए पंचायत चुनावों के दौरान आतंकियों की धमकी और नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के बहिष्कार के चलते कई सीटों पर चुनाव नहीं हो पाया था। अब हालात बदलने के साथ ही इन सीटों पर अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की पूर्व स्थिति की बहाली तक किसी प्रकार के चुनाव में हिस्सा न लेने का एलान करने वाली नेशनल कांफ्रेंस अब अपने नेताओं की रिहाई की शर्त पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनावों से दूर रहने का कोई स्पष्ट संकेत देने के बजाय चुप्पी साधना बेहतर समझा है।

बीते चार-पांच दिनों में जो संकेत मिले हैं, यह अब स्वायत्तता और सेल्फ रूल जैसे राजनीतिक एजेंडे से कहीं ज्यादा अपने कैडर को पार्टी के झंडे तले जमा रखने को लेकर ज्यादा फिक्रमंद हैं। बीते दो वर्षों में जिस तरह से पंचायतों को सशक्त बनाया गया है, उसके बाद इन दलों का अधिकांश कैडर, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, नहीं चाहता कि वह लोकतंत्र में हाशिए पर खड़ा रहे। वह 2018 की गलती को दोहराने के मूड में नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना चाहता है। अगले माह कई चरणों में संपन्न होने वाली पंचायत चुनावों की प्रक्रिया कश्मीर केंद्रित दलों को खुद को संभालने और छद्म अलगाववाद का लबादा उतारने का मौका दे रही है। अब देखना यह है कि वह इस लबादे को कब और कैसे उतारते हैं।

कश्मीर के दौरे पर आए विदेशी राजनयिक दल के सदस्य। फाइल

मंथन

विकसित देश के दर्जे का अर्थ

अमेरिका ने भारत को 'विकसित अर्थव्यवस्था' मान लिया है। लिहाजा विकासशील देशों को मिलने वाली अमेरिकी मदद अब भारत को नहीं मिल सकेगी

शाहिद ए चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार

बीती दस फरवरी को अमेरिका ने भारत सहित एक दर्जन से अधिक देशों को 'विकासशील' की श्रेणी से हटा दिया है। अमेरिका व्यापार करने के उद्देश्य से देशों को विकासशील, विकसित आदि श्रेणियों में रखता है, जिसके तहत विकासशील देशों को विभिन्न प्रकार के व्यापार लाभ दिए जाते हैं। भारत को विकासशील की श्रेणी से निकाल 'विकसित' अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रख दिया गया है। इससे भारत का अमेरिका से व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह काम उस समय किया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका का जबरदस्त दबाव है कि नई दिल्ली अमेरिकी दूध व दुग्ध उत्पादों के लिए अपने बाजार खोल दे, लेकिन परिवर्तित टैग की पृष्ठभूमि में ट्रंप के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कोई व्यापार समझौता होना कठिन प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए भी कि नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव और अमेरिकी प्रशासन इसके बाद ही कोई करार करेगा।

यूनाईटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) कार्यालय देशों की एक सूची रखता है, जिन्हें वह विकासशील, विकसित व सबसे कम विकसित श्रेणियों में रखता है। जो देश विकासशील की श्रेणी में आते हैं उन्हें कुछ चीजें अमेरिका को निर्यात करने की अनुमति होती है और उनको वह 'अधिक टैरिफ' नहीं देना पड़ता जो विकसित देशों को देना पड़ता है। विकासशील देश का स्टेटस यूएस ट्रेड एक्ट-1974 के तहत है, जो गरीब देशों को तेजी से विकास करने के लिए जीएसपी (जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसिज) की अनुमति प्रदान करता है। विश्व ट्रेड संगठन (डब्लूटीओ) के तहत इन लाभों का विस्तार हुआ, जब रईस देश इस बात पर सहमत हो गए कि जो देश अपने को गरीब कहते हैं उन्हें व्यापार लाभ दिया जाए। डब्लूटीओ के जो सदस्य हैं उनमें से लगभग दो-तिहाई देश अपने आपको विकासशील कहते हैं और यह लाभ हासिल करते हैं।

कोई देश विकासशील है या नहीं, यह तय करने का कोई पैमाना नहीं है, सब कुछ मनमर्जी पर है। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत व चीन ने जो आर्थिक प्रगति की है, उसके आधार पर कुछ का कहना है कि इनके विशेष दर्जे पर विराम लगा देना चाहिए। पर दूसरी ओर विकास के अन्य सूचकांकों की ओर भी इशारा किया जाता है जिनमें भारत व चीन रईस संसार से काफी पिछड़े हुए हैं। फिर इस बात पर भी सहमति नहीं है कि इस प्रकार की श्रेणी की जरूरत है भी या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि भारत को विकासशील के दर्जे से क्यों निकाला गया? ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने तेजी से विकास कर रहे देशों जैसे भारत व चीन पर निरंतर यह आरोप लगाए हैं कि वह गलत तरीके से व्यापार लाभ ले रहे हैं, जो केवल वास्तव में विकासशील देशों के लिए आरक्षित हैं।

इसलिए ट्रंप चीन जैसे देशों से व्यापार समझौते फिर से करना चाहते हैं ताकि आवश्यक रूप से इन करारों को अमेरिकी हितों के लिए 'अधिक संतुलित' किया जा सके। परंपरागत दृष्टि से जीएसपी के तहत सबसे ज्यादा लाभ भारत ने उठाया है कि उसकी 2000 वस्तुओं से अधिक पर इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगता था। इस विशेष लाभ को पिछले वर्ष ट्रंप प्रशासन ने समाप्त कर दिया था, जिससे जाहिर है कि भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। अब जब यूएसटीआर क्लासिफिकेशन के तहत भारत का स्टेटस बदल गया है तो खोए हुए जीएसपी लाभों को फिर से हासिल करना और अधिक कठिन हो जाएगा। अपने फैसले के समर्थन में ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया है कि भारत व चीन जैसे देशों ने पिछले कुछ दशकों के दौरान महत्वपूर्ण विकास किया है। उसका मानना है कि यह पर्याप्त कारण है विभिन्न व्यापार लाभों को वापस लेने का। ट्रंप प्रशासन ने इसके अलावा वैश्विक व्यापार में भारत और चीन की हिस्सेदारी का भी उल्लेख किया है और जी-20 क्लब की इनकी सदस्यता का भी कि अब यह दोनों देश महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति बन गए हैं। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह आरोप भी लगाया है कि टैरिफ से बचने के लिए बहुत से विकसित देश अपने को विकासशील घोषित करते हैं। सवाल यह भी है कि अमेरिका के इस निर्णय का वैश्विक व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ड्यूटी फ्री एक्सेस पर विराम लगने के बाद जो वस्तुएं अमेरिका में आएंगी उससे अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने वाली वस्तुओं पर कुल टैक्स बोझ बढ़ जाएगा, जो जाहिर है कि ट्रेड स्टेटस बदलने के कारण ऐसा होगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जो इस वर्ष वैसे ही सुस्ती की मार झेल रही है।

इससे अनेक देशों में विकास प्रभावित होगा, आर्थिक सुस्ती और महंगाई भी बढ़ेगी। हाल ही में भारत ने अमेरिका से आयातित की जाने वाली कुछ चीजों पर टैरिफ कम करने का ऑफर दिया था। यह ऑफर उस समय दिया गया था, जब अमेरिका ने शिकायत की थी कि भारत जैसे देश अमेरिकी कंपनियों को सीमित पहुंच मुहैया कराते हैं।

अगर इस प्रकार की व्यापारिक चालें दोनों तरफ व्यापार बाधाओं को कम कर दें तो इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। लेकिन चिंताजनक तथ्य यह भी है कि अमेरिका और उसके विभिन्न व्यापार साझेदार अपने घरेलू उत्पादकों को सुरक्षित रखने का निरंतर प्रयास करते हैं, बजाय उस उपभोक्ता के जो कम टैरिफ से लाभान्वित होता है। इसलिए टैरिफ में कमी आने की संभावना तो नहीं ही लगती है। (ईआरएस)

3.8 लाख किलोमीटर की दूरी तक सफर के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपना एक साल पूरा कर लिया। इस दौरान 100 फीसद सीटों पर आरक्षण के साथ ट्रेन ने 92.29 करोड़ की आय अर्जित की।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 20 फरवरी 2020

जम्मू-कश्मीर

काम आया विपक्षी दलों का दबाव

पंचायत उपचुनाव को लेकर मंगलवार सुबह हुई सर्वदलीय बैठक के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम के बीच रात को चुनाव स्थगित कर दिया गया। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई सारी अधिसूचनाओं को वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 13 फरवरी को केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में रिक्त पड़े 1011 सरपंच और 11639 पंच हलकों के चुनाव दलीय आधार पर करवाने का एलान किया था। उसके साथ ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी कि मतदान आठ चरणों में करवाया जाएगा। पहले चरण का मतदान पांच मार्च और अंतिम चरण का मतदान कहा गया था कि मतदान के लिए वोटिंग मशीन के बजाय मतपेटियां और मतदान पत्र इस्तेमाल होंगे, पर 18 फरवरी रात को सारी अधिसूचना वापस ले ली गई।

इसे विपक्षी दल अपनी बड़ी उपलब्धि मान रह हैं। विपक्ष चुनाव की घोषणा के बाद से ही इस मुद्दे पर अड़ा हुआ था कि पहले चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर हुए और अब राजनीतिक आधार पर करवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इतना ही नहीं विपक्षी दलों का यह भी तर्क है कि जब राजनीतिक पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व पांच माह से जेलों में बंद है तो ऐसे में चुनाव करवाने में कोई औचित्य नहीं है। शायद विपक्षी दलों के दवाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी की थी, उन्हें वापस ले लिया। बेशक मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरक्षा का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। किसी भी चुनाव की घोषणा से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पहले ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी होती है। चुनाव को लेकर तेजी से बदले घटनाक्रम को देखा जाए तो सरकार भी विभिन्न राजनीतिक दलों को यह मुद्दा नहीं देना चाहती कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष के बिना ही पंचायतों के चुनाव हो गए। मंगलवार को पीडीपी, नेकां, कांग्रेस, पैंथर्स ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। यहां तक कि पीडीपी ने तो बैठक का बहिष्कार भी कर दिया था। पंचायत चुनाव राजनीतिक आधार पर कराए जाने पर विपक्षी दलों के कड़े रुख ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

> चुनाव को लेकर तेजी से बदले घटनाक्रम को देखा जाए तो सरकार भी दलों को यह मुद्दा नहीं देना चाहती कि जम्मू कश्मीर में विपक्ष के बिना ही पंचायतों के चुनाव हो गए

विपक्षी पार्टियों ने फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि उनका दवाब काम आया। उपचुनाव की घोषणा तो दो या तीन सप्ताह में हो जाएगी, लेकिन पहले की तरह चुनाव गैर राजनीतिक आधार पर ही कराए जा सकते हैं। इससे एक समानता बनी रहेगी और विपक्ष को मुद्दा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस और पैंथर्स के नेता जम्मू संभाग में लोगों के बीच आ जा सकते हैं। केंद्र को चाहिए कि वह पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को उनके कार्यकर्ताओं से मिलने दिया जाए, जिससे कि वह चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर सकें।

पंजाब

पाप है अनाज की बर्बादी

देश में एक तरफ जहां बड़ी संख्या में लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है, वहीं दूसरी तरफ हालात ऐसे भी हैं कि भंडारण और रखरखाव की सुविधा न होने के कारण लाखों टन अनाज हर साल बर्बाद हो जाता है। पंजाब में भी भंडारण और रखरखाव के अभाव में बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद होता है। यह निःसंदेह पीड़ाजनक है। प्रदेश का अन्नदाता कड़ी मेहनत करके देश का अन्न भंडार भरने में अधिकाधिक योगदान का प्रयास करता है, परंतु अदूरदर्शिता और अफसरशाही की हीलाहवाली के कारण मंडियों में ही बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो जाता है। गत दिवस प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु की यह पीड़ा पंजाब दौरे पर आए केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री राव साहेब दादाराव दानवे के समक्ष छलकी भी। हालात कितने गंभीर हैं इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 95 लाख मीट्रिक टन अनाज में से 36 लाख मीट्रिक टन अनाज खुले में पड़ा है। बाकी अनाज गोदामों में है। भंडारण की स्थिति तब और गंभीर हो जाएगी, जब नया अनाज मंडियों में पहुंचेगा।

इस बार अप्रैल में करीब 130 लाख मीट्रिक टन अनाज मंडियों में पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इससे मंडियों में न सिर्फ अफरातफरी का माहौल बनने की आशंका है, अपितु इस बात से भी इन्कार

> हैरत की बात यह है कि ऐसी स्थिति हर साल उत्पन्न होती है, लेकिन शायद ही कभी इसके समाधान के प्रति गंभीरता से प्रयास किए गए

प्रतीकात्मक फोटो

नहीं किया जा सकता है कि इस साल भी बड़ी मात्रा में अनाज बर्बाद हो सकता है। हैरत की बात यह है कि ऐसी स्थिति हर साल उत्पन्न होती है, लेकिन शायद ही कभी इसके समाधान के प्रति गंभीरता से प्रयास किए गए। यदि अभी भी अनभिज्ञता का प्रदर्शन किया गया तो हालात और गंभीर ही होंगे। इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। प्रदेश में भंडारण की व्यवस्था तो बढ़ानी ही होगी, साथ ही निर्यात की व्यवस्था को भी सहज व सुगम बनाना होगा। इससे अनाज की बर्बादी तो रुकेगी ही, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में करीब 50 हजार करोड़ की कीमत का अन्न हर साल बर्बाद होता है। इतना अन्न बिहार जैसे राज्य की कुल आबादी को एक साल तक भोजन उपलब्ध करवा सकता है। 2017 की सीएसआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इंग्लैंड में भोजन की जितनी खपत होती है, उतना हम बर्बाद कर देते हैं। वहीं एक सर्वे के अनुसार भारत में हर साल प्रति व्यक्ति 51 किलोग्राम खाने की बर्बादी करता है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है, लेकिन वैश्विक भूख सूचकांक-2019 में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा भूख पीड़ित देशों की सूची में 102 वें स्थान पर रहा।

हालांकि देश में अनाज की बर्बादी रोकने के संबंध में कोई कानून नहीं है और न ही इसे रोकने के प्रति नागरिकों में पर्याप्त सजगता का भाव ही निहित है। अनाज की बर्बादी पर अंकुश लगाए बिना कुपोषण और भुखमरी जैसी बुनियादी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से नहीं निपट जा सकेगा।

झारखंड

करनी होगी मजदूरों की फिक्र

अर्थव्यवस्था की रफ्तार जब सुस्त दिखाई देने लगे तो गांवों, कस्बों, शहरों में अधिक से अधिक हाथों को काम देने की कवायद होनी चाहिए। तालाब खोदने, ग्रामीण सड़क एवं नालियों के निर्माण जैसे छोटे-छोटे काम शुरू देने चाहिए। इससे लोगों के पास पैसे आएंगे। बाजार में मांग बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा जिससे अर्थव्यवस्था की सुस्ती भी दूर होती चली जाएगी। अर्थशास्त्र का यह बेहद सामान्य फॉर्मूला है। देश की अर्थव्यवस्था को सुस्ती के दौर से निकालने के लिए केंद्र सरकार इस दिशा में काम करती नजर आ रही है। वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाकर मांग बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राज्यों को भी अपने-अपने स्तर पर इस तरह के कदम उठाने चाहिए।

देखा जाए तो झारखंड की अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसमें ऐसे ही उपायों की सख्त जरूरत है। इसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा बेहद कारगर साबित हो

प्रतीकात्मक फोटो

सकती है। झारखंड में भी इससे बड़ी संख्या में मजदूर जुड़े हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह महत्वपूर्ण योजना सरकारी एजेंडे से गायब-सी है। इस कारण सुदूर गांवों से पलायन रोकने में सक्षम इस योजना से जुड़े मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। काम मिल भी गया तो ससमय मजदूरी भी नहीं मिल रही। इतना ही नहीं इस योजना के तहत मजदूरों की तय मजदूरी भी बेहद कम है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को जहां एक दिन की मजदूरी के तौर पर 171 रुपये भुगतान का प्रावधान है, वहीं इसी राज्य में सामान्य मजदूरों के लिए प्रति दिन की न्यूनतम मजदूरी 274 रुपये तय है।

कई वर्षों से मनरेगा के मजदूर और पंचायत प्रतिनिधि मजदूरी को बढ़ाने की मांग राज्य सरकार से करते आ रहे हैं। धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन असंगठित होने के कारण इनकी आवाज सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पाती है। ये मजदूर अपने पड़ोसी राज्य ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का उदाहरण देते हैं, जहां अभी झारखंड से बेहतर मजदूरी वहां की सरकारें दे रही हैं। महंगाई के दौर में 171 रुपये पर्याप्त नहीं हैं। मनरेगा मजदूरों की मांगों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मजदूरी कम होने के कारण यहां से मजदूर अन्य राज्यों में पलायन करने लगे हैं। यह चिंताजनक है। इस स्थिति को बदलना होगा। नई सरकार से हर वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हैं। ऐसे में मनरेगा मजदूरों की फिक्र भी सरकार को करनी होगी।

बंगाल

विधानसभा से पहले निकाय चुनाव

बंगाल की ममता सरकार ने सूबे के 102 नगर निकायों (नगर पालिका एवं निगम) में चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए संभावित तिथि भी तय कर ली है। इसके मद्देनजर आगामी 20 फरवरी को तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर के सभी नगर निकायों के चेयरमैन, मेयर से लेकर वार्ड पार्षदों एवं नेताओं की बैठक बुलाई है। भाजपा, कांग्रेस एवं वामपंथी दल भी अपने-अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। देखा जाए तो सीएए, एनआरसी और एनआरपी के जरिये मतदाताओं की गोलबंदी में जुटे राजनीतिक दलों को अब अपनी-अपनी हैसियत आंकने का एक अवसर आ गया है। यह मौका 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट भी होगा। जैसे हांडी से एक चावल के जरिये पूरी स्थिति आंक ली जाती है वैसे ही कुछ निकाय चुनाव में भी संकेत मिलेगा। 2010 में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने निगमों और निकायों पर कब्जा जमकर उस जमाने की वामपंथी सरकार की जड़ें हिलानी शुरू कर दी थीं। तबसे बंगाल में दो बार सत्ता संभाल रहीं ममता तीसरी पारी के लिए दम साधे हैं। इस दिशा में वह लगातार मुहिम चला रही हैं। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर वह राज्य के हर कोने में जा रही हैं और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं।

> राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने की तैयारी में जुट गई है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। यह अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा

इधर भाजपा ने भी ममता सरकार के खिलाफ बंगाल में लगातार मुहिम चलाई है। लोकसभा में 18 सीटें हासिल करने वाली भाजपा की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव परिणामों ने उसे चौकन्ना कर दिया है। भाजपा निकाय चुनाव में बुनियादी मुद्दों को हवा देने की कोशिश करेगी और इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार भी ठहराएगी। ममता बनर्जी खुद भाजपा पर हमलावर हैं और बजट सत्र में उन्होंने मुफ्त बिजली देने का एलान कर मतदाताओं को साधने का भरपूर उपक्रम किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसी फंडे से सभी विपक्षी दलों को चित कर दिया। जाहिर है कि बुनियादी मुद्दों के जरिये निकाय चुनाव को साधने की कोशिश होगी। संभव है कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर अपनी किस्मत आजमाएं। ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य के सभी निकाय प्रमुखों की बैठक बुलाई है। यह बैठक भी चुनावी रणनीति के लिहाज से ही आहूत की गई है। रणनीतिक दांव-पेच में सभी एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। निकाय चुनाव में वोटर की कसौटी पर कौन कितना खरा उतरेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में आ गई है। अब मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा पर उसकी राह रोकने की चुनौती है। इस बीच दल-बदल भी शुरू हो गए हैं। तृणमूल छोड़कर दूसरे दलों में गए लोग एक बार फिर लौटने लगे हैं।

पीओएस सिस्टम से मध्य प्रदेश में थम गई सरकारी राशन की बंदरबांट

- छह माह में बचा 8.73 करोड़ किलो गेहूं, 2.93 करोड़ किलो चावल
- पीओएस सिस्टम लागू होने के बाद अंगूठा लगाकर दे रहे राशन
- सरकारी राशन की दुकानों पर अब नहीं फटक रहे फर्जी गरीब

प्रतीकात्मक फोटो

हरिओम गौड़, श्योपुर

देश की राशन दुकानों पर गरीबों को सस्ती दरों पर मिलने वाले गेहूं-चावल के वितरण को पीओएस सिस्टम (अंगूठा लगा कर राशन वितरण) से जोड़ने के बाद फर्जी गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आसपास नहीं भटक रहे हैं। इसका असर यह हुआ कि पिछले छह महीने में अकेले मध्य प्रदेश की पीडीएस दुकानों पर आठ करोड़ 73 लाख किलो गेहूं और दो करोड़ 93 लाख किलो चावल बच गया है।

सरकार ने राशन की दुकानों के लिए पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) सिस्टम लागू किया है। इसके तहत सितंबर में 2019 में श्योपुर समेत पूरे प्रदेश में पीडीएस दुकानों को फिंगर प्रिंट व्यवस्था से जोड़ दिया गया। श्योपुर में एक लाख 6 हजार 800 गरीब परिवार हैं जिन्हें पीडीएस दुकान से एक-एक रुपये किलो में गेहूं और चावल दिया जाता है। यहां 23 लाख 21 हजार 721 किलो गेहूं का आवंटन हुआ था, जो फरवरी में लुढ़ककर 12 लाख 71 हजार 293 किलो रह गया। यानी सितंबर की तुलना में फरवरी में अकेले श्योपुर में ही 10 लाख 50 हजार 428 किलो गेहूं बच रहा है।

पूरे मप्र की बात करें तो सितंबर में 52 जिलों को 22 करोड़ 28 लाख 72 हजार 105 किलो गेहूं आवंटित हुआ। इन्हीं जिलों को फरवरी में 13 करोड़ 55 लाख 52 हजार 763 किलो गेहूं दिया गया है। यानी प्रदेशभर में आठ करोड़ 73 लाख 19 हजार 342 किलो गेहूं बच गया है। बचे हुए गेहूं की मात्रा इतनी है कि चंबल-ग्वालियर संभाग के सातों जिले श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, गुना के 11.44 लाख गरीबों (जिन्हें हर माह 1.35 करोड़ किलो गेहूं बंटता है) को छह माह तक बंट सकता है। इसी प्रकार बचा अनाज चार महानगरों भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के 12 लाख 13 हजार गरीब परिवारों (जिन्हें हर माह 1.52 करोड़ किलो गेहूं बंटता है) को साढ़े पांच माह तक दिया जा सकता है। मांग में कमी को देखते हुए शासन ने भी दुकानों का राशन आवंटन कम कर दिया है।

छह माह में गेहूं का आवंटन (किलो में)

महीना	श्योपुर में	पूरे प्रदेश में
सितंबर	23,21,721	22,28,72105
अक्टूबर	23,21721	18,08,26020
नवंबर	23,17,757	21,03,95882
दिसंबर	14,93,980	16,89,35292
जनवरी	12,71,293	13,55,52763
फरवरी	12,71,293	13, 55,52763

चावल का आवंटन (किलो में)

महीना	श्योपुर में	पूरे प्रदेश में
सितंबर	5,93,344	7,38,27800
अक्टूबर	5,39,344	6,12,39168
नवंबर	5,38,373	7,07,06361
दिसंबर	3,43,548	5,51,83743
जनवरी	2,88,908	4,45,20563
फरवरी	2,88,908	4,45,20563

> फिंगर प्रिंट से राशन वितरण अनिवार्य हुआ तो हर दुकान पर सैकड़ों राशनकार्ड से गेहूं-चावल लेना बंद हो गया। सितंबर की तुलना में फरवरी में 10 .50 लाख किलो गेहूं का आवंटन कम करना पड़ा है।
> – एनएस चौहान, जिला आपूर्ति अधिकारी, श्योपुर

> हम राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य असल गरीबों को लाभ देने का है। बीपीएल सर्वे पूरा होने के बाद इसमें और सुधार आएगा।
> – प्रद्युम्न सिंह तोमर, खाद्य आपूर्ति मंत्री, मप्र

बोल बम के जयकारों से गूंज रही सतपुड़ा की वादी

चौरागढ़ मेला... मन्नत पूरी होने पर एक इंच से लेकर दो क्विंटल तक के त्रिशूल शिव को अर्पित करते हैं श्रद्धालु

अच्छेलाल वर्मा, होशंगाबाद

सतपुड़ा की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी की वादियां इन दिनों बोल बम के जयकारों से गूंज रही हैं। त्रिशूल लिए हजारों श्रद्धालुओं में चौरागढ़ पहुंचने की धुन है। मप्र के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चौरागढ़ महादेव मंदिर मौजूद है, जहां महाशिवरात्रि तक चलने वाले आठ दिनी मेले के दौरान आसपास के जिलों सहित नजदीकी प्रदेशों से करीब छह लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शनों को पहुंचते हैं।

महाशिवरात्रि के दिन यहां अपार जनसमूह उमड़ेगा। मन्नत पूरी होने पर एक इंच आकार से लेकर दो क्विंटल तक वजनी त्रिशूल बाबा को अर्पित किए जाते हैं। पुजारी बाबा गरीबदास बताते हैं कि चौरागढ़ महादेव की मान्यता को लेकर अनेक कथाएं हैं। एक कथा यह भी है कि भस्मासुर को वरदान देने के बाद भगवान शिव ने यहां निवास किया था। चौरागढ़ में आदिवासियों की प्राचीन बसाहट रही है। चौरागढ़ मेला के नोडल अधिकारी जिला पंचायत सीईओ आदित्य सिंह ने बताया कि अब तक 50 हजार से अधिक त्रिशूल भेंट हो चुके हैं। महाशिवरात्रि पर यह संख्या कई गुणा बढ़ जाएगी।

छिंदवाड़ा जिले के जुन्नरदेव निवासी बंशीलाल खापरे करीब एक क्विंटल वजनी त्रिशूल भेंट करने चौरागढ़ आए हैं। वे अपने परिवार और मोहल्ले के 15 लोगों की मदद से यह त्रिशूल लेकर मंदिर की ओर नंगे पांव बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती से दो बसों से श्रद्धालु यहां त्रिशूल चढ़ाने आए हैं।

नजदीकी रेलवे स्टेशन पिपरिया है। पचमढ़ी से 10 किमी तक वाहन जाता है। यहां से चार किमी पैदल रास्ता है। फिर 325 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचते हैं। पचमढ़ी मध्यप्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण और अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुडा की रानी भी कहा जाता है। यहाँ घने जंगल, मदमाते जलप्रपात और निर्मल तालाब हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सतपुड़ा पर्वतमाला की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी में मौजूद है चौरागढ़ पहाड़ी

चौरागढ़ में महादेव को चढ़ाने के लिए इस तरह के त्रिशूल तैयार किए जा रहे हैं। नवदुनिया

दर्शन को पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु, महाशिवरात्रि पर उमड़ेगा अपार जनसमूह

मंदिर तक पहुंचने के लिए इस तरह की खड़ी सीढ़ियां चढ़ते हैं श्रद्धालु। नवदुनिया

महाशिवरात्रि पर शिवलिंग से हटाया जाता है पीतल का आवरण

अजय जैन, विदिशा : विदिशा की गंजबासौदा तहसील के उदयपुर गांव में भगवान शिव का एक हजार साल पुराना नीलकंठेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण परमार राजा उदयादित्य ने कराया था। मंदिर में पांच फीट ऊंचे चबूतरे पर तीन फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिस पर पीतल का आवरण चढ़ा रहता है। महाशिवरात्रि पर साल में एक बार इस आवरण को हटाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु लाल पत्थर से बने शिवलिंग के दर्शन करते हैं। शिवरात्रि पर यहां मेला भी लगता है, जिसमें एक लाख से अधिक लोग जुटते हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि मेले को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। करीब 51 फीट ऊंचे इस मंदिर के चारों तरफ पत्थर की मजबूत दीवारें बनी हुई हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से पर शिव, दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु और गणेश सहित अन्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं।

वर्ष के 364 दिन शिवलिंग पर रहता है पीतल का आवरण। नवदुनिया

साल में एक बार खुलते हैं रायसेन के किले में स्थित मंदिर के द्वार

अम्बुज माहेश्वरी, रायसेन : रायसेन में किले में मौजूद शिव मंदिर के द्वार महाशिवरात्रि ही पर खुलते हैं। 12वीं शताब्दी में निर्मित किले में इस दिन मेला भी लगता है। मंदिर के ताले खुलवाने के लिए कई आंदोलन हुए। 1974 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाशचंद सेठी तक को आना पड़ा था, लेकिन अब भी साल में केवल महाशिवरात्रि पर ही मंदिर के द्वार खुलते हैं। यह शिव मंदिर सोमेश्वर धाम के नाम से भी पहचाना जाता है। महाशिवरात्रि पर प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के ताले खोले जाते हैं और दिनभर पूजा-अर्चना व अभिषेक का क्रम चलता है। सांझ ढलते ही मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। दरअसल, यह कोई धार्मिक परंपरा न होकर प्रशासनिक व्यवस्था है। बताते हैं कि एक बार सांप्रदायिक तनाव के दौरान बनी परिस्थितियों के चलते प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया था।

किले पर स्थित मंदिर में विराजमान सोमेश्वर महादेव। फाइल फोटो

चीन भेजा जाएगा पंचकूला की ग्रामीण महिलाओं का बनाया मास्क

बड़ी जिम्मेदारी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव बक्शीवाला की महिलाएं तैयार कर रहीं उत्पाद

राजेश मलकानियां, पंचकूला

पंचकूला, हरियाणा के गांव बक्शीवाला के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इन दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण से निबटने में सक्षम मास्क बनाने में जुटी हुई हैं। पहली खेप में 10 लाख मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ रहे चीन को सप्लाई किए जाएंगे। दावा है कि इसके पहनने से वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है।

जनसंख्या नियोजन

बख्शीवाला की महिलाओं ने बताया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उन्हें 10 लाख मास्क तैयार करने का ऑर्डर मिला है। हिमाचल प्रदेश के परवाणू स्थित एक कंपनी को चीन से मास्क के लिए ऑर्डर मिला था, जिसने उन्हें यह काम सौंपा है।

बख्शीवाला के स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) की प्रधान स्वर्ण कौर ने बताया कि उक्त कंपनी के अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया और उसके बाद 10 लाख मास्क तैयार करने की जिम्मेदारी समूह को दे दी गई। अब समूह की महिलाएं मास्क तैयार करने में जुटी हुई हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े इस समूह से जुड़ी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। अब उनकी कोशिश रंग ला रही है।

गांव बक्शीवाला की स्वयं सहायता समूह को मिले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्वर्ण कौर ने गांव के सभी समूहों की महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। उनका कहना है कि शुरुआत में महिलाओं के सामने बड़ी मुश्किल सिलाई मशीनों की थी। इसके बाद फैसला किया गया कि जिन महिलाओं के पास मशीनें हैं, वह आपस में मिलकर काम कर लेंगी। दिन में कुछ महिलाएं और रात में कुछ महिलाएं मास्क तैयार करेंगी।

स्वर्ण कौर ने बताया कि वह रोजाना दो हजार मास्क तैयार करके दे रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस टारगेट को 5 हजार रोजाना तक ले जाया जाएगा। फिलहाल 40 महिलाएं मास्क बनाने के काम में जुटी हैं। उनकी कोशिश है कि समूह से और भी महिलाओं को जोड़ा जाए। पंचकूला की एडीसी मनीता मलिक ने बताया कि महिलाओं का यह प्रयास न केवल इन्हें आर्थिक मजबूती देगा, बल्कि आजीविका के नए रास्ते भी खोल रहा है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हरियाणा में पंचकूला के बख्शीवाला में मास्क तैयार करने में जुटी ग्रामीण महिलाएं। जागरण

हरियाणा में पंचकूला के बख्शीवाला में मास्क तैयार करने में जुटी ग्रामीण महिला। जागरण

दैनिक जागरण
सबरंग
साहित्य के...
नई दिल्ली, गुरुवार, 20 फरवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

अपनेपन की नमी में खिले सिंधी कपोलों पर हिंदी फूल

साहित्यिक धरोहर

सन् 1947 में हुए देश विभाजन के कारण सिंध के हिंदू सिंधी अदीबों की टोली भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ-साथ दिल्ली में भी आकर बसी। दिल्ली की उर्वरा भूमि में जैसे ही इन विस्थापित लेखकों को अपनेपन की नमी मिली तो उन्होंने अपनी कलम की स्याही से उत्पन्न बीजों का रोपण कर किया। कालांतर में इन बीजों से अंकुर फूटे और अंकुरों से निकली छोटी छोटी कोपलें...समाचार पत्र, पत्रिकाओं, स्मारिकाओं, कहानी, उपन्यास और नाटकों की किताबों एवं ग्रंथों के रूप में जिससे सिंधी साहित्यिक बगिया बनी। वर्तमान में दिल्ली में जो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं उनमें उल्लेखनीय हैं-संवाद सिंधी (संपादक-श्रीकांत भाटिया) सिंधी टुडे (संपादक-कमल खत्री) सिंधी गुलिस्तान (संपादक-अंजली तुलियानी) दिल-ए-सिंध (संपादक-महेश छावड़िया) और सिंधु धारा टाइम्स (संपादक-हेमनदास मोटवानी)। सभी अखबार आपको सिंधी रीति-परंपरा... साहित्य-समाज की जड़ों से जोड़े रखते हुए दिखेंगे। चूंकि हिंदी अब दिल्ली में रहने वाले सिंधी समाज की संगिनी बन चुकी है, अतः इन समाचार पत्रों में सिर्फ सिंधी भाषी नहीं बल्कि हिंदी में भी खूब सामग्री प्रकाशित होती है। जिसे देखकर सिंधी और हिंदी की सामाजिक समरसता झलकती है और यह समरसता साहित्यिक दृष्टि से सशक्त भी होती है। इन पत्रों की विशेषता है ये सिंधी समाज के दो प्रमुख त्योहार चेटीचंड व चालीहा उत्सव पर विशेषांक प्रकाशित करते हैं। सिंधी नव वर्ष चेटीचंड वर्ष प्रतिपदा के दिन व वरुण देव के अवतार पर झूलेलाल को समर्पित एवं चालीहा उत्सव प्रति वर्ष 16 जुलाई से 25 अगस्त के मध्य आयोजित होता है। पत्रिकाओं में सिंधी अकादमी द्वारा प्रकाशित सिंधु जोत व झिरमिर तथा राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद द्वारा प्रकाशित महक व पोपटड़ा का उल्लेख किया जा सकता है। इन पत्रिकाओं में सिर्फ वरिष्ठ स्थापित लेखक ही नहीं बल्कि नवांकुर भी लिख रहे हैं।

रवि टेकचंदानी, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिंधी भाषा व साहित्य के प्राध्यापक

स्वतंत्रता पर विभाजन की दास्तां : पत्रिकाओं का उल्लेख करते हुए दो पत्रिकाओं के सिंधी विशेषांकों का उल्लेख समीचीन है। एक साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य का सिंधी साहित्य विशेषांक व भारतीय अनुवाद परिषद का सिंधी अनुवाद विशेषांक। दोनों विशेषांकों को सिंधी हिंदी आदान-प्रदान की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान देना उपयुक्त होगा। सिंधी साहित्य में स्वतंत्रता व विभाजन के विषय पर केंद्रित अनेक रचनाएं लिखी गई हैं। कविता, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा के क्रम में हिंदी में प्रकाशित उल्लेखनीय पुस्तक है भारत देश के विभाजन की 'सिंधी कहानियां।' यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सिंधी पीठ द्वारा प्रकाशित की गई है। इग्नू के कुलपति प्रो नागेश्वर राव ने इसी पुस्तक पर मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि अनेक भाषाओं संस्कृतियों की धरती भारत सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता ही अद्भुत मिसाल है। भारतीय भाषाओं का कालजयी एवं श्रेष्ठ साहित्य इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिंधी और अन्य भाषाएं हिंदी के विकास में लगातार अपना योगदान दे रही हैं।

प्रेमचंद से भीष्म साहनी तक सिंधी में उपलब्ध : भारतीय अनुवाद परिषद की पत्रिका अनुवाद के सिंधी अनुवाद विशेषांक के अनुक्रम में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेख प्रकाशित किए गए हैं -सिंधी हिंदी अनुवाद सेतु, अनुवाद एक कला, अनुवाद और शैली, सिंधी हिंदी अनुवाद की समस्याएं, सिंधी तकनीकीवादों के मानवीकरण की आवश्यकताएं, सिंधी कहावतें आदि। सन् 1947 के पश्चात वर्तमान समय तक हिंदी से सिंधी तथा सिंधी से हिंदी में अनुदित रचनाओं का प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद के साथ साथ धर्मवीर भारती, जैनेंद्र कुमार, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरदयाल, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश भारती, चतुरसेन शास्त्री, मन्नू भंडारी, राजेंद्र सिंह बेदी, निर्मल वर्मा, आशापूर्णा देवी, भीष्म साहनी आदि लेखकों की रचनाएं सिंधी में अनुदित हो चुकी हैं। सिंधी लेखकों द्वारा हिंदी में रचित साहित्य की बानगी देखिए-सुंदरी आत्मचंदानी की रेखा (उपन्यास), गोविंद माटही की छुई मुई (उपन्यास), मोतीलाल जोतवाणी की पीली बाती पर (उपन्यास), आनंद सोमानी की अर्धवृत्त (उपन्यास), डॉ मुरलीधर जेटली सिंधी भाषा व्याकरण एवं प्रयोग, प्रेम प्रकाश स्वतंत्रता के पश्चात सिंधी नई कविता का संचयन, राशी रामाणी-सिंध इतिहास संस्कृति और साहित्य, लीला तलरेजर-जमीन पर जमीन की तलाश, जेठो लालवाणी-सिंधी नाटकों का इतिहास, अशोक भवनानी-साधना आदि।

दिल्ली वाले सिंधी भाषी : डॉ मुरलीधर कृष्णचंद जेटली, आनंद खेमानी, डॉ सरस्वती बाली, मोहिनी हिंगोरानी, सिंधु भाटिया, तीना श्रृंगी, मोहन हिमशानी, हीरो ठाकुर, शालिनी सागर, मेंघराज गुरनानी, डॉ मुरली भवनानी, रमेश लाल, इंदिरा टेकचंदानी, कंचन मोटवाणी आदि भले दिल्ली वाले सिंधी भाषी हैं लेकिन हिंदी भाषा में भी बराबर लेखन कर रहे हैं।

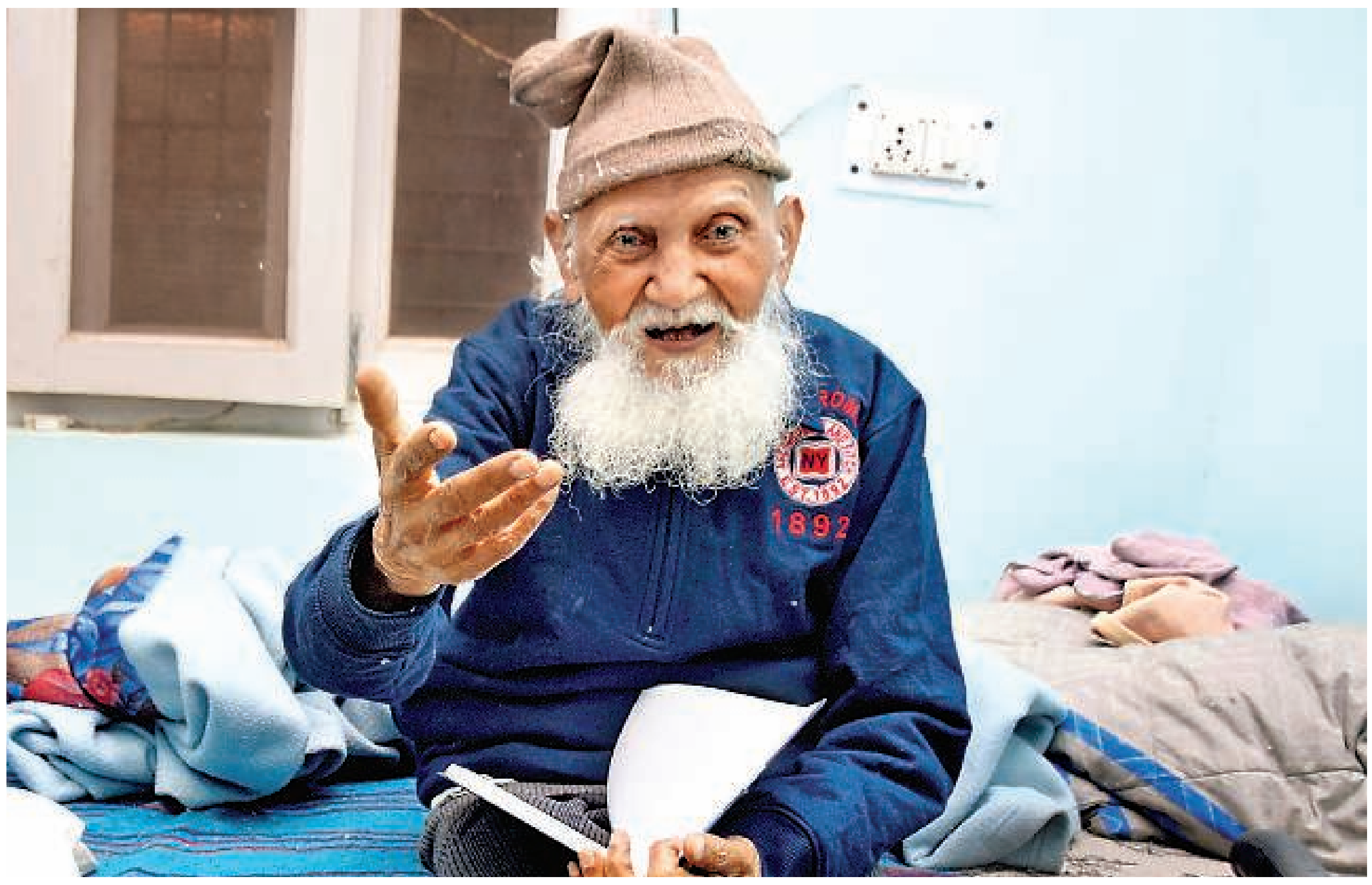

अपनी शर्तों पर जीता हूं, अपनी शर्तों पर लिखता हूं...अब दिल्ली वाला हूं दिल से दिल्ली की बात करता हूं...दैनिक जागरण से बातचीत के दौरान इसी अंदाज में नजर आए 90 वर्षीय विष्णुचंद्र शर्मा।

शर्तों पर चलना सिखाया दिल्ली ने

वरिष्ठ साहित्यकार विष्णुचंद्र शर्मा ने जीवन अपनी शर्तों पर जीया, यही मिजाज लेकर दिल्ली भी आए... और अपने तरीके से साहित्य गढ़ा, तभी साहित्यिक दुनिया में दुर्वासा भी कहलाए। भले एक सशक्त परिवार से ताल्लुक रहा, पर अपने दम पर दिल्ली में पहचान की ख्वाहिश लिए दिल्ली आए। कैसी रही उनकी दिलचस्प यात्रा, लेखन जगत ने कैसे उन्हें दुर्वासा नाम दिया, आपातकाल के दौर में कैसे लेखन किया...इसी पर विष्णुचंद्र शर्मा से रितु राणा ने विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

बातचीत

● दिल्ली ने आपको बुलाया था, या आप ही संभावना तलाशने आए थे?

-सन् 1960 की बात है, वाराणसी के काशी विद्यापीठ से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में मैं किसी सरकारी पद पर नौकरी के लिए साक्षात्कार देने आया था। साक्षात्कार तो हो गया लेकिन उसमें मुझसे पुलिस सत्यापन करने लगी, मैंने इससे इन्कार कर दिया। उसके बाद मैं अपने राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर बीरबल साहनी (पूर्व सांसद) उनके पास चला गया था। एक दिन मेरे पास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ सिंह आए थे वह भी मेरे परिचित थे। उन्होंने मेरा बैग उठाया और मुझे अपने साथ नई दिल्ली 15 कैनिंग लेन स्थित अपने निवास पर ले गए। मैं दिल्ली में सात वर्ष उन्हीं के साथ रहा था। उनके घर पर ही मैंने दिल्ली में अपनी पहली कहानी भी लिखी थी।

● नौकरी नहीं की, लेकिन फिर भी दिल्ली के ही होकर रह गए?

-नौकरी नहीं मिली लेकिन मुझे यहां के साहित्यिक वातावरण ने खूब आकर्षित किया। मैं दिल्ली में अशोक वाजपेयी, प्रभाकर वाजपेयी व दिल्ली के नए लेखकों के कारण ही रहने लगा था। नौकरी नहीं थी इसलिए खर्चा चलाने के लिए अशोक वाजपेयी मेरे लिए काम खोजते थे। मैं लेख लिखता था और वह मेरे लिए प्रकाशक तलाशते थे। एक बार प्रभाकर ने मुझे स्टेट्समैन के संपादक मिस्टर सरकार से भी मिलवाया था। शादी के बाद 1967 में पत्नी के साथ सरोजिनी नगर स्थित लोवर डिवीजनल क्लर्क क्वाटर में रहने चला लगा। वहां 'अपना पोस्टर' कहानी लिखी। पत्नी लेडी इरविन कॉलेज में पढ़ाती थीं तब उन्हें 100 रुपये मासिक वेतन मिला करता था। यहां मेरी मुलाकात राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता व श्रीकांत से हुई। मैं करोल बाग में एमए की छात्राओं को कोचिंग भी देने लगा था। 1972 में हम यमुनापार के सादतपुर क्षेत्र में आ गए। यहां बाग-बगीचा वहां मैंने बाग-बगीचा लगाया हुआ था। वहां मेरे पास बाबा नागार्जुन आया करते थे वे पहले यमुना विहार में रहते थे बाद में उन्होंने मेरे घर के पास ही घर ले लिया था।

● राजनीतिक परिवार से थे तो दिल्ली में नेताओं के बीच भी खूब साख रही होगी?

-हां, यह तो सत्य है कि मैं राजनीतिक परिवार से था। नाना पंडित रामनारायण मिश्र नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। पिता कृष्णचंद्र शर्मा सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध चिकित्सक, तत्कालीन प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में मंत्री और कांग्रेस की केंद्रीय काउंसिल के सदस्य थे। इसके अलावा वह काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्यों में भी रहे। वह लाल बहादुर शास्त्री व संपूर्णानंद आदि के घनिष्ठ मित्र भी थे। और बहन सत्यवती शर्मा भी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थीं। इन्हीं कारणों से दिल्ली में भी जब आया तो अमूमन लेखक व नेता जानते थे। एक किस्सा याद आता है जब दिल्ली में कभी किसी आयोजन में लाल बहादुर शास्त्री मुझे देखते थे तो तुरंत एक ही सवाल पूछते थे, तुम्हारा सामान कहां हैं? चलो मेरे साथ, लेकिन मैं दिल्ली में अपनी पहचान नाना और पिता जी के नाम के माध्यम से नहीं बल्कि अपने काम के माध्यम से बनाना चाहता था। इसलिए शास्त्री जी के बुलावे पर कभी उनके यहां रहने नहीं गया।

● फिर तो दिल्ली शहर को अलग ही अंदाज में जीया होगा?

-हां, पता नहीं कुछ तो इस साहित्यिक नगरी दिल्ली में ऐसा था कि एक बार यहां आने के बाद बनारस में भी मेरा मन नहीं लगा। जब मैं दिल्ली आया था तब रघुनाथ सिंह कश्मीर के बहुत बड़े कवि की रचना 'कल्हड़ा' का संपादन कर रहे थे। दिल्ली में मेरी दिनचर्या नियमित होती थी। रोजाना सुबह पांच बजे जागना, सैर करना और रघुनाथ सिंह के साथ उनके घर पर चाय पीना। उसके बाद सिर्फ किताबों की दुनिया दिखाई देती थी। रोज सुबह कनॉट प्लेस स्थित ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता था, वहां से किताबें भी लाता था। सचिवालय की लाइब्रेरी में जाता था वहां मेरे कुछ मित्र बन गए थे और परिचित भी पहले से थे जो मुझे 'न्यू अराइवल' वाली किताबें अपने नाम से लेकर देते थे। सभी जगह से किताबें लेता था और एक ही जगह बैठकर पढ़ने का शौक था वो था हिंदी भवन का बनारसीदास चतुर्वेदी केंद्र। वहीं दिन बीत जाता था। तो यही किताब और लेखन की दुनिया रही जिसने मुझे तब से अभी तक भी दिल से लगाए रखा है।

● स्मृति में आज भी उन दिनों की बातें आज भी जीवंत बैठी होंगी?

-एक बार मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में लेख देने गया मुझे उसके लिए महेंद्र भटनागर ने मात्र 60 रुपये दिए जबकि उससे पहले से ही मुझे लेख के लिए 300 रुपये मिल रहे थे। मुझे गुस्सा आया और मैंने 60 रुपये के चेक पर लिखकर बिड़ला जी के नाम भेजा दिया कि 'बिड़ला जी पान खाकर इस पर थूक दीजिएगा।' दूसरे दिन हिंदुस्तान टाइम्स के प्रबुद्ध अधिकारी ने मुझे बुलाया और मुझे चेक दिया और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि जितना विष्णु कहें उतने का चेक बनाकर दे दो और हिंदुस्तान टाइम्स में वह जो काम करना चाहें उन्हें नियुक्त कर लें। ऐसा शायद उन्होंने मेरे पिता व नाना की प्रतिष्ठा को देखते हुए कहा लेकिन मुझे किसी की दया नहीं चाहिए थी इसलिए मैं वहां से लौट गया। रेडियो, पत्रकारिता जगत में मुझे 'बिगड़ा हुआ लेखक' कहा जाता था जिस कारण बाबा नागार्जुन ने मुझे 'दुर्वासा' नाम भी दिया था। यह नाम मुझे मेरी क्रोधित प्रवृति के कारण मिला था।

● आपके साहित्यिक सफर में आए उतार-चढ़ाव?

-बनारस से ही मेरे साहित्यिक सफर की शुरुआत हो गई थी। जिसे दिल्ली आकर एक दिशा मिली। 1957 में चर्चित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का संपादन किया। और दिल्ली आकर सर्वनाम का संपादन भी किया। वहीं, बंगाल के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, मुक्तिबोध की जीवनी भी लिखी। कविता, उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण व आलोचना की करीब 50 पुस्तकें लिखी हैं। त्रिलोचन की एक कविता है 'दर्द कहां ठहरा सांसों-सी गली में लेटा रहा अर्थात दिल्ली की जिंदगी में हर कवि दर्द की गली में घूमने वाला था और मैं उनके दर्द का हिस्सेदार था। अपनी शर्तों पर जीवन जीने के कारण मैं दिल्ली में एक गुमनाम साहित्यकार बनकर रह गया क्योंकि मैंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की सिर्फ अपने मन की करता था। दिल्ली का एक लेखक वर्ग जहां मेरी 'दुर्वासा' व्यक्तित्व से डरता था। वहीं, दूसरा वर्ग मेरी तीखी आलोचना से डरता था।

● आपकी किताबों में किसी तरह दिल्ली शहर की खोज पूरी होती है?

-मैंने दिल्ली पर ज्यादा तो नहीं लिखा लेकिन 1975 में लगे आपातकाल पर दो रचनाएं लिखी थीं। जिसके लिए मुझे काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। मेरी उन रचनाओं ने पुलिस व प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। मैंने 'जनतंत्र' नाटक लिखा था जिसमें जनता पर हुए अत्याचारों द्वारा प्रशासन की पोल खोली गई थी। इसके अलावा 'तत्काल' नाम से कविता संग्रह लिखा था वह भी आपातकाल पर ही था। जेएनयू और दिल्ली विवि के छात्र भी मेरे पास उसकी प्रति लेने आते थे।

● फिर तो आपातकाल के समय काफी संघर्ष किया होगा?

-आपातकाल के समय मैं रात 12 बजे प्रेस वालों ने मुझसे 'तत्काल' की प्रति मंगाई थी। मैं उस वक्त ट्रेन में था बनारस से दिल्ली लौट रहा था। दिल्ली पहुंते ही एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे प्रति मांगने लगी, मैंने पूछा, कहां से आई हो वह बोली मैं खालसा कॉलेज में पढ़ती हूं मैंने उसे पूछा वहां के हिंदी व इतिहास के शिक्षक का नाम बताओ तो वह कुछ नहीं बोल पाई मैंने उसे फटकार कर भगा दिया। बाद में मुझे पता चला था कि वह लड़की सीआइडी से थी।

● साहित्यिक अड्डे कौन-कौन से थे जहां आप जाना पसंद किया करते थे?

-उन दिनों सभी साहित्यकार व कलाकारों की सबसे प्रिय जगह कॉफी हाउस या टी हाउस हुआ करती थी। वहां साहित्यकारों की आपस में खूब सकारात्मक बहस होती थीं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक नेमिचंद्र जैन, नरेश मेहता व श्रीकांत, रमेश गौड़, हंसराज रहबर व रमाकांत भी खूब आते थे।

● दिल्ली में किसी साहित्यकार से जुड़ा संस्मरण?

-केदारनाथ सिंह व नामवर सिंह मेरी हर रचना खरीदकर पढ़ते थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तभी मेरा तत्काल नाम से कविता संग्रह आया था था। उस समय नामवर सिंह जेएनयू में हिंदी विभाग और भाषा विभाग के प्रमुख थे। मैं उन्हें अपनी कविताएं पढ़ाने गया था मेरी कविताएं सुनने से पहले उन्होंने दो कप कॉफी मंगवाई और 32 पेज पढ़ने के बाद कहा कि विष्णु इस समय जेल में बड़ा दबाव चल रहा है। न जाने तुम्हारी यह कविताएं छपने से क्या बवाल हो जाए। जब वह किताब छपी तो मेरे पीछे सीआइडी वाले पड़ गए थे। मेरी इस किताब की 14 प्रतियां सीआइडी ने भी खरीदी थीं। एक बार मैं कनॉट प्लेस स्थित क्वालिटी रेस्त्रां में डॉ. भोलानाथ तिवारी के साथ बैठा था उन्होंने वहां मुझे आइसक्रीम खिलाई और पूछा कि हिंदी के तीन बड़े आलोचक के नाम बताओ। पहला नाम रामचंद्र शुक्ल का आया उसमें कोई मतभेद नहीं हुआ। दूसरा नाम पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिया उसके बाद जब मैंने तीसरा नाम राम विलास शर्मा का कहा तो उन्होंने डॉ.नगेंद्र का नाम लिया और यहां हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। एक संस्मरण और बताता हूं सन् 2001 में सादतपुर वाले घर में मैंने प्रमोद कुमार तिवारी से कहा था कि जेएनयू से ऐसे लड़के को लेकर आओ जो मुझे, स्पेनिश सिखाए तो उसके पीछे यह मंतव्य था कि सीधे स्पेनिश साहित्य को पढ़ना समझना चाहता हूं ताकि हमारी हिंदी में उसका बेहतर रूप आए। इनके अलावा दिल्ली में कांति मोहन, रामदीप गुप्ता, भगवान सिंह व रमा सिंह भी मेरे करीबी मित्र थे।

● नई दिल्ली जैसे पॉश इलाके को छोड़कर यमुनापार जैसे पिछड़े इलाके में रहे?

–जब मैंने यमुनापार के सादतपुर इलाके में जमीन ली, तब यहां बसावट कम थी और खूब पेड़–पौधे, खेत व जंगल थे। चारों ओर हरियाली का वातावरण था। यमुना नदी भी पास थी तब वह बहुत ही स्वच्छ व सुंदर दिखती थी। मैं काशी से था इसलिए यहां के प्राकृतिक वातावरण ने मुझे आकर्षित किया। और एक खास बात यह भी थी कि रमाकांत, नागार्जुन, करुण निधान, माहेश्वर जैसे रचनाकार लेखक भी रहने लगे थे जिससे साहित्यिक परिवेश भी बन गया था।

वेद शास्त्रों का ज्ञान व संस्कृत की दुर्लभ पुस्तकों का खजाना

फुर्सत का ज्ञान

जिस प्रकार ऋषि-मुनि के आश्रम में तोता और मैना भी जाप करना सीख जाते हैं ठीक उसी प्रकार आप संस्कृत अकादमी में आकर संस्कृत पढ़ना व बोलना सीख जाएंगे। यहां आकर आपको संस्कृत साहित्यिक परिवेश की अनुभूति होगी। संस्कृत में मंत्र जाप व धारा प्रवाह उच्चारण आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। झंडेवालान स्थित संस्कृत अकादमी की स्थापना 1987 में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई। इसी के साथ यहां संस्कृत के प्रचार-प्रसार व दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के लिए पुस्तकालय खोला गया। वेद व शास्त्रों का ज्ञान व संस्कृत की पुस्तकों का खजाना जो इस पुस्तकालय में है, वह दिल्ली के किसी अन्य पुस्तकालय में नहीं मिल सकता। अकादमी के सचिव डॉ. जीतराम भट्ट बताते हैं कि इस अकादमी की स्थापना विधानसभा स्थित पुराने सचिवालय में की गई थी। उसके बाद अकादमी वजीरपुर में शुरू की गई और 1998 से अब तक यह झंडेवालान में चल रही है। पुस्तकालय में संस्कृत की 9853 और हिंदी की 9789 व भारतीय विद्या पर आधारित 6774 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय में कोई भी आकर पढ़ सकता है और शोध के लिए पुस्तकों का उपयोग भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह पुस्तकालय निश्शुल्क है।

ताकि युवाओं तक पहुंचे संस्कृत : अकादमी में पुस्तकालय शुरू करने का उद्देश्य संस्कृत भाषा को आमजन व खासकर युवाओं तक पहुंचाना था। साथ ही संस्कृत शास्त्र की शिक्षा के प्रचार-प्रसार व शोध में लगे छात्रों को भी सुविधा देने का मकसद था। अकादमी द्वारा समस्त संस्कृत वाड्मय की सूक्तियों को संग्रहित कर प्रकाशित करने की वृहद योजना भी अद्वितीय है। यह कार्य स्थायी महत्व का है जिससे संस्कृतज्ञों और संस्कृत के जिज्ञासु दोनों को ही लाभ मिलेगा। वहीं इससे संस्कृत और संस्कृति को समझने में बहुत सहायता मिलेगी।

ताकि संस्कृति के साथ संस्कृत भी बढ़े...संस्कृत अकादमी में आपको दुर्लभ किताबें, ग्रंथ मिल जाएंगे। जागरण

हिंदी किताबों का भी खजाना

हिंदी के बड़े–बड़े लेखक जयशंकर प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, नागार्जुन, आदि लेखकों की पुस्तकों का भंडार है। इनमें दिल्ली जो एक शहर है, बिंदु–बिंदु विचार, चिदंबरा, खुली खिड़कियां, यमुना के बागी बेटे, स्कंदगुप्त, हिमालयन गजेटियर, ध्वनियों के आलोक में स्त्री, राष्ट्रभाषा का सवाल, पॉपुलर कल्चर, गणतंत्र का गणित, हिंदी उपन्यास कला आदि रोचक पुस्तकें पाठकों को खूब आकर्षित करती हैं।

दिल्ली संस्कृत अकादमी यहीं है संस्कृत पुस्तकालय

ऐसे पहुंचे

नजदीकी मेट्रो स्टेशन झंडेवालान वहां से पांच मिनट पैदल चलकर पुस्तकालय तक पहुंचा जा सकता है।

खुलने का समय

पुस्तकालय सुबह 9 : 30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुलता है। शनिवार और रविवार बंद रहता है।

बड़े-बड़े साहित्यकार भी यहां आते हैं पढ़ने : पुस्तकालय में स्वर्गीय डॉ. रमाकांत शुक्ल व प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जैसे बड़े-बड़े साहित्यकार भी पढ़ने आते थे। प्रोफेसर सत्यवृत शास्त्री जिन्होंने थाइलैंड की राजकुमारी को संस्कृत पढ़ाई थी वह भी यहां अक्सर आते रहते हैं। इनके अलावा डॉ. मंडन मिश्र आदि साहित्यकार भी यहां आते हैं। वहीं, भारतीय विद्या भवन के महेश महेश्वरी ने इसी पुस्तकालय में बैठकर वेदों पर शोध किया है। इस पुस्तकालय में जो संस्कृत के ग्रंथ हैं वह दिल्ली के किसी और पुस्तकालय में नहीं मिलेंगे। साथ ही संस्कृत संगीत संध्या डीवीडी, संस्कृत गीत-संगीत डीवीडी, संस्कृत श्लोक संगीत डीवीडी, एकल श्लोक संगीत डीवीडी भी यहां उपलब्ध हैं। इसके अलावा संस्कृत में लिखी 795 पांडुलिपियों का संग्रह भी यहां हैं।

रितु राणा

बॉलीवुड सितारों व नेताओं की पसंद जगदीश स्टूडियो

काम की दुकान

फ्लैश...लैंस...कैमरा एक अलग ही अद्भुत दुनिया होती है। एक पोज... एक शॉट...एक तस्वीर दिल जीत लेती है न... लेकिन उस एक तस्वीर के पीछे कैमरे का कितना कमाल होता है। लैंस कितनी बारीकी से आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है। वो लाइट, एक्शन और कैमरा...मोबाइल वाली सेल्फी और कैमरे की दुनिया से एकदम अलग होता है...। इसी कैमरे की दुनिया का एक नाम है दक्षिणी दिल्ली, खन्ना मार्केट का जगदीश स्टूडियो। जिसके दीवाने वैश्विक पटल पर भी हैं, सिने जगत में भी है और राजनीतिक पटल पर भी हैं। इस स्टूडियों की शुरुआत भी संघर्ष के साथ...विभाजन के संघर्ष के दिनों में ही हुई थी। दुकान के मालिक सुनील कुमार अरोड़ा बताते हैं कि विभाजन की त्रासदी झेलते हुए मेरे पिता जी जगदीश कुमार अरोड़ा पाकिस्तान के शेखुपुरा से दिल्ली पहुंचे थे। वैसे तो पिता जी को खन्ना मार्केट में सरकार से राशन डिपो खोलने के लिए दुकान मिली थी लेकिन उसमें उनका मन नहीं लगा। पिता जी को फोटोग्राफी का काम पसंद भी था और प्रतिष्ठित भी लगता था। सो उन्होंने 1950 में जगदीश स्टूडियो शुरू किया। मेरे पिता जी जगदीश अरोड़ा ने फोटोग्राफी की शुरुआत 635 बॉक्स कैमरा से की थी। ये सन् 1980 की बात है मैं महज 13 वर्ष का था तभी पिता जी की मृत्यु हो गई थी और मुझे दुकान की कमान संभालनी पड़ी। पहले तो यह परिस्थिति वश मजबूरी का काम लगता था लेकिन धीरे-धीरे इसमें दिलचस्पी बढ़ती गई और अब तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी जगदीश स्टूडियो खुल गया है। जिसे मेरे भाई प्रवीण अरोड़ा संभाल रहे हैं। वहीं अब हमारे बेटे भी इस काम में रुचि ले रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं।

खास और आम सभी की पसंद : बताते हैं कि पिता जी जिन 1975 में जिन कैमरों का इस्तेमाल करते थे उन्हें आज भी स्टूडियो में रखा हुआ है। आज स्टूडियो वेडिंग शूट के लिए देश व दुनिया में मशहूर है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों के बारे में कहते हैं कि देश की जानी-मानी हस्तियां तो उनके ग्राहकों की सूची में हैं साथ ही लंदन बैंकॉक, बाली, अमेरिका आदि देशों में भी लोग कैमरा खरीदने आते हैं। नेता, अभिनेता व बड़े-बड़े बिल्डर शामिल हैं। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ, स्मृति इरानी, बिरजू महाराज, गोपाल अंसल, गुलाम नबी आजाद, डॉ. नरेश त्रेहन, मीरा कुमार, मोंटेक सिंह आहलुवालिया, कपिल सिब्बल, टीवी कलाकार धीरज धूपर, विनी अरोड़ा आदि भी कैमरा खरीदने या किसी विशेष अवसर पर फोटो शूट के लिए आते रहते हैं। वहीं, डाबर व एरोस कंपनी के मालिकों की सभी पार्टी व कार्यक्रम भी हमारा स्टूडियो ही करता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की बेटी की शादी का शूट भी किया था। हाल ही में भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सलमान खान व अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस द्वारा आईफा पुरस्कार के अनाउंसमेंट का शूट भी किया था। यहां आप फोटोग्राफी के बाद अपनी फोटो को सुंदर व आकर्षक फ्रेम में भी फिट करा सकते हैं।

रितु राणा

जगदीश स्टूडियो...नेता ही नहीं बड़े-बड़े अभिनेता भी हैं इनकी फोटोग्राफी के कायल। जागरण

ऐसे पहुंचे

दुकान के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग है, यहां से 10 मिनट पैदल चलकर मार्केट तक पहुंचा जा सकता है।

दुकान खुलने का समय

रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 :30 बजे तक।

कोटक महिंद्रा बैंक को मिली आरबीआइ की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : निजी कर्जदाता कोटक महिंद्रा बैंक को प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम करने के लिए आरबीआइ की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले जनवरी के अंत में बैंक ने आरबीआइ से अपने प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 26 परसेंट तक कम करने की इजाजत मांगी थी। इसके साथ ही बैंक ने आरबीआइ के खिलाफ बांबे हाई कोर्ट में लंबित मुकदमें को वापस लेने की बात भी कही है। गौरतलब है कि वर्ष, 2018 में बैंक ने प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 19.70 परसेंट तक कम करने की इजाजत मांगी थी।

डीपीआइआइटी में 28 हजार स्टार्ट-अप पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले आठ महीनों में सात नए स्टार्ट-अप 100 करोड़ डॉलर का आकार लेने में कामयाब रहे हैं।
– पीयूष गोयल
वाणिज्य व उद्योग मंत्री

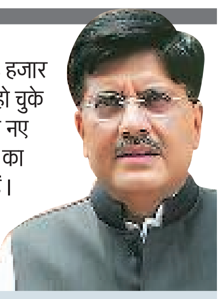

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
41,323.00	12,125.90	₹ 42,339	₹ 48,652	₹ 71.54	$ 58.69
▲ 428.62	▲ 133.40	▲ ₹ 462	▲ ₹ 1,047	(बदलाव नहीं)	

चीन से आयात पर निर्भरता कम करने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार 'मेक इन इंडिया' को बनाएगी चीन की सप्लाई चेन का विकल्प
- उद्यमी एवं सरकार दोनों चीन की मौजूदा स्थिति को मान रहे अवसर

भारतीय उद्योग एवं सरकार दोनों चीन से आने वाले इंटरमीडिएट गुड्स की सप्लाई चेन का विकल्प 'मेक इन इंडिया' के तहत तैयार करने में जुट गए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स और ऑटो पाट्र्स के खुदरा बाजार के लिए तो घरेलू कंपनियों को मैन्यूफैक्चरिंग के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस बात पर विचार हो रहा है कि चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए घरेलू उद्योग को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। औद्योगिक संगठन फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत में मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 189 अरब डॉलर (करीब 13.23 लाख करोड़ रुपये) के कच्चे माल का आयात किया गया था। इसमें चीन की हिस्सेदारी 15 फीसद से अधिक की थी। चीन में फैले कोरोना वायरस की वजह से भारत में कच्चे माल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। सरकार और उद्योग दोनों ही इसे मेक इन इंडिया को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, 'निश्चित रूप से यह समय भारत में मेक इन इंडिया की स्थिति को मजबूत करने का है। यह बड़ा अवसर है।' हालांकि उन्होंने

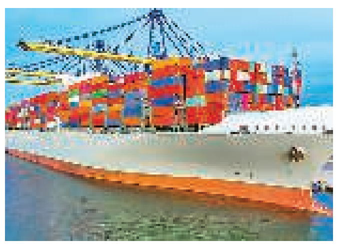

प्रतीकात्मक

इस बात का खुलासा नहीं किया कि चीन के हालात से उत्पन्न अवसर को भुनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

क्लोथ मैन्यूफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआइ) के प्रेसिडेंट राहुल मेहता कहते हैं कि सप्लाई चेन प्रभावित होने से अपैरल और फैब्रिक के ऑर्डर चीन की जगह घरेलू बाजार में शिफ्ट भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत घरेलू स्तर पर सप्लाई चेन को विकसित करना भारत के लिए लंबी अवधि में काफी लाभदायक होगा। रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यातक जिप, बटन व ब्लेंडेड फैब्रिक के लिए मुख्य रूप से चीन पर निर्भर करते हैं।

ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एकमा) के महानिदेशक विनी मेहता के मुताबिक भारत में 4.2 अरब डॉलर (करीब 29,400 करोड़ रुपये) के वैसे ऑटो कंपोनेंट का आयात किया जाता है जिसकी बिक्री खुदरा बाजार में होती है। कोरोना के बाद कंपोनेंट का आयात प्रभावित हो रहा है। अगर सरकार इस समय में साथ दे तो चीन की सप्लाई चेन को अपने देश में स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित ऑटो पाट्र्स विक्रेता संजीव गुलाटी के मुताबिक पुराने दोपहिया वाहनों व गाड़ियों में लगने वाले पाट्र्स की लोकल सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। इससे घरेलू स्तर पर कई पाट्र्स का निर्माण शुरू हो जाएगा।

मोबाइल फोन के पाट्र्स के निर्माण के लिए भी भारत में काफी गुंजाइश है। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर माह 7000-8000 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन कंपोनेंट का आयात चीन से करता है।

दुनिया की मैन्यूफैक्चरिंग पर कोरोना का ग्रहण

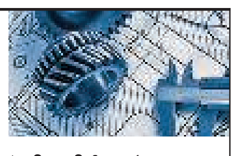

कोरोना संकट से लगने वाली सर्वाधिक चपत में चीन शीर्ष पर है। हालांकि इसका असर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि चीन मैन्यूफैक्चरिंग का सुपरपावर है। दुनिया में अगर सौ चीजें तैयार की जाती हैं तो उनमें से करीब 29 चीन में निर्मित होती है। ऐसे में चीनी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट से दुनिया प्रत्यक्ष रूप से हलकान हो रही है। तमाम देशों में इसके उत्पादों की आपूर्ति का संकट है। घरेलू क्षमता वाले कुछ देश इसे अवसर के रूप में ले रहे हैं तो पूरी तरह चीन पर आश्रित देश संकटग्रस्त हैं।

अमेरिका को पीछे किया

2010 से पहले तक मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका की बादशाहत थी। चीन ने अब इसे धकेल कर दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया है।

4 लाख करोड़ डॉलर : चीनी मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र का कुल मूल्य (2018 में)

30% चीनी अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी

11% अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी

मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी

(शीर्ष दस देश फीसद में)

देश	हिस्सेदारी
चीन	28.4
अमेरिका	16.6
जापान	7.2
जर्मनी	5.8
द.कोरिया	3.3
भारत	3.0
इटली	2.3
फ्रांस	1.9
ब्रिटेन	1.8
मेक्सिको	1.5

स्रोत : संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय विभाग

सोनभद्र की कोख में 3,000 टन सोने का अयस्क

प्रशांत शुक्ल, सोनभद्र

- जीएसआइ की टीम द्वारा पुष्टि के बाद खनिजों की नीलामी के लिए शुरू हुई जियो टैगिंग
- सोन पहाड़ी पर 2943.25 टन व हरदी ब्लाक में 646.15 किलो मिला सोने का भंडार
- एंडालुसाइट व पोटाश अयस्क का भी मिला भंडार, अब यूरेनियम की शुरू हुई खोज

सोनांचल की कोख खनिज संपदा से लबालब है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) को सोनभद्र के दो स्थानों पर करीब तीन हजार टन सोने का अयस्क मिला है। इससे करीब डेढ़ हजार टन सोना निकाला जा सकेगा। इसी तरह जीएसआइ ने 90 टन एंडालुसाइट, नौ टन पोटाश, 18.87 टन लौह अयस्क व 10 लाख टन सिलेमिनाइट के भंडार की भी खोज की है। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक रोशन जैकब ने मुख्य खनिजों की नीलामी के आदेश जारी कर दिए हैं।

चिह्नित खनिज स्थलों की जियो टैगिंग के लिए गठित सात सदस्यीय टीम 22 फरवरी तक खनन निदेशक को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य को जिम्मेदारी सौंपते हुए केंद्र सरकार ई-निविदा जारी करने का निर्देश देगी।

निविदा को हरी झंडी मिलने के बाद खनन को अनुमति मिलेगी। वरिष्ठ खान अधिकारी केके राय के मुताबिक जीएसआइ की टीम लंबे समय से यहां काम कर रही थी। अब नीलामी को लेकर आदेश आ चुका है। इसी क्रम में जियो टैगिंग शुरू की गई है। जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले में यूरेनियम के भंडार का भी अनुमान है, इसके लिए केंद्रीय कुछ अन्य टीमें खोज में लगी हैं।

जीएसआइ के मुताबिक सोनभद्र की सोन पहाड़ी पर 2,943.26 टन सोना और हरदी ब्लॉक में 646.15 किलो सोने का अयस्क है। इसी प्रकार पुलवार ब्लॉक में दो स्थानों पर 12.7 टन और 22.16 टन तथा सलइयाडीह ब्लॉक में 60.18 टन एंडालुसाइट का भंडार है। पटवध ब्लॉक में 9.15 टन पोटाश व भरहरी ब्लॉक में 14.87 टन लौह अयस्क और छिपिया ब्लॉक में 9.8 टन सिलीमैनाइट के भंडार की खोज की गई है।

कोरोना प्राकृतिक आपदा घोषित

फायदा ▶ ट्रेडर्स को बड़ी राहत, छोटे निर्यातकों को बैंकों के री-पेमेंट पर रियायत संभव

पोर्ट पर तत्काल क्लीयरेंस की सुविधा भी, बुधवार को वित्त मंत्री के साथ बैठक में निर्यातकों ने रखी कई मांगें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के कारण प्रभावित व्यापार से पीड़ित कारोबारियों को बुधवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ी राहत देने की घोषणा की गई। वित्त मंत्रालय ने कोरोना को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखने का एलान किया। इसके तहत कोरोना की वजह से माल की सप्लाई प्रभावित होने पर कांट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी या उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इन कारोबारियों को वित्तीय संस्थानों की तरफ से वैसे ही मदद दी जाएगी जैसी मदद प्राकृतिक आपदा के दौरान उद्योग जगत को दिया जाता है। इसका फायदा उठाने के लिए कारोबारियों को संबंधित संस्थानों या फर्म को सूचित करना पड़ेगा कि कोरोना की वजह से उनका काम प्रभावित हुआ है।

कोरोना की मार से कारोबार जगत में

प्रतीकात्मक

उपजी चुनौतियों से निपटने के लिए पिछले दो दिनों से मंत्रालयों में चल रही कवायद के बाद बुधवार को देर शाम वित्त मंत्रालय की तरफ से मेमोरेंडम जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि, 'चीन या किसी दूसरे देश में कोरोना वायरस फैलने से सप्लाई चेन में आए व्यवधान को लेकर संशय ज्की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसे प्राकृतिक आपदा माना जाएगा।' यह मेमोरेंडम केंद्र सरकार के सभी विभागों व मंत्रालयों को भेजा गया है। गत मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्लाई चेन में हो रहे व्यवधानों से निपटने के लिए उद्योग जगत के साथ लंबी बैठक की थी। बुधवार को भी वित्त मंत्री ने निर्यातकों के साथ तो नीति आयोग में शीर्ष अधिकारियों के साथ इस मामले में बैठक की गई। कारोबारियों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से उन्हें डिफाल्टर घोषित होने का खतरा टल गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही छोटे निर्यातकों को बैंकों के री-पेमेंट में रियायत दी सकती है। वहीं उन्हें पोर्ट पर भी माल की आवाजाही के लिए तत्काल क्लीयरेंस की सुविधा मिल सकती है। चीन में कोरोना वायरस फैलने से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को निर्यातकों की बैठक बुलाई थी। चीन से आने वाले कच्चे माल की कमी से निर्यातकों के ऑर्डर की डिलिवरी में देरी की आशंका है। वहीं कच्चे माल की कमी होने से निर्यातकों की लागत भी बढ़ सकती है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने बताया कि वित्त मंत्री के साथ बैठक में कोरोना फैलने से भारतीय व्यापार पर पड़ने वाले असर की व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि फियो की तरफ से वित्त मंत्री के समक्ष निर्यातकों की ओर से कई मांगें कई रखी गईं। इनमें छोटे निर्यातकों को बैंक के रिपेमेंट में रियायत देने के साथ उन्हें जीएसटी विभाग द्वारा उन्हें रिस्की जोन में नहीं रखे जाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि निर्यातकों की तरफ से बैंकों को पेमेंट में देरी से उन्हें एनपीए श्रेणी में रख दिया जाता है। वहीं, पोर्ट पर तत्काल क्लीयरेंस की सुविधा की भी मांग की गई ताकि माल की आवाजाही में कोई विलंब नहीं हो। सराफ ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार की तरफ से निर्यातकों की मांगें मान ली जाएंगी।

दूसरी तरफ टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी ने भी चीन में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति एवं उससे उपजी व्यापार की नई संभावनाओं पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इसमें टेक्सटाइल मंत्रालय के सचिव व अधिकारियों के साथ वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों, सभी निर्यात संबर्धन परिषद के अध्यक्षों के और बाइंग एजेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्पेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सिद्ध नाथ सिंह ने सरकार को कालीन उद्योग की समस्या तथा कालीन उद्योग के लिए नई संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

एजीआर बकाया के दोबारा आकलन में जुटा दूरसंचार विभाग

- अलग-अलग सर्किल की गणना में नहीं है समानता
- टेलीकॉम कंपनियां पहले ही कर चुकी हैं इसकी शिकायत

नई दिल्ली, प्रेट्र : एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) को लेकर टेलीकॉम सेक्टर में तमाम उठापटक के बाद नए सिरे से इसकी गणना किए जाने की बात सामने आई है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने संबंधित अधिकारियों को फिर से एजीआर आकलन करने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने अलग-अलग सर्किल ऑफिसर्स की गणना में अंतर पाया है। इसके कारण फिर से बकाया का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्यूनिकेशन अकाउंट्स को एक दिशानिर्देश जारी करके दोबारा आकलन करने को कहा है। इसके लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 15 दिन के भीतर भुगतान संबंधी कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया है।

इस बीच, बुधवार को भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल और वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बिड़ला ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की मदद के बगैर मौजूदा हालत में कंपनी को चलाते रहना संभव नहीं है और वे इसे इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत दिवालिया प्रक्रिया में ले जाने के पक्षधर हैं। हालांकि दोनों दिग्गजों ने मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताया। मित्तल ने सिर्फ इतना कहा कि टेलीकॉम सेक्टर पिछले करीब साढ़े तीन वर्षों से दबाव में है और सरकार को इसके स्थायित्व के बारे में विचार करना चाहिए। मित्तल ने इससे पहले बुधवार को टेलीकॉम सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात की, जिनसे बिड़ला मंगलवार को मिल चुके हैं।

इससे पहले पिछले वर्ष चार और 13 दिसंबर को विभाग की ओर से डेबिट वाउचर रिपोर्ट (डीवीआर) का फिर से आकलन करने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन उस दौरान री-असेसमेंट करने के बाद भी टेलीकॉम कंपनियों की शिकायत दूर नहीं की जा सकी थी। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कई डीवीआर को लेकर आपत्ति जाहिर की है। बताया जा रहा है कि सभी सर्किल ऑफिसर्स ने एजीआर आकलन में एक जैसी विधि नहीं अपनाई है। इसके चलते डीओटी को फिर से आकलन का आदेश जारी करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए यह कार्य जल्द समाप्त करने को कहा गया है।

मौजूदा गणना के मुताबिक एयरटेल के ऊपर करीब 35,586 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़, टाटा टेलीसर्विसेज पर 13,800 करोड़, बीएसएनएल पर 4,989 और एमटीएनएल पर 3,122 करोड़ रुपये बकाया है।

बढ़ सकती है मुकदमेबाजी

नई दिल्ली, आइएएनएस : एनालिस्ट कंपनी क्रेडिट सुइश ने कहा है कि एजीआर मामले में भारतीय टेलीकॉम कंपनियों की ओर अभी और मुकदमेबाजी संभव है। इस दौरान कंपनी ने उम्मीद जताई कि एयरटेल इस गहरे संकट से बाहर निकलने में सफल हो सकती है, जबकि वोडाफोन आइडिया पर संकट के बादल सबसे गहरे हैं। एयरटेल ने हाल में ही एजीआर भुगतान के लिए 300 करोड़ डॉलर (करीब 21,000 करोड़ रुपये) जुटाए थे। कुल एजीआर का 75 परसेंट हिस्सा ब्याज और जुर्माने के रूप में है। इसे लेकर विवाद संभव है, जिससे मुकदमेबाजी होने की आशंका है।

जेल व जुर्माना से उद्योग जगत चिंतित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- उपभोक्ता कानून के लागू होने में लगेगा डेढ़ से दो महीने का समय
- 12 वर्षों की जेल और 50 हजार रुपये तक का लगेगा जुर्माना

उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 के कुछ नये व सख्त प्रावधानों को लेकर उद्योग जगत ने चिंता जताई है। संसद के दोनों सदनों से पारित इस नए कानून की नियमावली बनाने को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को उद्योग जगत समेत सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया। चर्चा के दौरान उद्योग जगत ने कानून में 12 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने पर अफसोस जताया।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पासवान ने बताया कि उद्योग संगठनों ने कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। इनमें शिकायतों में पारदर्शिता होने की बात प्रमुख है। उन्होंने शिकायतों के निपटारे में मध्यस्थता के प्रावधान की प्रशंसा भी की। ई-कॉमर्स पर नियंत्रण रखने के लिए जो

प्रतीकात्मक

प्रावधान किए गए हैं, उन पर भी लंबी चर्चा हुई। उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रामक प्रचार जैसे मुद्दे पर कंपनियों की नकेल कसने और ब्रांड एंबेसडर बनने वाली हस्तियों को सावधान किया गया है।

बैठक में देश के सभी शीर्ष उद्योग संगठनों के साथ बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता मंत्रालय के आला अफसरों ने भी भाग लिया। चर्चा के दौरान उद्योग क्षेत्र के लोगों ने सरकार को भरोसा दिया कि उनकी ओर से स्व नियमन तंत्र विकसित किये जाएंगे। कानून के प्रावधानों को सही तरीके से लागू करने वाले नियमों को बनाने में वे सरकार के साथ रहेंगे। पासवान ने बताया कि उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि उनकी ओर से वैश्विक स्तर के बेहतर प्रावधानों को लागू करने के प्रयास किये जाएंगे। हालांकि उन्होंने जोर देकर सरकार से कहा कि शिकायतों में पारदर्शिता कायम करने की जरूरत है। गठित किए जाने वाले उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में जांच के साथ जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। दंड के प्रावधानों पर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई।

टेक्नोलॉजी चुनने में एकरूपता लाएगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मंत्रालय सहित सभी सरकारी विभागों, पीएसयू को इस्तेमाल से पहले टेक्नोलॉजी ग्रुप से लेनी पड़ेगी राय
- अधिकार प्राप्त टेक्नोलॉजी ग्रुप के गठन को कैबिनेट दी मंजूरी, 12 सदस्यीय होगा यह ग्रुप

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ ही सरकार अब इसकी गुणवत्ता को भी परखेगी। इसके तहत कोई भी मंत्रालय या सरकारी विभाग मनमर्जी से किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके लिए पहले उन्हें सरकार की ओर से गठित अधिकार प्राप्त टेक्नोलॉजी ग्रुप से सलाह लेनी होगी। यह ग्रुप नवीनतम टेक्नोलॉजी के बारे में समय-समय पर सलाह देगा, तकनीकी उत्पादों की मैपिंग करेगा, सरकारी अनुसंधान और विकास संगठनों में विकसित टेक्नोलॉजी के दोहरे उपयोग के वाणिज्यीकरण जैसे मुद्दों पर काम करेगा। साथ ही यह ग्रुप देशभर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में चल रहे शोध कार्यों पर नजर रखेगा व उद्योग और समाज की जरूरत को समझते हुए जरूरी शोध को लेकर भी सलाह देगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते

प्रतीकात्मक

हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि अधिकार प्राप्त इस टेक्नोलॉजी ग्रुप में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। मौजूदा समय में सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन हैं। सरकार ने इस टेक्नोलॉजी ग्रुप को गठित करने का यह फैसला सरकारी विभागों में अलग-अलग स्तर पर इस्तेमाल में ली जा रही अलग-अलग टेक्नोलॉजी को देखते हुए लिया है। मौजूदा समय में तकनीक के बढ़े इस्तेमाल से कामकाज में पारदर्शिता व तेजी आई है। कई बार विभाग बिना परखे और एक्सपर्ट सलाह के ही अपने स्तर पर टेक्नोलॉजी खरीदने व इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे होता यह है कि बाजार में बेहतर व सस्ती टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बाद भी विभाग उन तक नहीं पहुंच पाते। अधिकार प्राप्त टेक्नोलॉजी ग्रुप अब ऐसी चिंताओं से बचाएगा। मंत्रालय को टेक्नोलॉजी आधारित नीति बनाने में भी यह ग्रुप मदद करेगा। आगे चलकर अलग-अलग स्तरों और जगहों पर हो रहे शोध कार्यों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना भी योजना में शामिल है।

देशभर में बनेंगे 10 हजार किसान उत्पादक संगठन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : छोटे किसानों को संगठित कर खेती करने के लिए सरकार ने देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार कुल 4,496 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से 2024 तक इन एफपीओ का गठन करेगी। सरकार हर एफपीओ को उसके गठन के अगले पांच साल तक मदद देगी। इसके लिए 2024-25 से 2027-28 की अवधि में एफपीओ के सहयोग हेतु 2,369 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस तरह इस योजना पर कुल खर्च 6,865 करोड़ रुपये होगा।

बैठक के बाद केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना को लागू करने में तीन सरकारी एजेंसियों स्माल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की अहम भूमिका रहेगी। योजना में एक जिला, एक उपज समेत कई अन्य स्कीमों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। एक एफपीओ में शामिल किसानों की संख्या मैदानी क्षेत्रों में 300 और पहाड़ी राज्यों में 100 होगी। इन संगठनों को कई तरह की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। तोमर ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो एफपीओ गठित किए जाएं। देश के चिन्हित 115 आकांक्षी जिलों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के लिए नाबार्ड 1000 करोड़ और एनसीडीसी 500 करोड़ रुपये का क्रेडिट फंड उपलब्ध कराएंगे।

हलचल

वित्त मंत्री ने दिया है कोरोना के दुष्प्रभाव से निपटने का आश्वासन, सेंसेक्स 429 अंक और निफ्टी 133 अंक सुधरकर हुए बंद

कोरोना पर सरकार के आश्वासन से शेयर बाजार मजबूत

मुंबई, प्रेट्र : कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा कारोबारी जगत को आश्वासन देने से शेयर बाजारों का मनोबल बढ़ा है। लगातार चार सत्रों की गिरावट के बाद बुधवार को देश के प्रमुख शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 428.62 अंकों के उछाल के साथ 41,323 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 133.40 अंकों की तेजी देखने को मिली। यह 12 हजार के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करके 12,125.90 पर स्थिर हुआ।

सेंसेक्स पैक में बजाज फाइनेंस, एचयूएल, आरआइएल, ओएनजीसी और एचडीएफसी के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर सन फार्मा, टीसीएस, एयरटेल, एलएंडटी और इंडसइंड बैंक के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में एनर्जी, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस कंपनियों के स्टॉक्स में 2.37 परसेंट तक की तेजी देखी गई। इस दौरान बीएसई के सभी

प्रतीकात्मक

सेक्टोरल स्टॉक्स हरे निशान पर बंद हुए।

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फार्मा, टेक्सटाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी हार्डवेयर सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस के इकोनॉमी पर प्रभाव के बारे में चर्चा की और इससे निपटने के लिए पुख्ता उपाय करने का आश्वासन दिया था। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने को लेकर सरकार द्वारा आश्वासन मिलने से घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक संदेश गया है। इसके अलावा चीन में कोरोना के नए मामलों में कमी आने की खबरों से भी बाजारों का उत्साह बढ़ा है।

इन शेयरों में रही हलचल

वोडाफोन आइडिया : सरकार द्वारा बैंक गारंटी नहीं भुनाने की खबरों के बाद इस टेलीकॉम कंपनी के शेयरों में 40 परसेंट तक का उछाल देखने को मिला। इस दौरान बीएसई में कंपनी के शेयर 38.28 परसेंट उछाल के साथ 4.19 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बिके। वहीं एनएसई में यह 40 परसेंट की छलांग के साथ 4.20 रुपये के भाव पर बंद हुआ। इससे पहले दूरसंचार विभाग ने तय समय पर एजीआर का भुगतान नहीं करने पर कंपनी की बैंक गारंटी भुनाने की बात कही थी। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि उसके पास साझा करने के लिए कोई सूचना लंबित नहीं हैं। कंपनी सभी सूचनाएं सार्वजनिक कर चुकी है। कंपनी के शेयरों में इस तेज उछाल को लेकर शेयर बाजारों ने वोडाफोन आइडिया से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे।

श्री सीमेंट : एनएसई के निफ्टी-50 सूचकांक में प्रवेश पाने की खबर के बाद कंपनी के शेयरों में खूब बिकवाली हुई। इस दौरान बीएसई में कंपनी के शेयर 2.55 परसेंट उछाल के साथ 25,222.90 रुपये और एनएसई में 2.58 परसेंट की तेजी के साथ 24,390 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। मंगलवार को एनएसई ने बताया था कि वह निफ्टी-50 से यस बैंक को निकालने की तैयारी कर रहा है। इसकी जगह श्री सीमेंट को रखा जाएगा।

सोना-चांदी के भाव में उछाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : बुधवार को स्थानीय सराफा बाजारों में तेजी का रुख रहा। इस दौरान सोना 462 रुपये चढ़कर 42,339 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। वहीं चांदी के भाव में 1,047 रुपये का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह 48,652 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिकी। जानकारों के मुताबिक बेहतर ग्लोबल कीमतों का असर घरेलू सराफा बाजारों पर देखने को मिला। यही कारण है कि सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,606.60 डॉलर और चांदी 18.32 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

500 शिपमेंट गैरकानूनी दवाओं के अमेरिका में प्रवेश करने से रोके हैं भारत–अमेरिका ने अपने पहली तरह के अभियान में। इस ऑपरेशन के दौरान दोनों देशों के जांचकर्ताओं ने 800 से ज्यादा शिपमेंट की जांच की। उन्होंने करीब 50 अलग–अलग एफडीए रेगुलेटेड उत्पादों की पहचान की।

न्यूज गैलरी

बोइंग 737 मैक्स विमानों के ईंधन टैंक में मिला कचरा

पेरिस : लगातार दो भीषण दुर्घटनाओं को लेकर विश्वभर में चर्चा के केंद्र में आए बोइंग 737 मैक्स विमानों के ईंधन टैंक में कचरा मिलने की जानकारी सामने आई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कंपनी द्वारा तैयार 400 नए मैक्स विमानों की गहन जांच–पड़ताल के दौरान कुछ विमानों के ईंधन टैंक में औजारों समेत धात्विक कचरा पाया गया। आशंका जताई गई है कि यह कचरा शॉर्ट सर्किट और आग लगने का कारण बन सकता है। पिछले साल 737 मैक्स विमानों से जुड़ी दो दुर्घटनाओं में 346 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटनाओं को लेकर बोइंग विमानों पर अंगुली उठने के बाद विश्व भर में इसकी उड़ानें बंद कर दी गई थीं। बोइंग की ओर से कहा गया है कि ईंधन टैंक में कचरा मिलने की जानकारी पर तुरंत काम करते हुए इस समस्या को दूर कर दिया गया है। विमानों के निर्माण को लेकर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। (एपी)

भ्रष्टाचार मामले में द. कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति बाक को जेल

सियोल : दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति ली म्यूंग–बाक को बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया गया। यह मामला 2008 से 2013 तक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए सैमसंग कंपनी से रिश्वत लेने से जुड़ा है। इस मामले में उन्हें 2018 में भी जेल भेजा गया था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। बुधवार को 17 साल की सजा का एलान करते हुए अदालत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने कृत्य पर कोई पश्चाताप नहीं जताया। (एएफपी)

ऑस्ट्रेलिया में दो छोटे विमानों की टक्कर में चार की मौत

पर्थ : ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणपूर्वी हिस्से के आसमान में बुधवार को दो छोटे विमान आपस में टकरा गए। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न से कुछ दूर हुई इस दुर्घटना में दोनों विमान में सवार चार लोगों की मौत हो गई। विक्टोरिया प्रांत की पुलिस जांच कर रही है। (एपी)

व्हाइट हाउस में प्रस्तुति देंगे भारतवंशी कॉमेडियन मिन्हाज

वाशिंगटन : भारतवंशी स्टैंडअप कॉमेडियन हसन मिन्हाज व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों के रात्रिभोज में फिर अपनी प्रस्तुति देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक मिन्हाज के माता–पिता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से अमेरिका आए थे। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले तीन वर्षों से इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के बावजूद शिरकत नहीं कर रहे हैं। इस बार भी आने की संभावना नहीं है। (प्रेट्र)

ब्रिटेन की नई वीजा नीति घोषित भारतीयों को होगा ज्यादा लाभ

एलान ▸ श्रम आधारित रोजगारों के लिए घटाए गए अवसर

एक जनवरी 2021 से लागू लागू होगी नीति, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश भी होंगे प्रभावित

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को नई वीजा नीति घोषित कर दी। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने कहा, नई नीति दुनिया के सबसे होशियार और सबसे अच्छे पेशेवरों को ब्रिटेन आने के लिए आकर्षित करेगी। नई नीति में श्रम आधारित रोजगारों और सामान्य कामकाज करने वाले लोगों के ब्रिटेन आने को हतोत्साहित किया गया है। उनके लिए जारी होने वाले वीजा की संख्या कम की गई है। भारतीय उद्यमियों और छात्रों ने ब्रिटेन की नई वीजा नीति का स्वागत किया है। कहा है, इससे कुशल पेशेवरों का आगमन आसान होगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

जाहिर है नई नीति का भारत के पेशेवरों को बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि भारतीय पेशेवर अंग्रेजी भाषा में दक्ष होते हैं जबकि अन्य प्रमुख देशों के लोगों को अंग्रेजी को लेकर मुश्किल होती है। ब्रिटेन में वीजा लेने के लिए अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना, प्रमुख शर्त होती है। नया वीजा सिस्टम एक जनवरी, 2021 से लागू होगा। 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलगाव के बाद ब्रिटेन में 31 दिसंबर तक संक्रमण काल लागू रहेगा, इस दौरान यूरोपीय यूनियन के बाकी बचे 27 देशों के लोग वहां बिना वीजा के आते-जाते रहेंगे। एक जनवरी, 2021 से किसी भी देश के आगंतुक के लिए ब्रिटेन में समान नियम होंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय पेशेवरों को मिलने की उम्मीद है। हाल के वर्षों में भी ब्रिटेन का वर्क वीजा प्राप्त करने वालों में भारतीय ही अग्रणी रहे हैं।

पटेल ने कहा, यह दिन ब्रिटेन के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। अब हम अपने देश में बेरोक-टोक आना-जाना बंद करने जा रहे हैं। इससे हमारी सीमाओं पर हमारा नियंत्रण स्थापित होगा। नई नीति लागू होने से ब्रिटेन में मनमाना आव्रजन रुकेगा। इससे ब्रिटेन और यहां रहने वाले लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, हम दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समुदाय के लिए लाभदायक होगा।

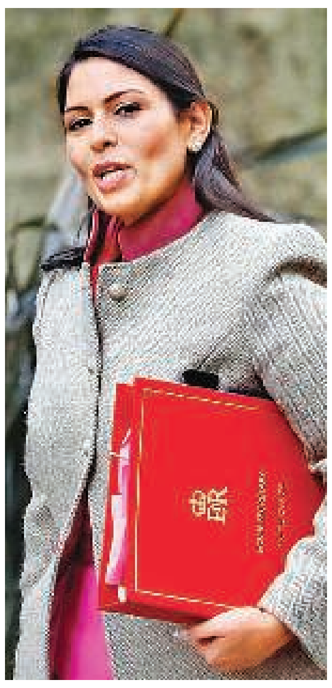

ब्रिटिश गृहमंत्री प्रीति पटेल की फाइल फोटो। एएफपी

'नागरिकता विहीन करने से रोकने को सभी उपाय करें'

इस्लामाबाद, प्रेट्र : भारत के अंदरूनी मामले में दखल देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा है कि किसी को भी नागरिकता विहीन करने से बचाव के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। पाकिस्तान दौरे पर आए गुतेरस ने यह बात भारत के नागरिकता संशोधन कानून (एनआरसी) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की बाबत कही है।

एक अखबार से साक्षात्कार में गुतेरस ने कहा, भारत में राष्ट्रीयता को लेकर कानून बदला है। इसे लेकर वह चिंतित हैं। उन्होंने कहा, इस इलाके में संयुक्त राष्ट्र सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उसकी इकाई यहां पर कार्यरत है। शरणार्थियों के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त भी इलाके में काफी सक्रिय हैं। आशंका है कि भारत में बने नए कानूनों से लोगों की नागरिकता छिनेगी और शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी। गुतेरस ने कहा, यह स्थिति रोकी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसका कोई देश हो। इसलिए किसी की नागरिकता विहीन करने से पहले उसके बचाव के हर संभव उपाय करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत में बीते दिसंबर में सीएए प्रभाव में आ चुका है। इसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित हो रहे हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें भारत में रहने वाले मुस्लिमों की नागरिकता को लेकर कोई बिंदु नहीं है।

पाक की अदालत ने हिंदू लड़की का जबरन निकाह रद किया

पहली बार
- सिंध प्रांत की महक कुमारी को कोर्ट ने नाबालिग माना
- पुलिस अफसरों को अपराध में लिप्त सभी लोगों पर कार्रवाई को कहा

कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदायों की नाबालिग बच्चियों को अगवा कर उनसे जबरन इस्लाम कुबूल कराना और निकाह पढ़वाना आम बात हो गई है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंध प्रांत की एक नाबालिग हिंदू लड़की महक कुमारी की शादी को पाकिस्तान की स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है।

बुधवार को पाकिस्तान के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलाम अली कनासरो ने पहली बार यह माना कि पीड़िता महक नाबालिग है। साथ ही कहा कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा तीन और चार के तहत उनकी शादी उपयुक्त नहीं है। उन्होंने लरकाना के वरिष्ठ पुलिस अफसरों से कहा कि वह इस मामले में लिप्त सभी लोगों पर कार्रवाई करें। महक कुमारी को कोर्ट में लरकाना के एक महिला शेल्टर होम से लाया गया था। सुनवाई के तुरंत बाद दंपती को तुरंत हिरासत में ले लिया गया।

कोर्ट ने कहा कि महक ने सोलंगी से निकाह करने के बाद मुस्लिम नाम अलीजा अपनाया लिया था। हालांकि इस दंपती ने दावा किया कि महक ने अपनी मर्जी से दरगाह अमरोत शरीफ में इस्लाम कुबूल किया है। जज ने इस संबंध में सुबूत और दस्तावेज मांगे, साथ ही सोलंगी को शादी के लिए अनुपयुक्त पाया। अदालत के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा थी। स्थानीय हिंदू और मुसलिम नेता भी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद थे।

महक कुमारी नौवीं कक्षा की छात्रा है। उसका अपहरण पाक के सिंध प्रांत के जकोकाबाद जिले से इसी साल 15 जनवरी को किया गया था। उसके अपहरणकर्ता अली रजा सोलंगी ने बाद में उसके साथ निकाह पढ़वा लिया था। तलाकशुदा सोलंगी के पहले से ही चार बच्चे थे। इसके बाद पीड़ित महक के पिता ने एफआइआर दर्ज कराई थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सर्वाधिक हिंदू रहते हैं, इसीलिए वहां नाबालिग लड़कियों को अगवा कर उनका जबरन धर्मांतरण करने की घटनाएं भी सबसे अधिक होती हैं।

चिली में समानता के लिए हिंसक प्रदर्शन

चिली के वालपरासियो में बुधवार को सरकार के खिलाफ एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी और पथराव किया। इस पर काबू पाने के लिए सुरक्षाबलों ने सख्त बल प्रयोग किया। चिली में आर्थिक और सामाजिक असमानता के खिलाफ महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रायटर

जापान में क्रूज से बाहर निकाले गए 500 से ज्यादा लोग

कोरोना का कहर

▸ चीन में जान गंवाने वालों की संख्या दो हजार से ज्यादा

योकोहामा, एजेंसियां : कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जापान में क्रूज पर फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। बुधवार को 500 से ज्यादा यात्रियों को क्रूज से निकलने की इजाजत दी गई। वायरस के संक्रमण से चीन में जान गंवाने वालों की संख्या 2004 हो गई है। संक्रमित होने वालों की संख्या लगातार दूसरे दिन घटी है। इसके बावजूद संक्रमित लोगों की संख्या 74 हजार के पार हो गई है। हांगकांग में एक और मरीज की मौत की जानकारी सामने आई है।

क्रूज पर फंसे लोगों के लिए 14 दिनों की आइसोलेशन अवधि का समय मुश्किलों भरा रहा। इस दौरान ना केवल यात्री डरे हुए थे बल्कि कुछ को तो खिड़की विहीन केबिनों में रखा गया था। क्रूज से उतरे 77 वर्षीय जापानी यात्री ने कहा, मुझे राहत मिली है। अब मैं आराम करना चाहता हूं। मीडिया को उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। अपने छह साल के बेटे के साथ 14 दिनों तक एक छोटे से केबिन में रहे यार्डली वोंग ने उतरने के बाद ट्वीट किया, अद्भुत देखभाल के लिए मैं कैप्टन और चालक दल का आभारी हूं।

छह भारतीय भी संक्रमित : क्रूज पर कुल 3711 यात्री थे। इनमें 138 भारतीय थे। टेस्ट में छह भारतीयों में संक्रमण का पता चला था। उनका जापान के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डायमंड प्रिंसेज नाम का यह क्रूज पांच फरवरी को जापान के तट पर पहुंचा था। जब यह जहाज योकोहामा बंदरगाह पहुंचा था तब तक उसमें कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था, लेकिन हांगकांग में उतरे एक व्यक्ति के संक्रमित होने का पता चलने के बाद क्रूज को आइसोलेशन में रख दिया गया। क्रूज पर अब तक 600 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। अमेरिका ने बीते रविवार को विशेष विमान भेजकर अपने 300 यात्रियों को क्रूज से बाहर निकाला था। इसमें वह 14 यात्री भी शामिल थे, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया था।

जापान के योकोहामा तट पर खड़े क्रूज जहाज डायमंड प्रिंसेज पर सवार उन यात्रियों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है जो कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आए हैं। तस्वीर में एक बस ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को लेकर पोर्ट से बाहर निकल रही है। एपी

निदेशक के बाद अस्पताल की चीफ नर्स की भी मौत : चीन में फैली महामारी के केंद्र वुहान से एक और बुरी खबर सामने आई है। वुचांग अस्पताल के निदेशक लिउ झिमिंग की मौत के बाद यहां की चीफ नर्स ली फैन (59) की मौत होने की जानकारी सामने आई है। ली की दो फरवरी तक अस्पताल के इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थी। परेशानी महसूस होने के बाद जब उनकी जांच की गई तो संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 फरवरी को उनकी मौत हो गई। बता दें कि उनके माता-पिता और भाई की संक्रमण से पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि उनके पति और बेटी को आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि अभी तक दोनों में संक्रमण नहीं मिला है।

चीन में बुखार के मरीजों पर रखी जाएगी नजर : चीन में जिन लोगों को 20 जनवरी से बुखार आ रहा है, उन पर ना केवल नजर रखी जाएगी बल्कि उनके रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी। ऐसे लोगों का भी पता लगाया जाएगा, जिन्होंने खांसी और बुखार की दवाएं दुकानों से खरीदी हैं। चीन के कई प्रांतों ने चिकित्सकीय प्रयोग के लिए खून उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। दरअसल, यात्रा प्रतिबंध के चलते डोनर घर पर ही रहने को मजबूर हैं। इस बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के प्रमुख माइकल रेयान ने उत्तर कोरिया में संक्रमण की बात से इन्कार किया है।

चीन में हॉस्टल से निकलने पर थी पाबंदी, लिफ्ट के बटन तक किए जाते थे साफ

नईदुनिया, खरगोन : आखिरकार गुरुग्राम में बनाए गए कोरोना राहत कैंप में 15 दिन निगरानी में रहकर मध्य प्रदेश के खरगोन के दो छात्रों ने घर लौटकर सुकून की सांस ली। चीन के शियान शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे अब्दुल मतीन खान व शुभम गुप्ता को वहां कोरोना वायरस फैलने के बाद सरकार की मदद से विशेष विमान से दिल्ली लाया गया था। उन्होंने बताया कि चीन में उन्हें हॉस्टल से निकलने नहीं दिया जा रहा था। लिफ्ट के बटन तक बार–बार साफ किए जाते थे।

भारत लाए जाने के बाद दो फरवरी को उन्हें दिल्ली के निकट गुरुग्राम में सेना के कैंप में रखा गया था। 15 दिन निगरानी के बाद उन्हें खरगोन जाने की अनुमति मिली। गोगावां में छात्र अब्दुल ने जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' से चर्चा में कहा कि वुहान में कोरोना वायरस की जानकारी दिसंबर में लीक हुई थी, लेकिन उस समय उनकी मेडिकल पढ़ाई की परीक्षा चल रही थी। इस वायरस का उन्हें पता नहीं चला था। 10 जनवरी को वायरस के फैलने की जानकारी लगी तो उनके हॉस्टल से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई, वहीं यह वायरस जब पूरी तरह सक्रिय हुआ तो उन्हें भय सताने लगा। उन्होंने परिजन से फोन पर बात की। फोन पर अब्दुल ने बताया कि उनके कॉलेज में भारत के करीब 300 छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं।

स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची घर : खरगोन में अब्दुल के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। जिला डीसीओ डॉ. सुनील वर्मा व जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. रेवाराम कोशले शामिल थे। टीम ने मतीन को मॉस्क लगाने की सलाह देते हुए सैनिटाइजर की बॉटल दी। परिजन की भी जांच कर वायरस से बचाव के टिप्स दिए। मतीन को घर में ही रहने की सलाह दी गई।

दहशत के पल में भी शुभम ने बनाए रखा आत्मविश्वास : घर लौटे शुभम ने बताया कि चीन में संक्रमण की खबर से उनका दिल दहल गया था।

ईरान में संसदीय चुनाव से पहले हजारों उम्मीदवार अयोग्य

तेहरान, एएफपी : ईरान में शुक्रवार को होने वाले संसदीय चुनाव से पहले हजारों उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराए जाने के कारण सवाल उठ रहे हैं।

इस पर सफाई देते हुए ईरान की चुनाव निगरानी संस्था गार्जियन काउंसिल ने बुधवार को कहा कि इन उम्मीदवारों को मुल्क के कानून के अनुसार ही अयोग्य ठहराया गया है। इसमें किसी तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने लोगों से मतदान की अपील है। उन्होंने मतदान को धार्मिक कर्तव्य बताया।

संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने वाले जिन उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया गया है, उनमें से ज्यादातर उदारवादी गुट के हैं। इसी को लेकर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में सफाई देते हुए गार्जियन काउंसिल के प्रवक्ता अब्बास अली कदखुदाई ने कहा कि हमारी संस्था राजनीतिक धड़ों के साथ निष्पक्ष बर्ताव करती है। पूर्व के चुनावों में भी समान मानदंड अपनाया गया था। चुनाव प्रक्रिया हमेशा से निष्पक्ष रही है।

दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में 11 भारतीय

▸ 16वीं रैंकिंग के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भारतीय विवि में शीर्ष पर

लंदन, प्रेट्र : दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत की 11 यूनिवर्सिटी जगह बनाने मे सफल रही हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) की तरफ से जारी 'उभरती अर्थव्यवस्थाएं विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020' में यह जानकारी सामने आई है।

दुनिया के 47 देशों और क्षेत्रों के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की इस सूची में भारत से ज्यादा सिर्फ चीन के ही 30 विश्वविद्यालय शामिल हैं। लंदन में मंगलवार को ये आंकड़े जारी किए गए। वैसे दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले सभी देशों के 533 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें 56 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं।

इस सूची में 16वें स्थान के साथ बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आइआइएससी) भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर है। इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) का नंबर है। इसमें आइआइटी खड़गपुर 32वें, आइआइटी दिल्ली 38वें स्थान और आइआइटी मद्रास 63वें स्थान पर हैं।

टीएचई के चीफ नॉलेज ऑफिसर फिल बैटी ने कहा कि विश्व रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की सफलता को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है और बहुत लंबे समय तक वैश्विक स्तर पर उन्हें खराब प्रदर्शन के रूप में देखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये आंकड़े अहम साबित हो सकते हैं।

अव्वल 100 विश्वविद्यालयों में अमृता विश्व विद्यापीठ भी शामिल है, जिसने 51 पायदान की छलांग लगाई है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 141 थी। इस विश्वविद्यालय ने सभी क्षेत्रों में सुधार किया है। यह विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा 2017 में स्थापित प्रख्यात संस्थान योजना में शामिल था। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों को अधिक धन और स्वायत्तता प्रदान की जाती है। रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी पहली बार शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में जगह बनाने में सफल रहे हैं।

ट्रंप ने जताई तालिबान के साथ शांति समझौते की उम्मीद

वाशिंगटन, प्रेट्र : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के साथ शांति समझौते की संभावना बनी हुई है। ट्रंप ने मंगलवार को यहां कहा, शांति समझौते को लेकर तालिबान से हमारी बातचीत चल रही है। देखें आगे क्या होता है। समझौते की संभावना दिख रही है। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या में काफी कमी की गई है। अमेरिका शांति समझौते के पक्ष में है। ट्रंप के इस बयान पर अफगान मामले के विशेषज्ञ मार्विन विनबौम का कहना है कि अमेरिका और तालिबान के बीच यह समझौता इस महीने के अंत तक हो सकता है। लेकिन इससे पहले तालिबान को कम से कम एक सप्ताह के लिए हिंसा छोड़नी होगी। संभावित समझौते के तहत अमेरिका पहले अपने पांच हजार सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाएगा। तालिबान आतंकियों और अफगानिस्तान के बंदी सैनिकों को रिहा भी किया जा सकता है। सैनिकों की वापसी का कार्य नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरा किया जा सकता है।

वॉयलिन बजाते हुए महिला ने कराया दिमाग का ऑपरेशन

नया प्रयोग

ब्रिटेन में संगीत का प्रभाव देखने को मिला, डॉक्टरों ने वॉयलिन वादन कराने का फैसला किया इससे ऑपरेशन के दौरान मस्तिष्क के संवेदनशील हिस्से के ठीक से काम करते रहने का पता चलता रहता

लंदन, रायटर

कर्णप्रिय संगीत धुनों से दिमागी सुकून मिलने का तथ्य सर्वविदित है। नित्य प्रति जीवन में हम संगीत के असर को महसूस भी करते हैं। ताजा मामला ब्रिटेन के अस्पताल में भर्ती महिला डैगमर टर्नर (53) का है जिन्हें वॉयलिन पर अपनी प्रिय धुनें बजाते-सुनते ब्रेन ट्यूमर से छुटकारा मिला। लोकल एनस्थीसिया देकर उनके ट्यूमर को निकालने का ऑपरेशन चलता रहा और वह टेबिल पर लेटे वॉयलिन पर अपनी प्रिय धुनें बजाती रहीं। डैगमर को 40 साल से वॉयलिन से लगाव है।

प्रबंधन सलाहकार रहीं टर्नर के मस्तिष्क के उस स्थान पर ट्यूमर था, जिसके नजदीक से बाएं हाथ की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। लेकिन अस्पताल में खाली समय में मन बहलाने के लिए उन्होंने वॉयलिन बजाने का शौक कायम रखा। किंग्स कॉलेज अस्पताल में न्यूरो सर्जन प्रोफेसर केयोमर्स आश्कन इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने टर्नर से बात कर ऑपरेशन के दौरान उनसे वॉयलिन वादन कराने का फैसला किया। इससे ऑपरेशन के दौरान मस्तिष्क के संवेदनशील हिस्से के ठीक से काम करते रहने का पता चलता रहता। चूंकि इतिहास रचा जा रहा था, इसलिए इसके वाकये की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और बाद में उसे मीडिया को जारी भी किया गया। ऑपरेशन के दौरान टर्नर ने अपनी पसंदीदा मेहलर और जेरश्विर की धुनों को बजाते हुए मस्तिष्क से ट्यूमर निकलवाया।

ब्रिटेन के लंदन में मस्तिष्क के ऑपरेशन के बीच वायलिन बजाते हुए 53 वर्ष उम्र की डाग्मार टर्नर। ट्विटर से

दस वर्ष की उम्र से बजा रहीं वायलिन

प्रोफेसर आश्कन ने कहा, उनके करिअर में ऐसा पहली बार हुआ जब संगीत के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मरीज का ट्यूमर निकाला गया हो, वह भी ऐसे अंग का जो हर समय बहुत सक्रिय अवस्था में रहता है। टर्नर कहती हैं– दस वर्ष की उम्र से वॉयलिन बजाना उनके लिए जुनून बन गया था। व्यावसायिक कारणों से वह कम हुआ, उसी दौरान ट्यूमर ने शरीर में जगह बना ली। अस्पताल में समय मिलने पर फिर से पुराना शौक जगा, तो नतीजे के तौर पर खुद को फिर से स्वस्थ महसूस कर रही हैं।

अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट के मुख्य जज बने श्रीनिवासन

▸ चंडीगढ़ में जन्मे श्रीनिवासन यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले दक्षिण एशियाई

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारतवंशी जज श्री श्रीनिवासन अमेरिका के शक्तिशाली फेडरल अपील कोर्ट की कमान संभालने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के बाद फेडरल अपील कोर्ट को ही सर्वाधिक शक्तिशाली अदालत माना जाता है। 52 वर्षीय श्रीनिवासन ने गत 12 फरवरी को डीसी सर्किट की अपील कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालकर इतिहास रचा। चंडीगढ़ में जन्मे श्रीनिवासन अमेरिकी न्यायपालिका में इतने उच्च पद पर आसीन होने वाले दूसरे भारतवंशी हैं। इससे पहले प्रख्यात अमेरिकी वकील नेओमी जहांगीर राव को डिस्ट्रिक ऑफ कोलंबिया सर्किट कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी श्रीनिवासन के नाम पर विचार किया जा चुका है। श्रीनिवासन ने फेडरल सर्किट कोर्ट में मेरिक गारलैंड की जगह ली है। गारलैंड को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फेडरल कोर्ट में नामित किया था। लेकिन 2016 में अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी थी। श्रीनिवासन कंसास के लॉरेंस में पले-बढ़े हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया।

श्री श्रीनिवासन की फाइल फोटो। ट्विटर

पहले टेस्ट में मैदान पर उतर सकते हैं इशांत और पृथ्वी

भारतीय कप्तान कोहली ने दिए अंतिम एकादश में शर्मा व शॉ के चुने जाने के संकेत विकेटकीपर के रूप में पंत की जगह खेल सकते हैं अनुभवी साहा

वेलिंगटन, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को संकेत दिए कि सीनियर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अंतिम एकादश में शामिल हो सकते हैं।

टीम इंडिया के बुधवार को हुए नेट अभ्यास पर गौर करें तो शुक्रवार से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में अनुभवी रिद्धिमान साहा टीम में विकेटकीपर के रूप में युवा रिषभ पंत की जगह ले सकते हैं। जसप्रीत बुमराह, मुहम्मद शमी और इशांत टीम के तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाज हो सकते हैं, जबकि छठे स्थान के बल्लेबाज हनुमा विहारी पांचवें गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन अकेले विशेषज्ञ फिरकी गेंदबाज हो सकते हैं, जबकि रवींद्र जडेजा की ऑलराउंड प्रतिभा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इशांत रणजी ट्रॉफी के दौरान टखने में चोट लगने के बाद तीन सप्ताह से टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने नेट में सधी गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को अपनी गति एवं उछाल से हैरान कर उन्होंने सराहना भी बटोरी।

कप्तान कोहली ने कहा, 'वह (इशांत) बिलकुल सामान्य दिखे और चोट लगने से पहले की तरह ही गेंदबाजी करते दिखे। वह फिर से अच्छी जगहों पर गेंद डालने लगे हैं। वह पहले भी न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, अतः उनका अनुभव हमारे लिए लाभदायक साबित होगा। उन्हें अच्छी गति से गेंदबाजी करते और अच्छी जगहों पर गेंद डालते देखना वास्तव में सुखद अहसास है।' कप्तान ने कहा कि टीम शॉ की नैसर्गिक बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करना चाहेगी, जो इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि शुभमन गिल को बेंच पर बैठे रहना पड़ सकता है। कोहली ने कहा, 'पृथ्वी एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उनके पास खेलने का अपना तरीका है। हम चाहेंगे कि वह अपना सहज खेल जारी रखें और नैसर्गिक तरीके से खेलते रहें। इन लड़कों के ऊपर किसी भी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने जैसा कोई बोझ नहीं है। उन्हें विदेश में अच्छा खेलने को लेकर कोई घबराहट नहीं है। मयंक ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया था, पृथ्वी भी न्यूजीलैंड में ठीक वैसा कर सकते हैं। बिना डर के खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों का होना पूरी टीम का मनोबल बढ़ाता है, इससे हमें ऐसी शुरुआत मिलती है जो टीम चाहती है।'

कप्तान कोहली ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को महत्व नहीं देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'पृथ्वी को आप अपेक्षाकृत कम अनुभवी कह सकते हैं और मयंक को मैं कम अनुभवी कहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने पिछले साल काफी रन बनाए हैं इसलिए वह समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में किस तरह का खेल दिखाना होता है। मुझे लगता है कि सफेद गेंद के खेल में हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लाल गेंद वाली क्रिकेट खलते हैं, आप अनुशासित बल्लेबाजी करने लगते हैं, जो निश्चित तौर पर इस अवस्था में उनके ऊपर ठीक लगता है।'

टेस्ट सीरीज ट्रॉफी के साथ वेलिंगटन में बुधवार को न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (बायें) और भारतीय कप्तान विराट कोहली ● एएनआइ

वैगनर के कवर के तौर पर हेनरी न्यूजीलैंड की टीम में शामिल

वेलिंगटन: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए तेज गेंदबाज मैट हेनरी को नील वैगनर के कवर के तौर पर शामिल किया। वैगनर के पहले बच्चे का जन्म होने वाला है। न्यूजीलैंड टीम ने ट्वीट किया, 'नील वैगनर शुरुआती टेस्ट से पहले वेलिंगटन में टीम से नहीं जुड़ेंगे क्योंकि वह और उनकी पत्नी पहले बच्चे के जन्म के समय साथ रहना चाहते हैं। वैगनर बच्चे के जन्म तक तौरंगा में रहना चाहते हैं। मैट हैनरी आज रात उनके कवर के तौर पर टीम से जुड़ जाएंगे।' हेनरी 12 टेस्ट और 52 वनडे खेल चुके हैं, लेकिन टेस्ट मैचों में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, उन्होंने 12 टेस्ट में 30 विकेट लिए हैं।

संभावित एकादश : मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन/रवींद्र जडेजा, बुमराह, मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा

तीन साल तक तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे कोहली

वेलिंगटन: दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार कोहली अगले तीन साल में दो टी-20 विश्व कप और एक 50 ओवर के विश्व कप के साथ भारतीय क्रिकेट की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, जिसके बाद वह तीनों प्रारूपों में से किन्हीं दो में खेलने का फैसला कर सकते हैं। जब कोहली से पूछा गया कि क्या भारत में 2021 टी-20 विश्व कप के बाद कम से कम एक प्रारूप को छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, 'मेरी सोच बड़ी तस्वीर वाली है जहां मैं खुद को अब से तीन साल की कड़ी मेहनत के लिए तैयार कर रहा हूं। करीब आठ साल से मैं हर साल 300 दिन खेल रहा हूं, जिसमें यात्रा और अभ्यास सत्र भी शामिल हैं।' उन्होंने संकेत दिए कि अगले तीन साल तक तीनों फॉर्मेट में खेलते रहेंगे। इस साल 31 वर्ष के हो रहे भारतीय कप्तान ने माना कि बीच-बीच में छुट्टियां लेना उनके लिए कारगर रहा है। उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी हर वक्त इसके बारे में नहीं सोचते। हम व्यक्तिगत रूप से कई ब्रेक लेते हैं, भले ही मैचों के कार्यक्रम के बीच हमें इसकी गुंजाइश नहीं लगती हो। यह बात उन लोगों के लिए खासतौर पर लागू है जो हर तरह के प्रारूप में खेलते हैं।' कोहली के लिए यह केवल उनके प्रदर्शन की बात नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भी बात है, जिसके लिए उन्हें हर समय रणनीति बनाने के मकसद से दिमाग को आराम की जरूरत होगी।

विराट ने माना शीर्ष पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप

वेलिंगटन: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को आइसीसी की सबसे बड़ी स्पर्धा करार दिया। खेल की शीर्ष संचालन संस्था आइसीसी 2023-2031 तक अगले आठ साल के दौरान ज्यादा से ज्यादा सफेद गेंद के टूर्नामेंट जोड़ने की योजना बना रही है। आइसीसी के प्रस्तावित 2023-2031 भविष्य दौरा कार्यक्रम (एफटीपी) के अनुसार 2024 और 2028 में टी-20 चैंपियंस कप, 2025 और 2029 में वनडे चैंपियंस कप, 2026 और 2030 में टी-20 विश्व कप एवं 2027 और 2031 में वनडे विश्व कप निर्धारित किया गया है। कोहली ने कहा, 'मुझे लगता है कि आइसीसी टूर्नामेंट में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को सबसे शीर्ष पर होना चाहिए। मेरे लिए सभी अन्य टूर्नामेंट इसके बाद आते हैं। यह शायद इन सभी में सबसे बड़ा है, क्योंकि हर टीम लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल में जगह बनाना चाहती है। हम भी अलग नहीं हैं। हम इसके करीब हैं। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जल्द इसमें क्वालीफाई कर जाएं और हमारा उस चैंपियनशिप को जीतने पर लगा हो।' इसमें कोई शक नहीं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ने पारंपरिक प्रारूप में थोड़ी प्रतिद्वंद्विता ला दी है जिससे मुकाबले और अधिक रोमांचक हो गए हैं क्योंकि इसमें अंक दिए जाते हैं। कोहली ने कहा, 'इसने टेस्ट क्रिकेट को और अधिक रोमांचक बना दिया है और हमने ऐसा ही अनुभव किया है, हालांकि हमने ज्यादा मैच विदेशी सरजमीं पर नहीं खेले हैं। वेस्टइंडीज में दो मैच ही खेले हैं। हमने टेस्ट चैंपियनशिप के नाते ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं किया है। यह घरेलू सत्र शुरू होने के बाद से हमारा पहला दौरा है।' कप्तान को उम्मीद है कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज काफी चुनौतीपूर्ण होगी, जैसी हाल में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुई थी। उन्होंने कहा, 'मैच टक्कर के होंगे और टीमें ड्रॉ के बजाय जीत हासिल करना चाहेंगी, जो टेस्ट क्रिकेट में हमें देखने की जरूरत है। इंग्लैंड ने केपटाउन टेस्ट में अंतिम घंटे में मैच जीता था और आपको ऐसे ही कई नतीजे देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें काफी अंक दांव पर होंगे।'

> चोटिल होने से उनके दो खिलाड़ी (राहुल व रोहित) नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास काफी खिलाड़ी हैं जो प्रतिभाशाली हैं व जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी निभाने के काबिल हैं। उन्हें भले ही अनुभव नहीं हो, लेकिन वे शानदार खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से घरेलू हालात हमारे मुफीद होंगे, लेकिन बेसिन रिजर्व पर अच्छा करने के लिए काफी चीजों का ध्यान रखना होगा और अगले तीन दिनों में भारत को इनका आदी होना होगा। **टिम साउथी**, तेज गेंदबाज, न्यूजीलैंड

> मुझे लगता है कि टीम इंडिया का पूरा गेंदबाजी आक्रमण ही शानदार है। निश्चित रूप से इशांत का टीम में वापसी करना टीम में नए आयाम जोड़ेगा। उनके पास विश्व स्तरीय बल्लेबाजी क्रम मौजूद है और हमें इससे भी निपटना होगा लेकिन, वह किसी कारण से ही दुनिया की नंबर एक टीम हैं और हम जानते हैं कि हमें उनके खिलाफ सफल होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। **रॉस टेलर**, बल्लेबाज, न्यूजीलैंड

वेलिंगटन में बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान बातचीत करते भारतीय गेंदबाज इशांत शर्मा (बायें) और गेंदबाजी कोच भरत अरुण ● एएनआइ

भारतीय टीम किसी पर भी दबाव बना सकती है : हरमनप्रीत कौर

महिला टी-20 विश्व कप

- कहा, हम सकारात्मक सोच के साथ खेलने पर ध्यान दे रहे हैं
- धीमी पिच और भारतीय समर्थकों का टीम को फायदा मिलेगा

सिडनी, प्रेट्र: भारतीय महिला टी-20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम अगर आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप में सकारात्मक सोच के साथ मैदान पर उतरती है तो वह किसी भी टीम पर दबाव बना सकती है।

हरमनप्रीत ने कहा कि यह सकारात्मकता भारतीय टीम का सबसे मजबूत पक्ष है और उनकी टीम टूर्नामेंट के पहले मैच में चार बार की चैंपियन और मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। महिला बिग बैश लीग में सिडनी थंडर से खेलने के कारण शहर को अच्छी तरह से समझने वालीं हरमनप्रीत ने कहा, 'हमारे अंदर रोमांच पैदा होने लगा है क्योंकि हम पहले मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं और हम इसके सकारात्मक पक्षों पर गौर कर रहे हैं। हमारी टीम ऐसी है जो किसी भी टीम पर दबाव बना सकती है। हम सकारात्मक सोच के साथ खेलने पर ध्यान दे रहे हैं और उस तरह से खेलना चाहते हैं जैसे हम खेल सकते हैं, क्योंकि यह हमारा सबसे मजबूत पक्ष है।' हरमनप्रीत का मानना है कि धीमी पिच और भारतीय समर्थकों के समर्थन से उनकी टीम को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, 'अगर सिडनी शोग्राउंड की पिच धीमी रहती है तो इससे हमें फायदा होगा और अभी यह विकेट ऐसा दिख रहा है। हम इसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर ध्यान दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में सभी क्रिकेट को चाहते हैं। हम जहां भी जाते हैं वहां हमें प्रशंसकों का प्यार मिलता है और हम फिर से उनके समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं।'

रोमांचित हैं एनाबेल: ऑस्ट्रेलिया की युवा तेज गेंदबाज व क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सीईओ जेम्स सदरलैंड की बेटी एनाबेल सदरलैंड पहली बार टी-20 विश्व कप में भाग लेंगी। उन्होंने कुछ सप्ताह पहले ही टी-20 में पदार्पण किया था। एनाबेल ने कहा, 'मैं बेहद रोमांचित हूं। हम भारत के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं।'

सबसे ज्यादा खुश टीम हैं हम, थाइलैंड दूसरे स्थान पर : मंधाना

सिडनी, प्रेट्र: सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कहा कि भारतीय टीम महिला टी-20 विश्व कप में सिर्फ मजबूत दावेदारों में शामिल नहीं है, बल्कि युवा खिलाड़ियों की मौजूदगी से वे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा खुश टीम भी हैं। भारतीय टीम की औसत उम्र 23 साल से कम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुक्रवार को टूर्नामेंट से पहले मंधाना ने मजाक करते हुए कहा कि जहां तक मजा लेने की बात है तो केवल पदार्पण करने वाली थाइलैंड की टीम ही उन्हें चुनौती दे सकती है। आइसीसी के मुताबिक मंधाना ने कहा, 'यह ग्रुप सचमुच जानता है कि चीजों का आनंद कैसे उठाना है। यह युवा खिलाड़ियों को सहज बनाने की बात है और मैं भी उनके साथ ऐसी बन गई हूं। हमने काफी डांस किया, काफी गाने गाए और काफी चीजें कीं। मुझे लगता है कि हम विश्व कप की सबसे ज्यादा खुश टीम हैं, हालांकि थाइलैंड हमें कुछ चुनौती दे सकती है।' इस 'कूल टीम' की सरगना जेमिमा रोड्रिग्ज हैं जो मजाकिया वीडियो बनाती हैं और बेहतरीन गिटार भी बजाती हैं। कभी-कभी ड्रेसिंग रूम ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह डांस फ्लोर हो। उन्होंने कहा, ' हमारी टीम की उम्र देखो तो आप इसे महसूस कर सकते हो। इस तरह की युवा टीम को देखते हुए इसमें मजा होना चाहिए। पिछले एक या दो वर्षों में ऐसा ही हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इससे पहले ऐसा नहीं था, लेकिन तब से युवा खिलाड़ी आई हैं, खिलाड़ियों की स्फूर्ति बढ़ गई है।'

स्मृति मंधाना ● फाइल फोटो, प्रेट्र

भारत और ऑस्ट्रेलिया सबसे प्रभावशाली टीमें : ब्रेट ली

मेलबर्न: पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को लगता है कि आगामी महिला टी-20 विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया दो सबसे प्रभावशाली टीमें हैं जिनमें महिला क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जाने की काबिलियत है। टूर्नामेंट शुक्रवार से शुरू होगा, जिसमें भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ली ने आइसीसी की वेबसाइट पर कहा, 'आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2020 में महिला क्रिकेट अगले स्तर तक पहुंच सकता है और मुझे गर्व है कि ऑस्ट्रेलिया इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सिडनी पर पहला मैच खेला जाएगा और यह मैच टूर्नामेंट की लय तय कर सकता है क्योंकि यह मैच खेल की दो सबसे प्रभावशाली टीमों के बीच होगा।'

आशू और आदित्य को ग्रीको रोमन में कांस्य पदक

एशियन कुश्ती

- हरदीप ने भी कांस्य पदक पर जमाया कब्जा
- चैंपियनशिप में भारत के खाते में अब तक आए पांच पदक

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारत के आशू और आदित्य कुंडु ने बुधवार को यहां एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन क्रमशः 67 किग्रा और 72 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। आशू ने सीरिया के अब्दुलकरीम मुहम्मद अल-हसन को 8-1 से हराया जबकि कुंडु ने जापान के नाओ कुसाका को 72 किग्रा के एकतरफा मुकाबले में डेढ़ मिनट में 8-0 से पस्त कर दिया। आशू और आदित्य के अलावा हरदीप ने भी कांसे पर कब्जा जमाया।

भारत ने चैंपियनशिप में इस तरह पांच पदक जीत लिए हैं। इससे पहले सुनील कुमार ने 87 किग्रा में ऐतिहासिक स्वर्ण और अर्जुन हालाकुरकी ने 55 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ज्ञानेंद्र हालांकि बुधवार को 60 किग्रा ग्रीको रोमन कांस्य पदक मुकाबले में 0-6 से हार गए। इस वर्ग का स्वर्ण पदक जापान के केनीचिरो फुमिता ने अपने नाम किया जिन्होंने किर्गिस्तान के झोलामन शारशेंकोव को 4-0 से शिकस्त दी। मेहदी शेफोल्लाह मोहसन नेजाद ने 60 किग्रा में दूसरा कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कजाखिस्तान के एडोस सुल्तानगली को 4-3 से पराजित किया। हालांकि गुरुवार से भारतीय महिलाओं की कुश्ती शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि महिला पहलवान भारत के पदकों की संख्या को और बढ़ा देंगी। पदक की मुख्य दावेदारों में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक शामिल हैं।

हम क्यों नहीं स्वीकारते कि विरोधी बेहतर थे

गौतम गंभीर

फ्लिक

हम असफलताओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और निराशा हमारे चरित्र को परिभाषित करती है। क्रिकेट में, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब भी हम पिछड़ते हैं तो हम अपनी टीम में से किसी को दोष देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इसे आत्मविश्लेषण कहते हैं, लेकिन मैं इसे आत्मविश्वास की कमी कहता हूं। हम अपनी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं और उन चीजों को बदलते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। यही चीज तब हुई जब भारत हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 0-3 से हारा। इसके बाद उसी टीम की आलोचना हुई जिसने मेजबानों को टी-20 सीरीज में 5-0 से हराया था।

हम सिर्फ विरोधियों की सराहना क्यों नहीं कर सकते हैं और भविष्य के अपने मैचों की ओर क्यों नहीं देखते हैं? हम सिर्फ यह क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि विरोधी हमारी तुलना में बेहतर थे? टेस्ट सीरीज पर आते हैं, हमारे पास बल्लेबाजी में नई सलामी जोड़ी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल को जब मौका मिलेगा तो वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मयंक अग्रवाल पर मुझे काफी विश्वास है। वह वीरेंद्र सहवाग या डेविड वार्नर की तरह गेंदबाजों के साथ तिरस्कार का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास एक सलामी बल्लेबाज की स्पष्ट मानसिकता है। मैंने पृथ्वी और शुभमन के साथ काफी समय बिताया है। इस तरह के दौरे बल्लेबाजों के लिए चुनौती की तरह होते हैं, जहां गेंदबाजों के अनुकूल हालात होते हैं। मुझे लगता है कि हम उन्हें आंकने या उनके बारे में लिखने को लेकर जल्दबाजी में नहीं हैं। पृथ्वी अपने खेल में कसावट लाने के लिए मयंक या चेतेश्वर पुजारा से एक या दो चीजें सीख सकते हैं। भारत के पास प्रभावशाली गेंदबाजी आक्रमण है जिसे इशांत शर्मा के आने से स्थिरता मिल गई है।

#WhatDrivesYou

EXIDE

यूएफा चैंपियंस लीग डॉर्टमंड ने अंतिम-16 का पहला चरण का मैच 2-1 से जीता, हालैंड ने दागे दो गोल जबकि नेमार ने किया एक गोल

हालैंड के हमले से हिला पीएसजी

डॉर्टमंड, रायटर: 19 वर्षीय स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड के आठ मिनट के अंदर किए दो गोलों की मदद से डॉर्टमंड ने यहां अपने घरेलू मैदान पर यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के पहले चरण के मैच में सितारों से सजी पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) की टीम को 2-1 से शिकस्त दी। चोट के कारण पिछले चार मैचों से दूर रहे विश्व के सबसे महंगे फुटबॉलर नेमार ही पीएसजी के लिए एकमात्र गोल कर पाए। दोनों टीमों के बीच दूसरे चरण का मुकाबला 11 मार्च को पेरिस में खेला जाएगा।

गोलकीपर नवास ने किया सांचो को निराश: पहले हाफ में पीएसजी के नेमार के पास गोल करने का मौका था जब 11वें मिनट में फ्री किक पर उनका शॉट गोल पोस्ट के बायीं ओर से निकल गया। हालांकि इसके बाद डॉर्टमंड को गोल करने का मौका मिला तो सांचो का शॉट पोस्ट के ऊपर से चला गया। इसके बाद सांचो को एक और गोल करने का मौका मिला, लेकिन उनके इस प्रयास को पीएसजी के गोलकीपर नवास ने बेकार कर दिया। उन्होंने बॉक्स के अंदर से गेंद पर किक लगाई, लेकिन गेंद सीधा नवास के हाथों में चली गई। एक बार फिर सांचो ने गेंद पर किक लगाई, लेकिन किले की रक्षा में खड़े नवास ने उनको फिर से निराश कर दिया। पहला हाफ गोलरहित रहा।

हालैंड के आगे सब फेल: दूसरे हाफ में जहां हालैंड का जलवा देखने को मिला, वहीं नेमार व कायलियन एमबापे की जोड़ी सिर्फ एक गोल करने में सफल हुई। इस बीच, 59वें मिनट में नेमार को येलो कार्ड भी दिखाया गया जिसके बाद वह थोड़ा निराश दिखे। नेमार व एमबापे की जोड़ी के पास गोल करने का मौका बॉक्स के अंदर से मिला था लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। 69वें मिनट में हालैंड ने पेनाल्टी एरिया के पास से नवास को छकाकर गेंद को पोस्ट में पहुंचाकर टीम का मैच में खाता खोल दिया लेकिन इसके छह मिनट बाद ही नेमार व एमबापे की जुगलबंदी से पीएसजी मैच में वापसी करने में सफल हुई। अपने किले की रक्षा करने के लिए डॉर्टमंड के छह खिलाड़ी बॉक्स के बाहर थे, लेकिन एमबापे ने चालाकी से गेंद नेमार की तरफ भेजी और ब्राजील के इस खिलाड़ी ने स्कोर बराबर करने में ज्यादा देर नहीं की। हालांकि हालैंड के हमले से मैनेजर थॉमस टुकेल की खराब डिफेंसिव रणनीति की भी पोल खुल गई। 77वें मिनट में जियोवानी रेयना ने गेंद हालैंड को पास की और उन्होंने बॉक्स के बाहर से बायें पैर से गेंद को सीधा गोल पोस्ट में भेज दिया और उसे रोक पाना नवास के लिए मुश्किल था। इसके बाद डॉर्टमंड ने पीएसजी को गोल करने के मौके नहीं दिए और जीत हासिल की।

पीएसजी के खिलाफ गोल करने के बाद कुछ इस अंदाज में जश्न मनाते अर्लिंग हालैंड ● एपी

दिल्ली में होगा लिवरपूल का रोड शो

नई दिल्ली: इंग्लिश प्रीमियर लीग के शीर्ष क्लब लिवरपूल एफसी ने पुष्टि की है कि उसके रोड शो का अगला पड़ाव दिल्ली होगा। यह कार्यक्रम सात मार्च को शहर के सेलेक्ट सिटीवाक में आयोजित किया जाएगा जहां लिवरपूल फुटबाल क्लब 'एलएफसी विश्व हब' के माध्यम से अपने समर्थकों से जुड़ेगा। एलएफसी विश्व का यह चौथा सत्र है। एलएफसी विश्व ने 2016 के बाद से आठ देशों में अपने हजारों प्रशंसकों के साथ मुलाकात की है। लिवरपूल के दिग्गज एमिल हेस्की और जेसन मैकअटीर इस कार्यक्रम के लिए शहर में रहेंगे।

05 बुंडिशलीगा मैचों में हालैंड आठ गोल कर चुके हैं। नॉर्वे के हालैंड पिछले ट्रांसफर विंडो के तहत रेड बुल साल्जबर्ग से डॉर्टमंड की टीम से जुड़े थे

07 मैचों में हालैंड ने इस सत्र में यूरोप के एलीट टूर्नामेंट में 10 गोल दागे हैं जिसमें आठ गोल उन्होंने ग्रुप स्तर के मैचों में साल्जबर्ग टीम के लिए किए थे

10 गोल चैंपियंस लीग में करने वाले वह दूसरे युवा खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले एमबापे ने ऐसा किया था। वह एक टूर्नामेंट के एक ही सत्र में दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ गोल करने वाले पहले फुटबॉलर भी बन गए

> मुझे अभी भी अपने खेल में सुधार की जरूरत है और मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैं टीम को चैंपियंस लीग में आगे ले जाना चाहता हूं। मुझे अपना दूसरा गोल अच्छा लगा। **अर्लिंग हालैंड** स्ट्राइकर, डॉर्टमंड

एटलेटिको मैड्रिड ने गत विजेता लिवरपूल चौंकाया

मैड्रिड: स्पेनिश फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के पहले चरण के मैच में गत विजेता इंग्लिश क्लब लिवरपूल को 1-0 से हराकर उसे चौंका दिया। हालांकि स्पेनिश क्लब की असली परीक्षा 11 मार्च को होगी जब उसे लिवरपूल के घरेलू मैदान एनफील्ड में दूसरे चरण का मुकाबला खेलना होगा। एटलेटिको के समर्थकों ने वांडा मेट्रोपोलिटियानो में अपनी टीम का शानदार स्वागत किया। तोहफे में एटलेटिको ने लिवरपूल को एक भी शॉट लक्ष्य पर लगने नहीं दिया। लिवरपूल के सामने एटलेटिको ज्यादा असरदार टीम लग रही थी। स्पेनिश लीग में यह टीम चौथे स्थान पर है। वहीं, लिवरपूल ने प्रीमियर लीग के अभी तक खेले 26 मैचों में से 15 में गोल किए हैं। हालांकि इस मैच में गत विजेता के डिफेंस में लापरवाही नजर आई और चौथे मिनट में ही उसने गोल खा लिया। एटलेटिको के कोके ने कॉर्नर किक ली जो इंग्लिश क्लब के मिडफील्डर फाबिंहो से टकराते हुए एटलेटिको के सौल निगुएज के पास गई। सौल ने लिवरपूल के कीपर एलीसन को मौका नहीं दिया और स्पेनिश क्लब को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद मेजबान टीम ने गेंद अधिकतर समय अपने पास रखी और एलिसन की जमकर परीक्षा भी ली। लिवरपूल के मुहम्मद सलाह ने भी अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया था, लेकिन वार के कारण इस गोल को ऑफ साइड करार दे दिया था।

दादा और द्रविड़ ने बदली जूनियर क्रिकेट की तस्वीर

अरुण सिंह, पटना: कभी भारतीय क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया को आक्रामक बनाने वाले सौरव गांगुली वर्तमान में भारतीय जूनियर क्रिकेट की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

भारतीय जूनियर चयन समिति के सदस्य ज्ञानेंद्र बोले, गांगुली के आने से सीनियर टीम में आया बदलाव

भारतीय जूनियर टीम चयन समिति के सदस्य पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडेय ने बुधवार को जागरण से विशेष बातचीत में बताया कि अंडर-19 और भारत-ए टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल ने इशान किशन, पृथ्वी शॉ, रिषभ पंत जैसे कई प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें निखारा है। अब वह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में निदेशक के तौर पर अपनी भूमिका को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। साथ ही भारत-ए और अंडर-19 टीम की प्रगति पर वह कड़ी नजर रखे हुए हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर भारत-ए टीम को देखने मैं भी गया था और मैं दावे से कह सकता हूं कि द्रविड़ के कारण काफी फर्क पड़ा है। उसी तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं, जैसा कभी वह कप्तान के रूप में थे। उनके आने से सीनियर, जूनियर और महिला क्रिकेट में काफी बदलाव नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, राज्य संघों के क्रिकेट संचालन में भी वे बढ़-चढ़ कर मदद कर रहे हैं।

दादा के कहने पर एमपी वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट देखने पटना पहुंचे ज्ञानेंद्र पिछले दिनों बांग्लादेश के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में भारत की हार से निराश दिखे। उन्होंने बताया कि भारत का स्कोर अगर दो सौ के पार होता तो हमे लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। बहरहाल यशस्वी जायसवाल, प्रियम गर्ग, रवि बिस्नोई जैसे कई क्रिकेटरों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सीनियर टीम के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। अपने करियर में दो वनडे और सौ प्रथम श्रेणी मैच खेल चुके ज्ञानेंद्र पांडेय ने कहा कि बिहार क्रिकेट को पटरी पर लाने में आदित्य वर्मा की अहम भूमिका रही है। बिहार को रणजी की मान्यता उन्हीं के कारण मिली है।

साइना दूसरे दौर में पहुचीं, एचएस प्रणय बाहर

बार्सिलोना : भारत की ओलंपिक पदक विजेता शटलर साइना नेहवाल ने बुधवार को यहां बार्सिलोना स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में जगह बनाई। साइना ने पहले दौर में जर्मनी की यवोनी ली को 21-16, 21-14 से हराया। उन्होंने केवल 35 मिनट में यह मैच जीता। एचएस प्रणय हालांकि पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में मलेशिया के डेरेन लियु से 18-21, 15-21 से हार गए।

मैं जब चोटिल था तो हमेशा वापसी करने के बारे में सोचता था। अब मैं टीम में जगह बनाकर खुश हूं।
– चिंग्लेनसेना सिंह, हॉकी खिलाड़ी, भारत

न्यूज गैलरी

अंतिम-16 में पहुंचे थिएम

रियो डि जेनेरियो : शीर्ष वरीय ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने रियो ओपन के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने ब्राजील के फेलिप मेलीगेनी को तीन सेटों तक चले मुकाबले में मात दी। थिएम ने वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी को दो घंटे चार मिनट तक चले मैच में 6-2, 4-6, 6-1 से हराया। अगले दौर में थिएम का सामना स्पेन के जाउमे मुनार से होगा जिन्होंने इटली के साल्वाटोरे कारुसो को 7-5, 6-4 से हराया। थिएम के अलावा दूसरी वरीय डुसान लाजोविक ने इटली के मार्को चेचेहिनाटो को 6-4, 6-7, 6-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। यह मैच दो घंटे 16 मिनट तक चला। बुधवार को सर्बिया के इस खिलाड़ी का सामना इटली के लोरेंजो सोनेगो से होगा जिन्होंने लियोनाडरे मायेर को 6-1, 5-7, 6-5 से शिकस्त दी। (आइएएनएस)

अकादमी चाहते हैं केशवन

मुंबई : शीतकालीन खेलों में ल्यूज स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले छह बार के ओलंपियन भारतीय एथलीट शिवा केशवन युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमी खोलने की तैयारी में जुटे हैं और वह इस संदर्भ में राज्य सरकारों से बात करने में भी लगे हुए हैं। केशवन ने कहा कि मैं कई खेलों की सभी सुविधाओं वाला आवासीय परिसर बनाना चाहता हूं लेकिन क्योंकि ये खेल पर्वतों पर होते हैं तो हमें स्की क्षेत्र, आइस हॉकी के लिए सुविधाएं चाहिए होंगी। यह समय के साथ तैयार हो सकता है इसलिए मैं कुछ जमीन देने के लिए दो राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा हूं। फिर मैं इसके लिए कुछ प्रायोजक जुटाने की कोशिश भी कर रहा हूं। (प्रेट्र)

भारतीय महिला टीम जीती

नई दिल्ली : भारतीय अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम ने तुर्की के तुर्कलर में बुधवार को खेले गए दूसरे मैत्री मैच में रोमानिया को 1-0 से हराया। मैच का एकमात्र गोल प्रियंका देवी ने 29वें मिनट में पेनाल्टी पर किया। रविवार को खेला गया पहला मैत्री मैच 3-3 से बराबर छूटा था। भारतीय टीम ने पहले हाफ में दबाव बनाने के प्रयास किए। भारत के पास 28वें मिनट में गोल करने का मौका था लेकिन निर्मला देवी इसका फायदा नहीं उठा पाई। भारत को इसके एक मिनट बाद फिर से मौका मिला और प्रियंका ने 12 गज की दूरी से गोल करने में कोई गलती नहीं की। इस बढ़त को भारत ने अंतिम समय तक कायम रखते हुए जीत हासिल की। (प्रेट्र)

ओलंपिक को अन्य टूर्नामेंट की तरह ही लूंगा : जोकोविक

टोक्यो ओलंपिक डायरी ▶ बीजिंग ओलंपिक में नोवाक ने सर्बिया के लिए जीता था कांस्य

बेलग्रेड, आइएएनएस : ग्रैंडस्लैम और ओलंपिक की बात पर जोर देते हुए विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने कहा है कि यह सत्र उनका सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और वह रोजर फेडरर तथा राफेल नडाल के साथ सर्वकालिक महान टेनिस खिलाड़ी की रेस में शामिल होने को लेकर प्रेरित महसूस कर रहे हैं। जोकोविक ने बेलग्रेड स्थित उनके टेनिस कोर्ट पर याद दिलाया कि पिछले महीने सर्बिया की राष्ट्रीय टीम के साथ एटीपी कप का खिताब जीतने ने उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा, 'मेरे लिए सत्र की शुरुआत सर्वश्रेष्ठ तरीके से हुई है। मैं इसे अपने सर्वश्रेष्ठ सत्र में बदलने के लिए प्रेरित हूं। मैं जानता हूं कि यह ओलंपिक सत्र है, जिसका मतलब है कि कार्यक्रम थकान भरा होगा। विंबलडन के बाद आराम करने का कम समय होगा। मेरा लक्ष्य ग्रैंडस्लैम के साथ-साथ ओलंपिक खेल होंगे। मैंने बीजिंग 2008 ओलंपिक में सर्बिया के लिए कांस्य पदक जीता था। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मैं किसी अन्य टूर्नामेंट की तरह ही ओलंपिक में जाऊंगा। मुझे लगता है कि पदक जीतने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है।' इस दिग्गज खिलाड़ी नोवाक ने यह भी कहा कि इस सत्र में उनकी कोशिश अपनी फिटनेस पर और भी अधिक काम करने की रहेगी।

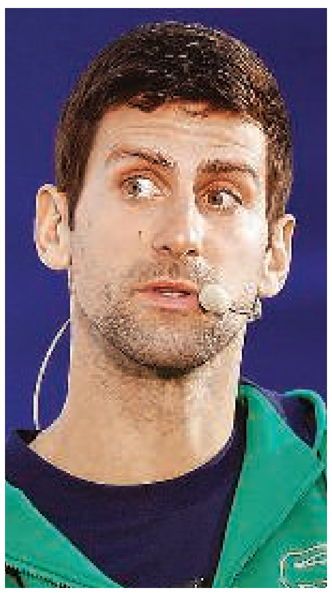

नोवाक जोकोविक। ट्विटर

ओलंपिक आयोजन पर जोखिम का कयास जल्दबाजी : डब्ल्यूएचओ

जिनेवा : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक शीर्ष अधिकारी का मानना है कि चीन में कोरोना वायरस के फैले संक्रमण के कारण टोक्यो ओलंपिक पर जोखिम मंडराने या आयोजन रद होने का कयास लगाना अभी जल्दबाजी है।

डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर पिछले महीने चिकित्सकीय आपातकाल की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों ने बार-बार दोहराया है कि 24 जुलाई से नौ अगस्त के दौरान प्रस्तावित इस आयोजन को लेकर उनके पास कोई आकस्मिक योजना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन कार्यक्रमों के निदेशक माइकल रियान ने डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन कहा, 'ओलंपिक अभी इस लिहाज से बहुत दूर है कि इसके आयोजन पर पड़ने वाले असर को लेकर कोई सुझाव दिया जाए। हम इस संबंध में निर्णय लेने के लिए वहां उपस्थित नहीं हैं।' डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ लगातार संपर्क में है। रियान ने कहा, 'हम उन्हें फैसला नहीं सुनाते हैं। हम जोखिम के आकलन में उनका सहयोग करते हैं। हम आने वाले सप्ताहों और महीनों में उनके साथ मिलकर काम करेंगे।' इस संक्रमण के कारण चीन में ओलंपिक क्वालीफायर समेत खेल के कई कार्यक्रम या तो रद अथवा निलंबित किए जा चुके हैं या फिर उनका आयोजन कहीं और किया गया। चीन ने पिछले ओलंपिक में 400 से अधिक खिलाड़ियों का दल भेजा था और उसने 26 स्वर्ण पदक सहित 70 पदक जीते थे।

सरनोबत बोलीं, सरकार ने हरसंभव मदद की

नई दिल्ली : एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला निशानेबाज राही सरनोबत का मानना है कि सरकार ने पिछले ओलंपिक खेलों की तुलना में आगामी टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के लिए भारतीय एथलीटों की मदद करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। सरनोबत ने कहा, 'सरकार के साथ संवाद बहुत अच्छा रहा। ओलंपिक की तैयारियों के लिए हमें जिस किसी भी चीज की जरूरत है, उन्होंने वे हर चीज हमें मुहैया कराई है। 2012 के लंदन ओलंपिक की तुलना में इस बार सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। यह मेरे करियर का दूसरा ओलंपिक होगा।' वह टोक्यो ओलंपिक में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेंगी और उन्होंने कहा कि भारत में खेल प्रतिभाओं की तलाश करने में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा।

ओलंपिक में ओसाका स्वर्ण पदक की दावेदार : पियर्स

नई दिल्ली, आइएएनएस : चार बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन मैरी पियर्स का मानना है कि जापान की स्टार महिला खिलाड़ी नाओमी ओसाका अगर टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतती हैं तो यह उनके लिए अच्छा होगा।

विश्व की 10वें नंबर की खिलाड़ी ओसाका उस समय सुर्खियों में आ गई थीं, जब उन्होंने 2018 में अमेरिका की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन का खिताब जीता था। ओसाका ने 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी खिताब अपने नाम किया था। पियर्स ने कहा, 'ओलंपिक एक ओपन टूर्नामेंट होगा। यह कहना मुश्किल है कि कौन इसमें स्वर्ण पदक जीतने जा रहे हैं क्योंकि इस समय काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको जापानी खिलाड़ियों को करीब से देखने की जरूरत है क्योंकि वे अपने देश में खेलने से प्रोत्साहित होंगे। ओसाका दावेदार हैं जो स्वर्ण पदक जीत सकती हैं। कितनी बार आपको अपने देश में ओलंपिक में खेलने का मौका मिलता है। कभी-कभी ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह अगर वह अपने देश में स्वर्ण जीतती हैं तो यह उनके लिए काफी अच्छा होगा।'

टोक्यो ओलंपिक के लिए हिंदी ट्विटर अकाउंट शुरू

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में खेल प्रशंसकों के लिए 2020 टोक्यो ओलंपिक की आयोजन समिति ने अपना हिंदी ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। ट्विटर अकाउंट 'टोक्यो2020 फोर इंडिया टोक्यो2020ही' सोमवार को शुरू किया गया जो भारत में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों टोक्यो 2020 का आधिकारिक अकाउंट है। इसके जरिये हिंदी बोलने वाले भारतीय प्रशंसकों को सारी जानकारी दी जाएगी। हिंदी भाषा में संदेश हालांकि रोमन इंग्लिश स्क्रिप्ट में ही दिखाई देंगे। एक ट्वीट के अनुसार, 'हम स्पेनिश, कोरियाई, हिंदी और फ्रेंच में नए टोक्यो2020 ट्विटर अकाउंट के शुरुआत की घोषणा करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम इस सफर पर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते।' इस नए हिंदी ट्विटर अकाउंट के 400 से ज्यादा फोलोअर्स हो चुके हैं। इसमें शीर्ष भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक 24 जुलाई से शुरू होगा।

पुजारा ने ग्लूस्टरशायर से अनुबंध किया

लंदन, प्रेट्र : भारत के टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा ने बुधवार को इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के पहले छह मैचों के लिए ग्लूस्टरशायर के साथ अनुबंध किया।

भारतीय टेस्ट टीम के प्रमुख खिलाड़ी पुजारा अपनी ठोस तकनीक के कारण बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ग्लूस्टरशायर के साथ उनका अनुबंध 12 अप्रैल से 22 मई तक के लिए है। पुजारा ने कहा, 'मैं इस सत्र में ग्लूस्टरशायर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलने से वास्तव में उत्साहित हूं। क्लब का शानदार क्रिकेट इतिहास है और यह इसका हिस्सा बनने और इसकी सफलता में योगदान देने का महत्वपूर्ण मौका है।' क्लब ने 32 वर्षीय पुजारा की लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता पर विचार किया। ग्लूस्टरशायर को उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। पुजारा ने कहा, 'मैं यह मौका देने के लिए क्लब का आभार व्यक्त करता हूं और ब्रिस्टल में अपनी टीम के साथियों से मिलने और वहां कुछ अच्छे स्कोर बनाने को लेकर उत्साहित हूं। मैंने वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में काउंटी क्रिकेट में खेलने का लुत्फ उठाया है और मैं इसे आगे जारी रखना चाहता हूं।' पुजारा इससे पहले काउंटी चैंपियनशिप में डर्बीशायर, यॉर्कशायर और नॉटिंघमशायर की तरफ से खेल चुके हैं। इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पदार्पण किया और टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 49.48 का है। प्रथम श्रेणी मैचों में उन्होंने 53.99 की औसत से रन बनाए हैं।

क्रिकेट डायरी

टी-20 लीग के लिए पाक में जुटेंगे शीर्ष अंतरराष्ट्रीय सितारे

कराची, एएफपी : पाकिस्तान में स्टार सुसज्जित पाकिस्तान सुपर लीग का पांचवां चरण गुरुवार से यहां शुरू होगा जिससे क्रिकेट प्रशंसकों को पहली बार घरेलू सरजमीं पर पूरी टी-20 लीग देखने का मौका मिलेगा। एक महीने तक चलने वाली इस लीग में छह टीमों 36 विदेशी खिलाड़ी भी भाग लेंगे। विदेशी खिलाड़ियों में शीर्ष अंतरराष्ट्रीय सितारे जैसे डेल स्टेन (दक्षिण अफ्रीका), शेन वॉटसन और क्रिस लिन (ऑस्ट्रेलिया), कॉर्लोस ब्रेथवेट (वेस्टइंडीज) और एलेक्स हेल्स और जेसन रॉय (इंग्लैंड) भी भाग लेंगे।

जिनेदिन जिदान के मुंह पर लगी किक

नई दिल्ली, जेएनएन : रीयल मैड्रिड और सेल्टा विगो के बीच सोमवार देर रात खेले गए स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के मैच में एक ऐसी घटना घटी जिसे देख सभी हैरान रह गए। दरअसल, विगो के जोसफ अइदू मैच के दौरान गेंद को अपनी तरफ लेने के चक्कर में अपना नियंत्रण खो बैठे और दुर्भागयपूर्ण तरीके से विपक्षी टीम यानी मैड्रिड के मैनेजर और महान खिलाड़ी रहे जिनेदिन जिदान के मुंह पर किक जड़ दी। अइदू विपक्षी टीम के टोनी क्रूस से गेंद बचाने के चक्कर में टेक्निकल एरिया में पहुंचे और दायें पैर से गेंद पर अपना नियंत्रण बनाने लगे, लेकिन वह यहां गेंद तो चूके ही साथ ही अपना नियंत्रण भी खो बैठे। यहां खड़े जिदान ने बड़ी फुर्ती से खुद को पीछे धकेला, लेकिन वह जोसफ की चपेट में आने से खुद को नहीं रोक सके। इस दौरान सेल्टा के खिलाड़ी का पैर सीधे जाकर जिनेदिन के मुंह पर जा लगा। जिदान को तुरंत डगआउट में ले जाया गया। जोसफ ने इस घटना के लिए हालांकि माफी मांग ली है। उन्होंने मैच के बाद कहा, 'मैच के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण भिड़ंत के लिए माफी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपके लिए मेरे दिल में इज्जत है।'

कुछ इस तरह मैच के दौरान जिदान के मुंह पर लगी जोसफ की किक। ट्विटर

विविध

राजस्थान में सरकारी अधिकारियों के साफा व माला पहनने पर रोक

जागरण संवाददाता, जयपुर

▶ अब जनप्रतिनिधि ही करेंगे सरकारी भवनों का उदघाटन और लोकार्पण

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अधिकारियों के किसी भी सरकारी समारोह में साफा और माला पहनने पर रोक लगा दी है। साथ ही यह भी तय किया है कि अधिकारी न तो सरकारी भवनों का उद्घाटन या लोकार्पण करेंगे और न ही शिलालेखों पर उनके नाम होंगे। उद्घाटन और लोकार्पण सिर्फ जनप्रतिनिधि ही करेंगे।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी कर सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं जिला कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश दिए हैं। सरकारी समारोहों में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) सेवा नियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्यों आया यह आदेश : दरअसल, राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं की शिकायत थी कि सरकारी कार्यक्रमों में विधायकों, पंचायत समिति प्रधान या सरपंच को नहीं बुलाया जाता है। इसमें अधिकारी मनमानी करते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोहों में सांसद से लेकर सरपंच तक को आमंत्रित किया जाए। जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टता और सम्मान भी दर्शाया जाए।

जेम्स बॉन्ड की फिल्मों जैसा काल्पनिक है सीबीआइ का आरोप पत्र : कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ सीबीआइ भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेंयू कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना व अन्य के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दाखिल किए गए आरोप पत्र पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआइ जांच पर सवाल उठाया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सह-आरोपित बनाए गए अधिवक्ता सुनील मित्तल पर कहा कि यह तो जेम्स बॉन्ड एवं मिशन इंपॉसिबल जैसे फिल्मों के मनगढ़ंत चरित्र जैसा है। आखिर क्यों इनके प्रति नरमी दिखाई जा रही है।

कोर्ट ने सीबीआइ से पूछा, आखिर अस्थाना का लाई-डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं कराया गया। न्यायाधीश ने तत्कालीन जांच अधिकारी अजय कुमार बस्सी को केस डायरी की व्याख्या करने के लिए 28 मार्च को होने वाली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने सुनील मित्तल के दामाद सोमेश्वर प्रसाद पर सीबीआइ से पूछा कि आखिर जो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने अपना फोन भी शेयर नहीं किया उसके साथ इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है। पिछले बुधवार को भी मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ की जांच पर नाखुशी जाहिर करते हुए कोर्ट ने सोमेश्वर मामले पर सीबीआइ से पूछा था कि आखिर मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाला स्वतंत्र घूम रहा है, जबकि जांच एजेंसी ने अपने ही डीसीपी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में 11 फरवरी को सीबीआइ मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें दुबई के कारोबारी मनोज प्रसाद को ही आरोपित बनाया गया है, जबकि राकेश अस्थाना, रॉ प्रमुख एसके गोयल व सीबीआइ के तत्कालीन डीएसपी देवेंद्र कुमार को निर्दोष बताया गया है।

यह है मामला : अक्टूबर 2018 में सीबीआइ ने राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने का केस दर्ज किया था। अस्थाना पर मनी लांड्रिंग मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से घूस लेने का आरोप था। हैदराबाद के सतीश बाबू सना की शिकायत के बाद अस्थाना, देवेंद्र, मनोज व सोमेश्वर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पांच बार रिश्वत ली गई थी। यह विवाद इतना बढ़ गया था कि अस्थाना ने तत्कालीन सीबीआइ डायरेक्टर आलोक वर्मा पर रिश्वत का आरोप लगाया था।

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में बैंककर्मी समेत आठ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा

▶ बुलंदशहर की पल्लाझाल पीएनबी शाखा में फर्जी व्यक्ति की आइडी से फर्म का खाता खोलकर किया गबन

▶ विद्युत निगम की ओर से सेक्टर-49 कोतवाली पुलिस में की गई थी शिकायत, एसआइटी कर रही थी जांच

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) को जारी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिये 1.66 करोड़ रुपये के गबन में पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक की बुलंदशहर जिले की जोखाबाद शाखा के डिप्टी मैनेजर अंकुर भास्कर और तीन बिजलीकर्मियों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 12.05 लाख रुपये,10.22 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बरामद हुआ है, जबकि लगभग कुल 78 लाख रुपये की संपत्ति सीज की है। एक फरार आरोपित की तलाश जारी है।

डीसीपी जोन-1 संकल्प शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर के अंकुर भास्कर, गाजियाबाद के खोड़ा निवासी सचिन व यतेंद्र चौधरी, बांदा निवासी जयसुभाष विश्वकर्मा, हरदोई निवासी ब्रजेश कुमार, राजस्थान के झुंझनू निवासी विशाल शर्मा व अलवर निवासी करन सिंह, बिहार के नालंदा निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित सचिन 15 वर्ष पहले गाजियाबाद के खोड़ा बिजलीघर में संविदा कर्मचारी था। वर्ष 2010 में उसने अपनी जगह जय सुभाष (संविदा कर्मी) को नौकरी पर रखवा दिया और खुद प्रॉपर्टी डीलिंग करने लगा। सचिन ने बिजली विभाग में मीटर लैब टेस्टिंग कर्मी करन सिंह व रिलाइवल डाटा कंपनीकर्मी मनीष के साथ मिलकर साजिश रची। योजना के तहत बुलंदशहर के जोखाबाद शाखा के पीएनबी कर्मचारी आनंद गौतम ने अपनी बैंक शाखा के डिप्टी मैनेजर अंकुर भाष्कर की मदद से पीएनबी की पल्लाझाल शाखा में रफीक शेख नाम की फर्जी (आइडी) से इशान इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अंडर ड्राफ्ट डिजाइनिंग (ईईईयूडीडी) नाम की फर्म का खाता खुलवाया।

फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले ब्रजेश कुमार ने इसमें मदद की। फर्म की चेक बुक जारी होने के बाद मनीष ने पीवीवीएनएल से बैंक को जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट के बंडल में से बड़ी धनराशि के डिमांड ड्राफ्ट निकालकर सचिन को देने शुरू कर दिए। आरोपित बुलंदशहर की शाखा से 300-400 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर उनकी गिनती पूरी कर देते थे। बड़ी रकम की धनराशि वाले डिमांड ड्राफ्ट से पीवीवीएनएल के स्टांप को मिटाकर उसमें बुलंदशहर के फर्जी खाते की स्टांप लगाकर नोएडा के सेक्टर-12 में जमा कर देते थे। आरोपितों ने बाद में विशाल शर्मा एवं यतेंद्र चौधरी को भी इसमें शामिल कर लिया। डीसीपी संकल्प शर्मा ने बताया कि बिजली विभाग 1 करोड़ 66 लाख के गबन का मुकदमा दर्ज कराया था।

'रंजीत सिन्हा के खिलाफ नई स्थिति रिपोर्ट दायर करें'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआइ को निर्देश दिया कि जांच एजेंसी के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा द्वारा 'आधिकारिक पद के दुरुपयोग' के आरोपों पर नई स्थिति रिपोर्ट चार सप्ताह के अंदर दायर करे। साथ ही शीर्ष अदालत ने कोयला घोटाले के 50 से अधिक मामलों में प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

जांच एजेंसी द्वारा समय मांगे जाने पर प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने उसे समय दे दिया। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट मीडिया में लीक होने के बाद 2012 में सामने आए मामलों में आरोप है कि सिन्हा ने सीबीआइ की जांच में बाधा डाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील एमएल शर्मा की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोयला घोटाला मामलों में प्रमुखता से लाभ उठाने वाले नवीन जिंदल के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए सीबीआइ को निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने सीबीआइ की तरफ से पेश वकील अमित आनंद तिवारी के बयानों का संज्ञान लिया कि जांच एजेंसी ने प्रक्रियाओं का पालन किया और आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि यह जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला मामले में सीबीआइ ने कम से कम 55 नियमित मामले दर्ज किए हैं और भागने की आशंका के चलते कुछ लोगों के पासपोर्ट भी जब्त किए हैं।

चीमा 30 जून तक एसपीपी बने रहेंगे

नई दिल्ली, एएनआइ : कोयला घोटाला मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा 30 जून तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से भी विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) बने रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनसे आग्रह किया था जिसे चीमा ने स्वीकार कर लिया। इससे पहले चीमा ने शीर्ष अदालत से कहा था कि वह सीबीआइ की ओर से तो एसपीपी बने रहना चाहते हैं लेकिन ईडी की ओर से इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। इसकी वजह उन्होंने ऐसे मामलों में विधि अधिकारियों की कमी को बताया था।

बच्चे को दादा-दादी से मिलने से रोकना सही नहीं : हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने मुंबई निवासी एक महिला को निर्देश दिया है कि वह अपने 10 वर्षीय बेटे को हफ्ते में एक बार अपने पूर्व सास-ससुर से मिलने दे या फिर जब भी वे दिल्ली से मुंबई आएं। अदालत ने टिप्पणी की कि बच्चे को अपने दादा-दादी से मिलने से रोकना सही नहीं है।

जस्टिस एसजे कथावल्ला और बीपी कोलाबावल्ला की खंडपीठ ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक महिला द्वारा पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। पुनर्विवाह कर चुकी इस महिला ने दावा किया था कि जब उसकी पहली शादी हुई थी तब सास-ससुर ने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। बच्चे (लड़का) का जन्म दिसंबर 2009 में हुआ था और उसके पिता की फरवरी, 2010 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला अपने माता-पिता के यहां चली गई थी और फिर पुनर्विवाह कर लिया था। हाई कोर्ट ने महिला का तर्क अस्वीकार करते हुए कहा कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, यह बच्चे को दादा-दादी से नहीं मिलने देने का आधार नहीं हो सकता।

एसआइटी सदस्यों पर एफआइआर दर्ज करने के आदेश पर रोक

जेएनएफ, जम्मू

▶ हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार को पक्ष रखने को कहा

▶ ट्रायल कोर्ट ने एसआइटी के छह सदस्यों पर एफआरआइ के दिए थे आदेश

बहुचर्चित कठुआ मामले की जांच करने वाली छह सदस्यीय स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम (एसआइटी) के छह सदस्यों पर एफआरआइ दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सिटी जज जम्मू ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को इस मामले की जांच करने वाली टीम के छह सदस्यों के खिलाफ फर्जी गवाह तैयार करने, गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखने और मानसिक व शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप में केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को एसआइटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस ताशी रबस्तान ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करते हुए पक्ष रखने का निर्देश दिया और तब तक एफआइआर में किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।

जनवरी 2018 को एक बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच की एसआइटी ने सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा को अपना गवाह बनाया था। लेकिन इन तीनों ने अक्टूबर 2019 में सिटी जज जम्मू की कोर्ट में एक आवेदन दायर कर एसआइटी के सदस्यों पूर्व एसएसपी क्राइम आरके जाला, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच पीरजादा नावेद, डीएसपी क्राइम ब्रांच शितांबरी शर्मा, नासिर हुसैन और उरफान वानी व केवल किशोर के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआइटी सदस्यों ने उन्हें कठुआ मामले के आरोपित सांझी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा के खिलाफ फर्जी बयान देने के लिए मजबूर किया था। इसके लिए एसआइटी के सदस्यों ने उन्हें गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में रखा और उन्हें शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। तीनों आवेदनकर्ताओं ने यह भी कहा था कि जांच अधिकारियों ने साजिश के तहत विशाल को इस केस में फंसाया और उसके खिलाफ फर्जी सुबूत तैयार करके धारा 164 के तहत जबरन बयान दर्ज कराए थे।

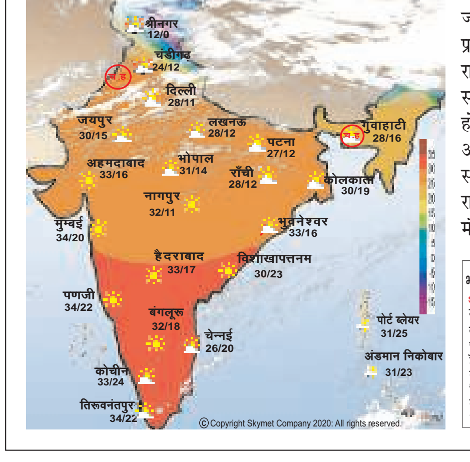

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में घने बादल छाये रहेंगे। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा और बर्फबारी होगी। पंजाब व हरियाणा में गरज और तेज हवाओं के साथ अनेक स्थानों पर वर्षा होगी। दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम आरामदायक होगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/18/आंबा	अहमदाबाद	34/16/सा
कोलकाता	30/18/व	बड़ौदा	36/14/सा
चेन्नई	31/22/सा	नागपुर	33/14/आंबा
हैदराबाद	32/17/आंबा	इन्दौर	32/16/व
बंगलूरू	31/18/व	राँची	29/12/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/21/आंबा	पटना	27/14/व
गुवाहाटी	29/17/सा	जमशेदपुर	30/14/सा
गंगटोक	15/10/सा	पुणे	34/19/सा

भारत के आखिरी वायसराय नियुक्त हुए लॉर्ड माउंटबेटन

आज ही के दिन 1935 में लॉर्ड माउंटबेटन को देश का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया था। वह 1948 तक भारत के अंतरिम गवर्नर जनरल रहे। उन्हें भारत का आखिरी अंग्रेज अफसर कहा जाता है।

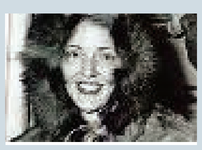

अंटार्कटिका पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनीं कैरोलिन

1935 में नॉर्वे की रहने वालीं कैरोलिन मिकलसन ने अंटार्कटिका में आज ही के दिन कदम रखा था। वहां पहुंचने वाली वह दुनिया की पहली महिला थीं। यहां कैरोलिन के नाम से एक पर्वत भी है जिसे माउंट कैरोलिन मिकलसन कहा जाता है।

अभिनय के अभिनव आयाम पेश करने वाले अन्नू कपूर

बेहतरीन अभिनय के साथ उत्कृष्ट कार्यक्रम प्रस्तोता के तौर पर लोगों के दिलों पर राज करने वाले अन्नू कपूर का जन्म 1956 में आज ही भोपाल में हुआ। उनका पूरा नाम अनिल कपूर है। अभिनय में रुचि होने के कारण नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश ले लिया। यहां एक नाटक के दौरान 23 साल की उम्र में 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का उनका निभाया किरदार श्याम बेनेगल को काफी पसंद आया। फिल्म मंडी से करियर शुरू किया। अभिनय के लिए फिल्मफेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले इस सितारे का सफर जारी है।

नौनिहालों को निहाल रहने देने में दुनिया विफल

दुनिया का हर देश अपने बच्चों के पुष्पित-पल्लवित होने को संरक्षित रखने में विफल रहा है। पारिस्थितिकी को खराब कर, जलवायु परिवर्तन और बाजारी प्रक्रियाओं के अति दोहन ने सभी देशों में बच्चों के स्वास्थ्य और उनके सुनहरे भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और अंतरराष्ट्रीय मेडिकल जर्नल लैंसेट द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो दशक में भले ही बच्चों की उतरजीविता, पोषण और शिक्षा में आमूलचूल सुधार हुए हों, लेकिन आज हर बच्चे का भविष्य मौजूद खतरों के चलते अनिश्चित बना हुआ है। भारत भी इस सूचकांक में औसत देशों के दर्जे में शामिल है।

ऐसे हुआ अध्ययन

180 देशों में किए गए इस अध्ययन में कई मानक शामिल किए गए। इनमें उतरजीविता, कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के साथ ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में टिकाऊपन और आय में अंतर शामिल रहे।

खराब देश

मध्य अफ्रीकी देश, चाड, सोमालिया, नाइजर, माली इस सूचकांक में सबसे नीचे शामिल हैं।

खतरनाक बाजारी प्रक्रियाएं

रिपोर्ट में फास्ट फूड और अत्यधिक शर्करा युक्त पेय पदार्थों से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक असर पर दुनिया को चेताया गया है। 1975 के मुकाबले दुनिया में मोटापे के शिकार बच्चों की संख्या में 11 गुना वृद्धि हो चुकी है। 1975 में इनकी संख्या 1.10 करोड़ अब 12.40 करोड़ पहुंच चुकी है।

बच्चों के लिए कौन से देश बेहतर

(रैंकिंग में)

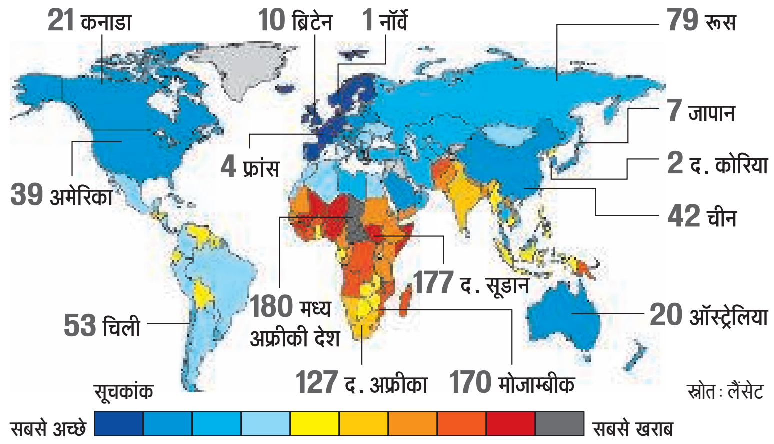

स्रोत: लैंसेट

शीर्ष पर ये देश

नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स, फ्रांस और आयरलैंड बच्चों के पुष्पित-पल्लवित होने के लिहाज से शीर्ष पर हैं।

कार्बन उत्सर्जन का उलटफेर

जब देशों का इस संबंध में प्रदर्शन प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के लिहाज से आंका गया तो बुरुंडी, चाड और सोमालिया सबसे अच्छे पाए गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब जैसे देश निचले दस देशों की सूची में रहे। इस स्थिति में नॉर्वे की रैंकिंग 156वीं, कोरिया 166, नीदरलैंड्स 160 रही। ये तीनों देश अपने 2030 के लक्ष्य की तुलना में प्रति व्यक्ति 210 फीसद ज्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं।

इधर-उधर की

कबूतर और कुत्ते की अनोखी दोस्ती हुई वायरल

न्यूयार्क, एजेंसी: आज आपको दोस्ती की ऐसी अनोखी तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल, न्यूयार्क की एक राहत संस्था मिआ फाउंडेशन ने वैलेंटाइन डे पर कुत्ते और कबूतर की दोस्ती की एक तस्वीर साझा की। जिस पर लाइक और शेयर का अंबार लग गया। तस्वीर में नजर आ रहे दोनों जीवों के नाम लुंडी (कुत्ता) और हर्मन (कबूतर) हैं। दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। लुंडी आठ महीने का है जो अपने पीछे के पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जबकि हर्मन अपनी ब्रेन इंजरी के चलते उड़ नहीं सकता। संस्था के मालिक श्यू रोजर्स ने बताया कि हर्मन को उन्होंने एक साल पहले एक कार डीलर के पार्किंग में देखा था। उसे बचाने में जुटे लोगों ने पाया कि वह उड़ नहीं सकता है। इसके बाद इलाज कराने के लिए वह उसे अपने साथ ले आए। इसी तरह लुंडी को इसके मालिक ने इसलिए उनके पास भेजा क्योंकि वह पिछले पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह इतना छोटा था कि उसे शर्ट की जेब में भी रखा जा सकता था। इसके बाद दोनों को उन्होंने अपने पास रख लिया। छह महीने बाद उन्हें इनकी दोस्ती का पता लगा जिसके बाद उन्होंने दोनों को साथ रखने का फैसला किया। अभी तक इन्हें 21 हजार लाइक मिल चुके हैं जबकि 45 हजार लोग इनकी तस्वीरें साझा कर चुके हैं।

बृहस्पति के वायुमंडल में बिखरा हो सकता है पानी

उम्मीद ▶ जूनो स्पेसक्राफ्ट से जुटाए गए आंकड़ों का किया अध्ययन

इस गैसीय ग्रह के वायुमंडल के 0.25 प्रतिशत अणुओं का निर्माण पानी की वजह से हुआ है

1995 में नासा के गैलीलियो मिशन में बृहस्पति में पानी की मौजूदगी की बात सामने आई थी। प्रतीकात्मक

लास एंजिलिस, प्रेट्र : नासा के जूनो मिशन द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर बताया है कि बृहस्पति के वायुमंडल में पानी बिखरा हो सकता है। इस ग्रह के भूमध्य रेखा के आसपास के वायुमंडल के लगभग 0.25 प्रतिशत अणुओं का निर्माण पानी की वजह से होता है। नासा ने बृहस्पति के अध्ययन के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को 2011 में लांच किया था। इस अध्ययन को नेचर एस्ट्रोनामी जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

सबसे पहले 1995 में नासा के गैलीलियो मिशन में इस ग्रह में पानी की मौजूदगी की बात सामने आई थी। इसके बाद से इस गैसीय ग्रह पर पानी की प्रचुरता मिलने का यह दूसरा अध्ययन किया गया है।

अमेरिका में नासा के जेट प्रोपेल्शन लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं के अनुसार सूर्य की तुलना में बृहस्पति बहुत शुष्क हो सकता है। यह तुलना तरल दृव्य नहीं बल्कि उसके घटकों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बृहस्पति संभवतः बनने वाला पहला ग्रह था और इसमें अधिकांश गैस और धूल शामिल है जो सूर्य में नहीं है। पहले के अध्ययनों में बताया गया था कि इस ग्रह के बनने के समय जो तरल पानी बचा था, उसे सोख लिया गया था। पानी की प्रचुरता से इस गैसीय ग्रह की आंतरिक संरचना और मौसम विज्ञान पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है।

अमेरिका में साउथवेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जूनो मिशन के प्रमुख अन्वेषक स्कॉट बोल्टन ने बताया कि जूनो की सबसे आश्चर्यजनक करने वाली खोज यह थी कि बृहस्पति में वायुमंडल अच्छी तरह से मिक्स नहीं है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इस पूरे ग्रह पर पानी इतना परिवर्तनशील हो सकता है।

माइक्रोवेव रेडियोमीटर से किया अध्ययन: नासा ने एक बयान में कहा कि जूनो के माइक्रोवेव रेडियोमीटर (एमडब्ल्यूआर) ने छह एंटीना का प्रयोग करके बृहस्पति का अध्ययन किया। इससे एक साथ कई गहराइयों पर वायुमंडलीय तापमान मापा जाता है। उन्होंने बताया कि एमडब्ल्यूआर से उत्सर्जित माइक्रोवेव विकिरण के कुछ तरंगदैर्घ्य को पानी अवशोषित करता है। बताया कि तापमान माप कर ग्रह के अंदर के वायुमंडल में पानी और अमोनिया की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। क्योंकि ये दोनों अणु माइक्रोवेव विकिरण को अवशोषित करते हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के लिए सबसे पहले बृहस्पति के भूमध्यरेखीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि वहां का वातावरण अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अच्छी तरह मिश्रित, गहराई पर भी दिखाई दिया। बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जूनो वैज्ञानिक चेंग ली ने कहा, 'हमने भूमध्य रेखा में पानी को पिछले मिशन गलैलियो की तुलना में अधिक स्पष्ट तरीके से मापा गया है।' शोधकर्ताओं ने कहा कि अभी इन परिणामों को और बेहतर तरीके से परखा जा रहा है।

राकेट को हल्का बना सकता है नया इंजन

प्रतीकात्मक

वांशिगटन, प्रेट्र: शोधकर्ताओं ने राकेट को हल्का और कम ईंधन की खपत वाला बनाने के लिए एक नए प्रकार के इंजन का कंप्यूटर माडल तैयार किया है। दावा है कि यह नया इंजन हल्का है और इसमें ईंधन भी कम लगता है। इस नए प्रकार के इंजन को घूर्णन विस्फोट इंजन कहा गया है।

फिजिकल रिव्यू ई पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, हालांकि यह इंजन अभी वास्तविक रॉकेट में प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि नया माडल इंजीनियरों को नए इंजनों को बेहतर और अधिक स्थिर बनाने की प्रेरणा देता है। इस अध्ययन के मुख्य लेखक जेम्स कोच ने कहा कि नए इंजन का मॉडल अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। हमारे पास इन इंजनों के बारे में बहुत सारा डाटा है, लेकिन यह नहीं पता की इसका करना क्या है। पारंपरिक रॉकेट इंजन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया- प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसमें ईंधन को जलाया जाता है जिससे गैस निकलती है जो जमीन पर बल लगाती है और इससे रॉकेट हवा में उठ जाता है। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नए इंजन का माडल एक ही केंद्र वाले कई सिलेंडरों पर बना है। इन सिलेंडरों के बीच की खाली जगह में ईंधन भरा होता है। जब ईंधन जलता है तो तुरंत पैदा हुई गर्मी एक शॉक वेव बनाती है। जिससे की इंजन की गैस काफी उच्च दबाव और तापमान के साथ निकलती है।

कठिन इलाकों पर काम करेगा सांप की तरह रेंगने वाला रोबोट

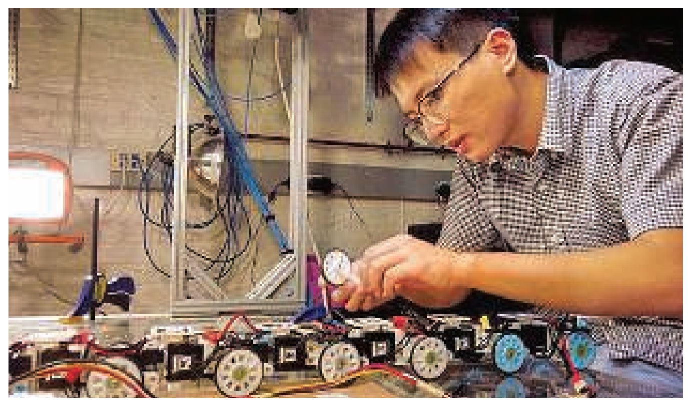

ऊबड़-खाबड़ जगहों पर चलने में माहिर है यह रोबोट। प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, प्रेट्र: सांप के रेंगने की कला से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सांप की तरह ही ऊंची जगहों पर चढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस तरह के रोबोट के जरिए खोज और बचाव कार्य बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से सफलतापूर्वक उबड़-खाबड़ इलाकों में काम किया जा सकता है।

रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस नामक पत्रिका में वर्णित यह रोबोट सांप की तरह ही अपने शरीर का 38 फीसद तक हिस्सा हवा में उठा देता है।

जांस होपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इस अध्ययन के सह लेखक चेन ली ने बताया कि हमें अपने उपकरणों को अधिक बेहतर बनाने के लिए अपने वातावरण में मौजूद जीवों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वे कठिन से कठिन हालात में जीवित रहने के लिए हमेशा संघर्षरत होते हैं। ली ने बताया कि पहले के अध्ययनों में सपाट सतह पर सांप जैसे रेंगने वाले रोबोट विकसित किए गए हैं, लेकिन यह नया रोबोट तीन आयामों पर चलने में माहिर है। यह पेड़ पर भी चढ़ सकता है।

ली और उनकी टीम ने सांप की चाल का अध्ययन करने के लिए आमतौर पर रेगिस्तान और पाइन ओक के जंगलों में रहने वाले सापों का अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान उन्होंने ऑब्जेक्ट की ऊंचाई और सतह के घर्षण को कई बार बदल कर देखा और समझा कि स्थितियां बदलने पर सांप किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। उन्होंने पाया कि सांप अपने शरीर को तीन हिस्सो में विभाजित करते हैं। उनका अगला और पिछला हिस्सा थोड़ा लचीला होता है जबकि बीच का हिस्सा कठोर बना रहता है। इस दौरान वे शरीर के तीनों हिस्सों का आकार घटाते-बढ़ाते रहते हैं। जब सांप की दूर की वस्तु पर पहुंचना चाहता है तो वह पहले अपना अगला हिस्सा बड़ा करता है और जब वहां पहुंचने वाला होता है तो वह हिस्सा छोटा और पीछे का बड़ा कर देता है। वहीं बीच का हिस्सा सामान ही रहता है।

फोटो न्यूज

पक्षी की तरह उड़ा मनुष्य

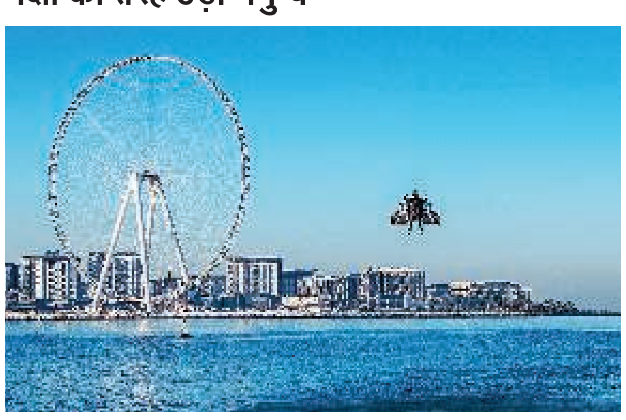

इंसान हमेशा से आसमान में पक्षियों की तरह स्वतंत्र रूप से उड़ने की कल्पना करता रहा है। इसे संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में जेटमैन के नाम से मशहूर फ्रांसीसी स्काई डाइवर विंस रेफेट ने साकार कर दिया है। दुबई एक्सपो-2020 में रेफट ने चार मिनी जेट इंजनों से संचालित कॉर्बन फाइबर विंग्स पहनकर 1800 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। जेट और विंग शरीर से नियंत्रित हो रहे थे। इस दौरान रेफट की औसत गति 240 किमी प्रति घंटे थी। हालांकि उनके जेट की अधिकतम क्षमता 4000 किमी प्रति घंटा है। खास बात यह भी है कि पहली बार इस तरह की कोई उड़ान ऊंचे प्लेटफॉर्म की बजाए सीधे जमीन से हुई है। एएफपी

लार से होगी अतिरिक्त वसा की जांच

शोध अनुसंधान

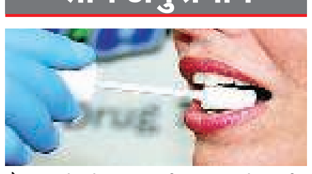

वैज्ञानिकों ने लार की जांच से शरीर में अतिरिक्त वसा का पता लगाने का तरीका ईजाद किया है। इसकी मदद से मोटापे से जुड़ी गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाना संभव हो सकेगा। शोधकर्ता पाउला मिडोरी कास्टेलो ने कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि चिकित्सकीय जांच के लिए लार को एक बेहतर विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाए। लार की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका सैंपल बिना दर्द और चीरफाड़ के आसानी से कई बार लिया जा सकता है।' बताया कि लार में मौजूद यूरिक एसिड का स्तर इस बात की जानकारी देता है कि शरीर में वसा की मात्रा कैसी है। यह किशोर उम्र में भी जानकारी देने में सक्षम है। यह जांच अहम है क्योंकि कम उम्र में वसा सही स्तर का पता नहीं चलने से आगे मोटापे से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। - प्रेट्र

त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले जीनोम का पता चला

त्वचा कैंसर की जांच की दिशा में वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने शरीर में आठ ऐसे नए जीनोम लोकेशन का पता लगाया है जो किसी व्यक्ति में त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। इस शोध में त्वचा कैंसर के प्रकार स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का कारण बनने वाले जीन की पहचान हुई है। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस त्वचा कैंसर से जुड़ा यह अब तक का सबसे बड़ा जेनेटिक अध्ययन है। इस अध्ययन में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के करीब 20,000 मरीजों और 6,80,000 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया था। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा त्वचा कैंसर के तीन प्रमुख कारण हैं। कुछ जेनेटिक कारण इन तीनों कैंसर में भूमिका निभाते हैं, जबकि कुछ जेनेटिक बदलाव केवल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की वजह बनते हैं। शोध के नतीजे इस कैंसर के इलाज का नया रास्ता खोजने में मददगार हो सकते हैं। - एएनआइ

स्क्रीन शॉट

कुछ बताया तो फराह मुझे डांटेंगी : रोहित शेट्टी

रोहित शेट्टी के लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर फराह खान जरूर कमेंट करती हैं। दरअसल, फराह और रोहित अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा दोनों साथ में एक ही फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। फराह ने रोहित की टीम ज्वॉइन की है। वह एक्शन कॉमेडी फिल्म पर काम कर रही हैं। यह फिल्म 'सत्ते पे सत्ता' की रीमेक होगी। जब रोहित से पूछा गया कि क्या उनकी अगली फिल्म रीमेक होगी, तब रोहित ने हंसते हुए कहा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो फराह मुझे डांटेंगी कि तुमने क्यों बता दिया। रोहित ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग चल रही है। इसकी घोषणा एक-डेढ़ महीने में हो जाएगी। रोहित शेट्टी की आगामी फिल्म 'सूर्यवंशी' होगी, जो उनके द्वारा रची गई पुलिस की दुनिया को 'सिंघम' और 'सिंबा' के बाद आगे लेकर जाएगी। 'गोलमाल' फ्रेंचाइजी की तरह रोहित अपनी इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को भी आगे लेकर जाएंगे। उनका कहना है कि 'सिंघम' के बाद पुलिस की हर फिल्म बड़ी होती चली गई है। 'सूर्यवंशी' अगर पसंद आई तो इसे आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल, रोहित 'सूर्यवंशी' के बाद 'सिंघम 3' लाने की तैयारी में हैं। 'गोलमाल 5' को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस फिल्म में वक्त है।

रितेश ने की छत्रपति शिवाजी पर फिल्म बनाने की घोषणा

हिंदी सिनेमा में इन दिनों ऐतिहासिक फिल्मों के निर्माण में फिल्ममेकर खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। हाल की बात करें तो 'मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ झांसी', 'केसरी', 'तान्हाजी : द अनसंग वॉरियर' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं। इसके बाद करण जौहर 'तख्त' व 'पृथ्वीराज चौहान' बना रहे हैं। उसके बाद द्रौपदी के नजरिए से महाभारत का निर्माण होने वाला है। कश्मीर की हिंदू रानी कोटा रानी पर भी फिल्म बनाने की तैयारी है। रितेश देशमुख भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाने की तैयारी में थे। उसके लिए उन्होंने गहन रिसर्च करने की बात कही थी। आखिरकार, उन्होंने बुधवार को शिवाजी की 390वीं जयंती पर इसकी घोषणा कर दी है। फिल्म के लिए उन्होंने 'सैराट' के निर्देशक नागराज मंजुले और संगीतकार अजय-अतुल से हाथ मिलाया है। यह तिकड़ी मिलकर शिवाजी की ट्रायोलॉजी का निर्माण करेगी। फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा। इसे मराठी और हिंदी में बनाया जाएगा। छत्रपति की भूमिका कौन निभाएगा, इस बारे में अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। मराठा साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज को जाता है।

अपनी दूसरी किताब ला रहे हैं संजय खान

'द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ' के बाद संजय खान अपनी दूसरी किताब लॉन्च करने की तैयारी में हैं। 'अस्सलामुअलैकुम वतन' शीर्षक वाली यह किताब देश की संस्कृति और वास्तुकला की विरासत के निर्माण में मुसलमानों की भूमिका को बयां करेगी। किताब में कुछ विवादास्पद सवालों का जवाब देने की भी कोशिश की गई है। संजय ने पुस्तक के लगभग हर पृष्ठ (जिसमें 10 अध्याय हैं) में दृढ़तापूर्वक यह कहा है कि वह 'खुद को पहले भारतीय, फिर किसी धर्म का व्यक्ति मानते हैं।' इस पुस्तक के माध्यम से खान सुझाव देते हैं कि यदि संभव हो तो भारत सरकार सभी नागरिकों को भारतीय के तौर पर संबोधित करने की पहल करे और धर्म से पहले भारतीय जोड़े। मसलन- भारतीय मुस्लिम, भारतीय हिंदू, भारतीय ईसाई, भारतीय सिख। यह हर नागरिक को हर चीज से पहले भारतीय होने का एहसास दिलाएगा।'

शायर साहिर लुधियानवी पर आएगा वेब शो

पिछले काफी अर्से से खबरें आ रही हैं कि संजय लीला भंसाली मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की तैयारी में हैं। अब खबर है कि लेखक अक्षय मनवानी साहिर लुधियानवी पर छह हिस्सों वाली बायोग्राफिकल सीरीज पर काम कर रहे हैं। यह सीरीज उनकी अपनी किताब 'साहिर लुधियानवी : द पीपुल्स पोयट' पर आधारित होगी। इसमें उनके बचपन से लेकर मशहूर गीतकार बनने के सफर को दिखाया जाएगा। 'प्यासा', 'नया दौर' और 'फिर सुबह होगी' जैसी क्लासिक फिल्मों में उनके लिखे गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। साहिर का जन्म 6 मार्च, 1921 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। बचपन में साहिर की जिंदगी संघर्ष में बीती। पिता की दूसरी शादी के बाद साहिर ने अपनी मां के साथ रहने का निर्णय लिया। 1951 में गुरुदत्त की पहली निर्देशित फिल्म 'बाजी' में उनके गीत 'तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर' ने साहिर की तकदीर बना दी। उन्होंने फिल्मी दुनिया को कई अनमोल गीत दिए।

डैनी के बेटे करते दिखेंगे जबर्दस्त एक्शन

अभिनेता डैनी डेन्जोंगपा के बेटे रिन्जिंग फिल्म 'स्क्वायड' से अभिनय में कदम रखने की तैयारी में हैं। वह फिल्म में धमाकेदार एक्शन करते नजर आएंगे। नीलेश सहाय द्वारा निर्देशित फिल्म में कई भयंकर विस्फोट होते दिखाई देंगे। नीलेश के मुताबिक, रिन्जिंग के इंट्रोडक्शन सीन में 60 विस्फोट होंगे, जिनके बीच से वह गुजरते दिखेंगे। सौ स्टंटमेन ने इस सीन को अंजाम दिया। नीलेश के मुताबिक, इस सीन के लिए उन्होंने हफ्ते भर तैयारी की, ताकि किसी गलती की संभावना न रहे। उन्होंने एक्शन करने को लेकर रिन्जिंग के नर्वस होने की बात से इन्कार किया। नीलेश के मुताबिक, रिजिंग एक्शन के लिए ही बने हैं। वे नहीं, मैं नर्वस था। उन्होंने निडर होकर सभी सीन किए हैं। रिन्जिंग कहते हैं, वे अविस्मरणीय पल थे। आठ कैमरे लगे हुए थे और मैं विस्फोटों के बीच से गुजर रहा था। ये विस्फोट तीन मिनट तक बिना रुके होते रहते हैं। फिल्म में रिजिंग के अपोजिट अनीता राज की भतीजी मालविका राज होंगी।

रूढ़िवादी सोच को तोड़ेगी 'पिन्नी' : ताहिरा कश्यप

कैंसर से जंग लड़ने वाली ताहिरा कश्यप शॉर्ट फिल्म 'टॉफी' का निर्देशन कर चुकी हैं। प्रख्यात अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा ने अब सात शॉर्ट फिल्मों को लेकर बनी फिल्म 'जिदंगी इन शॉर्ट' में 'पिन्नी' नामक कहानी का निर्देशन किया है। उसमें नीना गुप्ता केंद्रीय भूमिका में हैं। ताहिरा कहती हैं, 'मेरी कहानी मेरी सास से प्रेरित है। वह सबके लिए पिन्नी बनाती हैं। वह पूरे परिवार को जोड़कर रखती हैं। उनके जैसा हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाला इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। पंजाबी मां होने के कारण उन्हें सबको खाना खिलाना बेहद पसंद है। हमें भी पिन्नी वही बनाकर भेजती हैं। वहां से मैंने किरदार को काल्पनिक तौर पर गढ़ा। किरदार की मिठास मेरी सास से आती है। आमतौर पर लोग चाहते हैं कि घरेलू महिला खाना बनाने तक सीमित रहे। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह सिर्फ धारावाहिक ही देखेंगी। मेरी कहानी इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ना चाहती है। कहानी के अंत में एक ट्विस्ट भी है। कहानी सिंपल है, लेकिन वह कई स्तर पर अपने नजरिए को रखती है। अच्छी बात यह है कि हिंदी सिनेमा में अब साठ पार महिलाओं की कहानियों को भी बनाया जा रहा है।